RNI No. DELHIN/2012/48773

₹50

मासिक, विशेषांक 2019

वर्ष 8, अंक 7

फेम इंडिया

सोच बदलें, समाज बदलेगा

50

असरदार ब्यूरोक्रेट्स

एशिया पोस्ट - फेम इंडिया सर्वे

IFFCO
पूर्णतः सहकारी स्वामित्व
Wholly owned by Cooperatives

1967 से भारतीय किसान के सच्चे साथी

मिट्टी की जान. किसान की शान.

INDIAN FARMERS FERTILISER COOPERATIVE LIMITED
IFFCO Sadan, C-1 District Centre, Saket Place, New Delhi - 110017, INDIA
Phones : 91-11-26510001, 91-11-42592626. Website : www.iffco.coop

फेम इंडिया
www.fameindia.co
वर्ष 8, अंक 7, विशेषांक 2019

मैनेजिंग डायरेक्टर / एडिटर इन चीफ – राज श्री
चीफ एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर – उमाशंकर सोंथालिया
चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर – शंकर सोंथालिया
मैनेजिंग एडिटर / एक्जीक्यूटिव डॉयरेक्टर – श्वेता श्री
एक्जीक्यूटिव डॉयरेक्टर – राघवेश अस्थाना

एसोसिएट एडिटर – धीरज कुमार
नेशनल ब्यूरो हेड – दीपाली श्रीवास्तव
रेजिडेंट एडिटर – डॉ विष्णु रजगढिया
आर्ट डायरेक्टर – स्वर्ण लता

एडिटोरियल टीम –
शत्रुघ्न प्रसाद
सुधा उपाध्याय
आनंद वर्मा
हेमंत सिंह
मिथिलेश पाठक
अंजू राजपूत
मनजीत सिंह
नंदन झा
पंकज चौधरी

सेल्स – नीतू चौधरी
मार्केटिंग – पंकज तिवारी
सर्कुलेशन – प्रवीण मिश्रा

वेब टीम – रश्मि सिंह

फोटो रिसर्चर – राजेश वर्मा

लीगल एडवाइजर – शरद चंद्र झा

(स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक राजश्री द्वारा ज्योति प्रिंटर्स, ई -94, सेक्टर 6, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर से मुद्रित एवं ए -533, जीडी कालोनी, मयूर विहार फेज -3, दिल्ली से प्रकाशित, संपादक - राज श्री)

संपादकीय एवं मार्केटिंग ऑफिस
फेम इंडिया पब्लिकेशन प्रा.लि।
762,ब्लाक-एफ 8, सेक्टर-50, नोएडा 201304 (उ.प्र.)
फोन नं. - +91-7004450124

ई मेल : info@fameindia.co

RNI No. DELHIN/2012/48773

संपादकीय

यूं ही नहीं बनता कोई असरदार ब्यूरोक्रेट्स

वैसे तो देश के विकास में ग्राम विकास अधिकारी से लेकर देश के केंद्रीय सचिव तक सबकी भूमिकाएं अहम होती हैं, लेकिन आला अफसर विकास संबंधित योजनाओं का जो खाका तैयार करते हैं, देश या प्रदेश की पूरी मशीनरी उनको पूरा करने में तन-मन से जुटती है तभी कोई सुधार सही शक्ल लेता है। इसमें आईएएस अधिकारियों की भूमिका बेहद महत्त्वपूर्ण होती है। इसकी वजह भी साफ है। किसी भी आईएएस अधिकारी की चयन प्रक्रिया से लेकर इन्हें मिलने वाली ट्रेनिंग देश में सर्वोच्च स्तर की होती है। नये अधिकारी को जब पहली नियुक्ति मिलती है तो उसे एसडीएम बना कर किसी तहसील या अनुमंडल की बागडोर सौंपी जाती है। इस सबसे निचले पायदान से वह आम आदमी की समस्याओं से रूबरू होना शुरू होता है और उनका हल खोजता है। उसका यह अनुभव समय के साथ बढ़ता जाता है। अनुभवी ब्यूरोक्रेट्स विकास योजनाओं का खाका बनाने में खास रोल अदा करते हैं। चूंकि वे अपनी तैनाती के दौरान प्रदेश और विभागों के करीब-करीब हर हिस्से की प्राकृतिक संपदाओं, कृषि, सड़क, बिजली, वित्त और मानव पूंजी से भली भांति परिचित हो चुके होते हैं, इसलिए समस्याओं का निदान और विकास के नये पायदान गढ़ने के सूत्र उनके पास होते हैं। सत्ता के शिखर पर बैठे लोग इन्हीं सूत्रों के सहारे जनता के सपनों को साकार करते हैं। सत्तारूढ़ सरकार जनता से विकास के जो वायदे करती है इन्हें अमली जामा ये ब्यूरोक्रेट्स ही पहनाते हैं। इन्हें पता होता है कि विभाग के पास या राज्य के कितने संसाधन हैं और किस हिस्से की क्या जरूरत है। उसी के अनुरूप ये अधिकारी योजनाएं बनाते हैं। इससे ही विकास को गति मिलती है। यह अलग बात है कि इसका श्रेय इन्हें कम ही मिलता है। जब ब्यूरोक्रेट्स किसी योजना का प्रारूप तैयार करता है तो उसके समक्ष विभाग, क्षेत्र, राज्य या देश का विस्तृत दायरा होता है और होती है वहां की प्राथमिकताएं। किसी भी योजना की सफलता या विफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह आम लोगों से कितनी और किस तरह जुड़ी है। उस योजना का लाभ जनता को किस तरह मिलने वाला है। 'असरदार ब्यूरोक्रेट्स' के फेम इंडिया के इस अंक में हम उनके विकास और प्रगतिशीलता में दिये गये योगदान को सामने लाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

राजश्री

info@fameindia.co

राष्ट्र निर्माण में 'सरदार' की असरदार फ़ौज- नौकरशाही

राणा यशवंत
वरिष्ठ पत्रकार
(फाउंडर - द फ्रंट "जो बोलेंगे वो बदलेगा")
(thefront.in)

10 अक्तूबर 1949 को संविधान सभा की बैठक चल रही थी । इस बैठक में सभा के वरिष्ठ सदस्य और डिप्टी स्पीकर अनंत स्वामी आयंगर प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के बारे में अपनी राय रख रहे थे। उनकी बात से गृह मंत्री सरदार पटेल इतने आहत हुए कि इन्होंने कहा-" आयंगर साहब के विचार से ऐसा लगता है कि प्रशासनिक अधिकारी हमारे देश के दुश्मन हैं, हमें जिन लोगों से काम लेना है उनके प्रति हम दुश्मन-सा भाव रखते हैं. हमारा ऐसा बर्ताव देश की सेवा के बजाय कुसेवा होगी। उस बैठक में भारतीय प्रशानिक सेवा और अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर जो भाषण सरदार पटेल ने दिया था, उसको नौकरशाही के अधिकारों के लिहाज से मैग्नाकार्टा कहा जा सकता है। यह तब था जब समूची कांग्रेस, यहां तक की प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरु भी नौकरशाही के खिलाफ थे. सरदार पटेल नौकरशाही के पक्ष में चट्टान की तरह खड़ा रहे. इन्होंने कहा - "'यदि हम सक्षम अखिल भारतीय सेवा चाहते हैं तो, मैं आपको सलाह दूंगा कि सेवा अधिकारियों को मुख्यरूप से अपने विचार व्यक्त करने की आजादी होनी चाहिए। यदि आप प्रधानमंत्री हैं, तो आपका दायित्व बनता है कि आप अपने सचिव या मुख्य सचिव या अपने अधीनस्थों को किसी प्रकार के भय या लालच के बिना अपना मत व्यक्त करने का उचित वातावरण प्रदान करेंगे। किंतु आजकल तो मै इस प्रकार माहौल देख रहा हूं कि कुछेक प्रांत में सेवा अधिकारियों को कहा जाता है, 'नहीं, आप तो सेवा अधिकारी हैं, आपको हमारे निर्देशों को केवल अनुपालन करना है । इस प्रकार तो संघीय ढांचा रहेगा नहीं, संयुक्त भारत टिकेगा नहीं, आपके पास मुक्त मन से अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता वाली अखिल भारतीय सेवा यदि नहीं है और इन्हें सुरक्षा का भाव भी नहीं है, तो संघीय ढांचा नहीं रहेगा" ।

सरदार पटेल के उस भाषण को आज 70 साल हो गए। इन्होंने कितनी गहरी और मायने वाली बात कही थी, इसको आज के संदर्भ में भी रखकर समझा जा सकता है। आज भी उनकी बातें उतनी ही प्रासंगिक है। प्रशासनिक अधिकारियों की क्षमता पर सरदार पटेल को पूरा भरोसा था और वे यह मानते थे कि संविधान के अनुसार देश को चलना है तो फिर देश को समर्थ-सक्षम और निर्भीक अधिकारियों से लैस होना पड़ेगा। एक बार जब सरदार की तबीयत खराब थी, गृह सचिव एचवीआर आयंगर ने कुछ सुझावों की फाइल भेजी। उन सुझावों पर पटेल के निजी सचिव विद्या शंकर ने पहले टिप्पणी डाल दी और फिर उसके बारे में बीमार चल रहे सरदार को बता दिया। हामी भी मिल गई। लेकिन टिप्पणियां सुझावों के उलट थीं। आयंगर, पटेल के पा पहुंचे और अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी। इन्होंने अपने सुझावों के पक्ष में मजबूत तर्क भी रखे। सरदार ने अपनी पुरानी टिप्पणी रद्द करते हुए, गृह सचिव के सुझावों को मान लिया । आज देश में सिविल सेवा का जो ढांचा है, उसको खड़ा और मजबूत करने में सरदार की भूमिका बहुत बड़ी रही।

लेकिन एक सच यह भी है कि प्रशासनिक अधिकारियों से जिस तरह की सेवा, समर्पण और ईमानदारी की अपेक्षा देश को रही, वो पूरी नहीं हुई । जनता से उनका जुड़ाव और व्यवस्था को जनोपकारी बनाने को लेकर प्रतिबद्दता- दोनों में कमी आज भी महसूस की जाती है. इसका सबसे बड़ा कारण देश के राजनीतिक तंत्र के भी भ्रष्ट और अराजक होने को माना जाता है।

वैसे सच यह भी है कि भारत अगर उत्तरोत्तर संपन्न, सफल, सबल और सक्षम राष्ट्र बनता गया तो इसमें प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका सबसे बड़ी है। उनकी योग्यता, लगन, समर्पण और ईमानदारी के कारण ही ना सिर्फ समाज में व्यवस्था बहाल रहती है, बल्कि कुशल नीति-निर्माण से लेकर उनके सफल कार्यान्वियन तक का काम हो पाता है।

देश के हजारों आईएएस अधिकारियों के बीच सर्वश्रेष्ठ अधिकारियों के चुनना फेम इंडिया के लिए स्वयं में बेहद चुनौतीपूर्ण काम रहा। देश-निर्माण में लगे वैसे योग्य और ईमानदार अधिकारियों की बड़ी संख्या है, जो श्रेष्ठ आईएएस होने की हर शर्त पूरा करते हैं और यह देश के लिए गर्व की बात है। लेकिन, हर चयन-विधि की तरह हमारी भी एक प्रक्रिया रही. इसी प्रक्रिया से जो नाम आए, इन्हें पत्रिका में जगह दी जा रही है. सभी को शुभकामनाएं।

विकास को दिशा देते हाथ

ceo@fameindia.co

वैसे तो ब्यूरोक्रेसी का देश के विकास में सबसे अहम योगदान है, परन्तु आजकल ये आम धारणा बना दी गयी है कि ब्यूरोक्रेट्स करते ही क्या हैं? अक्सर नौकरशाही को लालफीताशाही से जोड़ कर इसे नकारात्मक रूप में पेश किया जाता है, जबकि वास्तविकता ये है कि देश के सर्वांगीन विकास से लेकर किसी भी योजना के क्रियान्वयन तक में इनकी भूमिका सबसे अहम होती है। सर्वोच्च ब्यूरोक्रैसी के प्रतीक आईएएस अधिकारियों का समाज और देश के निर्माण में बेहद महत्त्वपूर्ण योगदान है, परन्तु आम तौर पर उनके बेहतरीन कार्य का श्रेय सत्ताधारियों को मिल जाता है। हर कोई उनसे अपना काम साधने की फिराक में तो रहता है, किन्तु तारीफ राजनेता के हिस्से आती है।

एक जिम्मेदार व सकारात्मक मीडिया होने के नाते फेम इंडिया ने इस बार देश निर्माण में अपनी बेहतर भूमिका निभा रहे हजारों आईएएस अधिकारियों को श्रेय देने का निर्णय किया है। वर्त्तमान में देश भर में 5000 से भी ज्यादा आईएएस अधिकारी कार्यरत हैं। इनमें से सिर्फ 50 को असरदार के तौर पर चुनना एक बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य था।

सर्वप्रथम फेम इंडिया मैगजीन ने सर्वे एजेंसी एशिया पोस्ट के साथ मिलकर 1984 से 2003 तक के ब्यूरोक्रैट्स को इस सर्वे में शामिल किया। विभिन्न स्रोतों और मीडिया रिपोर्टों के आधार पर लगभग 300 अधिकारियों के नामों का चयन किया गया जो अपनी उत्कृष्टता के कारण विशिष्ट स्थान रखते हैं। ये इतना कठिन था कि सर्वश्रेष्ठ चुनना लगभग असंभव था। हमने उन सभी अधिकारियों को स्टेकहोल्ड सर्वे के आधार पर 50 कैटेगरियों में बांटा और हर कैटगरी से एक प्रमुख असरदार ब्यूरोक्रैट्स को फेम इंडिया के अंक में प्रकाशित कर रहे हैं। सर्वे में आये सभी प्रमुख 300 असरदार ब्यूरोक्रेट्स की प्रोफाइल fameindia.co पर और उनके प्रोफाइल वीडियो thefront.in पर जल्दी ही उपलब्ध करवाने की योजना है ।

एशिया पोस्ट सर्वे के मानदंड हैं - शानदार गवर्नेंस, दूरदर्शिता, उत्कृष्ट सोच, जवाबदेह कार्यशैली, अहम फैसले लेने की त्वरित क्षमता, गंभीरता और व्यवहार कुशलता।

असरदार ब्यूरोक्रेट्स

07 **अजय कुमार भल्ला**
प्रभावशाली
कुशल रणनीतिकार है प्रभावशाली अजय कुमार भल्ला

09 **डॉ. अजय कुमार**
उत्कृष्ट
कई पुरस्कारों से सम्मानित ब्यूरोक्रट है डॉ. अजय कुमार

12 **अंशु प्रकाश**
दूरदर्शी
दूरगामी योजना बनाने में माहिर हैं अंशु प्रकाश

20 **राजेश खुल्लर**
कामयाब
हरियाणा में बनाई पारदर्शी व्यवस्था राजेश खुल्लर ने

24 **शुभ्रा सिंह**
शक्ति
नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की शुरुआत की रणनीतिकार रही है शुभ्रा सिंह

28 **जितेंद्र नारायण**
जज्बा
भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ बेहद जज्बाती अधिकारी हैं जितेंद्र नारायण

37 **संजय लोहिया**
शोहरत
उत्तर पूर्व में खासी शोहरत प्राप्त आईएएस है संजय लोहिया

41 **राजीव टोपनो**
विलक्षण
विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं प्रधानमंत्री के निजी सचिव राजीव टोपनो

39 **अश्विनी सतीश भिड़े**
उड़ान
सफलता की ऊंचाइयों पर उड़ना भरने वाली अधिकारी हैं अश्विनी सतीश भिड़े

52 **संजीव वर्मा**
माहिर
चुनौतीपूर्ण परिस्थिति को संभालने में माहिर हैं जम्मू-कश्मीर के संजीव वर्मा

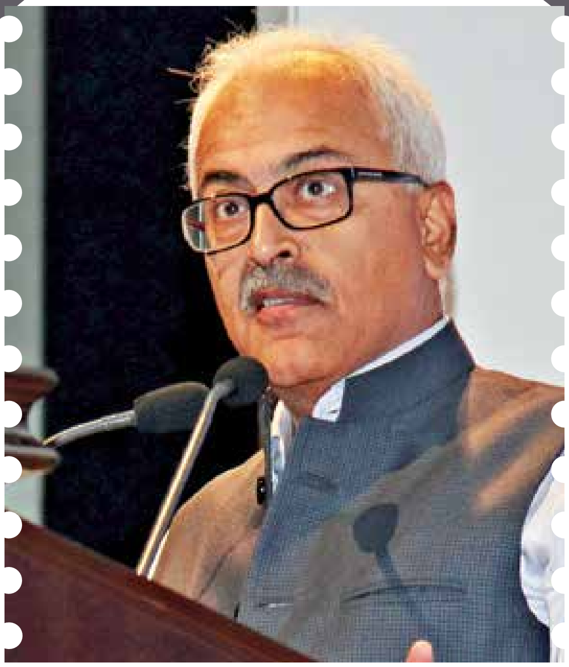

कुशल रणनीतिकार हैं प्रभावशाली अजय कुमार भल्ला

प्रभावशाली
★★★★★

देश के वर्तमान गृह सचिव वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी अजय कुमार भल्ला असम मेघालय कैडर के 1984 बैच के आईएएस है। इनकी गिनती देश के बेहद काबिल और अनुभवी अधिकारियों में होती है। जानकारों की मानें तो अजय भल्ला को गृह मंत्रालय के लिए स्वयं गृहमंत्री अमित शाह ने चुना है क्योंकि इन्हें एक कुशल रणनीतिकार और दूरदर्शी ब्यूरोक्रेट माना जाता है। ये अगले 2 वर्षों के लिए गृह सचिव नियुक्त किए गए हैं।

अजय कुमार भल्ला को गृह मंत्रालय का दायित्व उस समय दिया गया है जब कश्मीर को लेकर वर्त्तमान सरकार एक बड़ा फैसला ले चुकी है और वहां हालात सामान्य करना सबसे बड़ी चुनौती है। बात इतनी ही नहीं है। सरकार की प्राथमिकता तो नक्सलवाद और पूर्वोत्तर से उग्रवाद को खत्म करने की भी है। बताया जा रहा है कि चूंकि असम में अजय कुमार भल्ला ने आंतरिक अस्थिरता पर लगाम कसने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए सरकार को इनके लंबे प्रशासनिक अनुभव का अच्छा लाभ मिलेगा। देश की आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों से मुकाबले के लिए इनका चयन भी इनकी काबिलियत की व्याख्या है।

इससे पहले ये देश के ऊर्जा सचिव के तौर पर नियुक्त थे, जहां इन्होंने उत्कृष्ट सोच और जवाबदेह कार्यशैली का बेहतरीन प्रदर्शन किया, सौभाग्य योजना का पुरे देश में सफलतापूर्वक क्रियान्वयन इनकी शानदार गवर्नेंस क्षमता को साबित करता है। ऊर्जा मंत्रालय से पहले इनके पास फॉरेन ट्रेड के डीजी का ओहदा था और इस भूमिका में भी इन्होंने सरकार के लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल किया। सज्जन व्यक्ति की छवि वाले अजय कुमार भल्ला दिल्ली के निवासी हैं। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की क्वीन्स लैंड यूनिवर्सिटी से एमबीए किया है। इन्हें बेहद मिलनसार और बेहतरीन इंसान माना जाता हैं। कहा जाता है कि ये अपने फैसलों में इंसानियत को सबसे ऊपर रखते हैं।

अजय कुमार भल्ला भारत सरकार के कोयला मंत्रालय में बतौर ज्वाइंट सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी काम कर चुके हैं। ये भारत सरकार के शिपिंग विभाग के निदेशक (बंदरगाह) भी रहे हैं। असम- मेघालय कैडर में महत्त्वपूर्ण विभागों में कार्य का इन्हें एक लंबा अनुभव रहा हैं।

अन्य प्रमुख नाम:

ए आर सिहाग
ए बी पी पांडेय
आनंद कुमार
सी चंद्रमौली
दीपक कुमार

(इस श्रेणी के सभी प्रमुख ब्यूरोक्रेटस की पूरी प्रोफाइल fameindia.co पर पब्लिश की जा रही है।)

फेम इंडिया मैगज़ीन- एशिया पोस्ट के प्रमुख मापदंड:

दूरदर्शिता - ✓
उत्कृष्ट सोच - ✓
जवाबदेह - ✓
गंभीरता - ✓
शानदार गवर्नेंस - ✓
व्यवहार कुशलता - ✓
फैसला लेने की क्षमता - ✓

इन सात मुख्य बिंदुओं पर किये गये वार्षिक सर्वे 'असरदार ब्यूरोक्रेट्स -2019' में अजय कुमार भल्ला प्रमुख स्थान पर हैं।

सर्वे स्रोत :- विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की राय पर आधारित

भारतीय अर्थव्यवस्था में बड़े बदलाव के वाहक हैं राजीव कुमार

प्रेरणादायक

जुलाई 2019 में भारत सरकार के सबसे महत्त्वपूर्ण माने जाने वाले वित्त मंत्रालय की कमान संभालने वाले राजीव कुमार की गिनती तेज-तर्रार व सुलझे हुए रणनीतिकारों में होती है। 1984 बैच के झारखण्ड कैडर के इन आईएएस अधिकारी की जिम्मेदारी सरकार की आर्थिक नीतियां डिजाइन करने, इन्हें सरकार से मंजूर करवाने और उनके अनुपालन को सुनिश्चित करने की है। वित्त सचिव यानी वित्त मंत्रालय के सभी पांच विभागों- आर्थिक मामले, राजस्व, खर्च, वित्तीय सेवाएं और निवेश व सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन (डीआईपीएएम) के इंचार्ज।

उत्तर प्रदेश के मूल निवासी राजीव कुमार ने प्राणी विज्ञान से बीएससी कर लॉ की डिग्री हासिल की है। ये मैनेजेंट में डिप्लोमा होल्डर हैं और इन्होंने पब्लिक पॉलिसी में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है। अपनी लगभग 34 साल की सेवा में ये कई महत्त्वपूर्ण विभाग संभाल चुके हैं। ये कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में विशेष सचिव और संस्थापना अधिकारी के तौर पर काम कर चुके हैं। वनवासी कल्याण मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी रहने के अलावे ये दिल्ली में झारखंड भवन के रेजिडेंट कमिश्नर, और एडिशनल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। इन्होंने अपने गृह राज्य झारखंड में प्रशासनिक पोस्टिंग समेत कई महत्त्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है।

राजीव कुमार ने वित्त मंत्रालय की कमान बेशक हाल ही में संभाली हो, लेकिन वित्तीय मामलों पर काम करने का इनका ये पहला अवसर नहीं है। ये जून तक वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा में सचिव थे और व्यय विभाग में संयुक्त सचिव व अपर सचिव के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। राजीव अपनी उत्कृष्ट सोच और जवाबदेह कार्यशैली के ज़रिये पीएम मोदी की कई महत्वाकांक्षी योजनाओं, जैसे जन-धन योजना, मुद्रा लोन योजना, 59 मिनट लोन योजना (एमएसएमई क्षेत्र के लिये) को साकार करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। सरकार के कई महत्पूर्ण वित्तीय निर्णयों को इन्होंने बखूबी अंजाम तक पहुँचाया है. ये केंद्र की उस योजना का भी नेतृत्व कर चुके हैं, जिसके तहत बैंकों के विलय को मंजूरी दी गयी थी। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लगभग 2.11 लाख करोड़ रुपए का रीकैपिटलाइजेशन भी राजीव कुमार की देख-रेख में ही हुआ था।

बैंकिंग क्षेत्र में कई सुधारों का श्रेय राजीव कुमार को जाता है। अपनी कार्यकुशलता के दम पर इन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को रिकॉर्ड पूंजी निवेश उपलब्ध कराया है। इनकी योग्यता और अनुभव को देखते हुए इन्हें तीन बार बजट बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाया जा चुका है। इसके अलावा ये बैंकिंग नियामक भारतीय रिजर्व बैंक और देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड में भी शामिल हैं।

अन्य प्रमुख नाम:

संजय अग्रवाल
रीना राय
जलज श्रीवास्तव
सी के मिश्रा
अजय कुमार सवेनेय

(इस श्रेणी के सभी प्रमुख ब्यूरोक्रेटस की पूरी प्रोफाइल fameindia.co पर पब्लिश की जा रही है।)

फेम इंडिया मैगजीन- एशिया पोस्ट के प्रमुख मापदंड:

- दूरदर्शिता - ✓
- उत्कृष्ट सोच - ✓
- जवाबदेह - ✓
- गंभीरता - ✓
- शानदार गवर्नेंस - ✓
- व्यवहार कुशलता - ✓
- फैसला लेने की क्षमता - ✓

इन सात मुख्य बिंदुओं पर किये गये वार्षिक सर्वे 'असरदार ब्यूरोक्रेट्स -2019' में राजीव कुमार प्रमुख स्थान पर हैं।

सर्वे स्रोत :- विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की राय पर आधारित

FAME INDIA

कई पुरस्कारों से सम्मानित ब्यूरोक्रट हैं डॉ. अजय कुमार

उत्कृष्ट

अगस्त 2019 में नियुक्त भारत के रक्षा सचिव डॉ. अजय कुमार की पहचान एक बेहद जानकार और अनुभवी अधिकारी की है। रक्षा संबंधी नीतियों और मंत्रालय के प्रशासनिक व अन्य सभी पहलुओं पर रक्षा-मंत्री को उचित सलाह देना और सरकार की नीतियों को मंत्रालय से लेकर देश की सीमाओं तक लागू करवाना इनकी अहम जिम्मेदारियों में शामिल है। डॉ. अजय कुमार 1985 बैच के केरल कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। इनका जन्म 2 अक्टूबर, 1962 को पंजाब के जलंधर में हुआ था। ये आईआईटी कानपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक हैं।

डॉ. अजय कुमार ने मिनिसोटा यूनिवर्सिटी से डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में मास्टर ऑफ साइंस और मिनिसोटा यूनिवर्सिटी में कार्लसन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से बिजनेस ऐडमिनिस्ट्रेशन में पीएचडी भी की है।

डॉ.अजय कुमार भारत के 39वें रक्षा सचिव हैं। इससे पहले ये रक्षा उत्पादन सचिव थे। विभिन्न हथियार प्रणालियों के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाने और वर्ष 2025 तक विश्व के टॉप 5 हथियार उत्पादक देशों में शामिल होने की दिशा में डिफेंस प्रोडक्शन पॉलिसी तैयार करना इनकी दूरदर्शी सोच का परिचायक है। इनके ही प्रयासों का परिणाम है कि आज कई नये हथियारों और तोपों की डिज़ाइन और डेवलपमेंट का काम भारत में होने लगा है और भारतीय कंपनियां ग्लोबल डिफेंस मार्केट को टक्कर देने की दिशा में अग्रसर हैं।

डॉ अजय कुमार ने लगभग 30 वर्षों तक केरल व केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं दी हैं। जब ये वर्ष 2010 में भारत सरकार के आईटी विभाग में बतौर एडिशनल सेक्रेटरी पहुंचे तब ये टेलीकॉम मंत्रालय का हिस्सा था। इन्होंने सरकार से प्रस्ताव पास करवा कर इसे इलेक्ट्रानिक व आईटी मंत्रालय बनवाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी। मेक इन इंडिया के दौरान भारत में मोबाइल फोन से लेकर अन्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के निर्माण को बढावा देने वाली नीतियों का मसौदा इन्होंने ही तैयार किया था। इन्होंने माय गांव, प्रगति, जीवन प्रमाण, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, सरकारी विभागों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस जैसे कई महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमों को सफल बनाने में अहम रोल अदा किया है।

डॉ.अजय कुमार ने केरल में उद्योगों व आईटी उपक्रमों के विकास में काफी योगदान दिया है। प्रदेश में गैर परंपरागत ऊर्जा के विकास में भी इनकी अहम भूमिका रही। इनके कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कई रिसर्च पेपर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित हो चुके हैं। अपने स्कूल के दिनों में डॉ अजय कुमार भारत के राष्ट्रपति के हाथों स्काउटिंग के सर्वोच्च पुरस्कार सिल्वर एलीफेंट मेडल से भी सम्मानित हो चुके हैं।

अन्य प्रमुख नाम:

श्री शैलेश
बृज कुमार अग्रवाल
प्रवीण परदेशी
दीपक खांडेकर
विजय वर्धन

(इस श्रेणी के सभी प्रमुख ब्यूरोक्रेटस की पूरी प्रोफाइल fameindia.co पर पब्लिश की जा रही है।)

फेम इंडिया मैगज़ीन- एशिया पोस्ट के प्रमुख मापदंड:

- दूरदर्शिता - ✓
- उत्कृष्ट सोच - ✓
- जवाबदेह - ✓
- गंभीरता - ✓
- शानदार गवर्नेंस - ✓
- व्यवहार कुशलता - ✓
- फैसला लेने की क्षमता - ✓

इन सात मुख्य बिंदुओं पर किये गये वार्षिक सर्वे 'असरदार ब्यूरोक्रेट्स -2019' में डॉ अजय कुमार प्रमुख स्थान पर हैं।

सर्वे स्रोत :- विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की राय पर आधारित

देश के नागरिक उड्डयन को उम्मीद है जिनसे प्रदीप सिंह खरोला

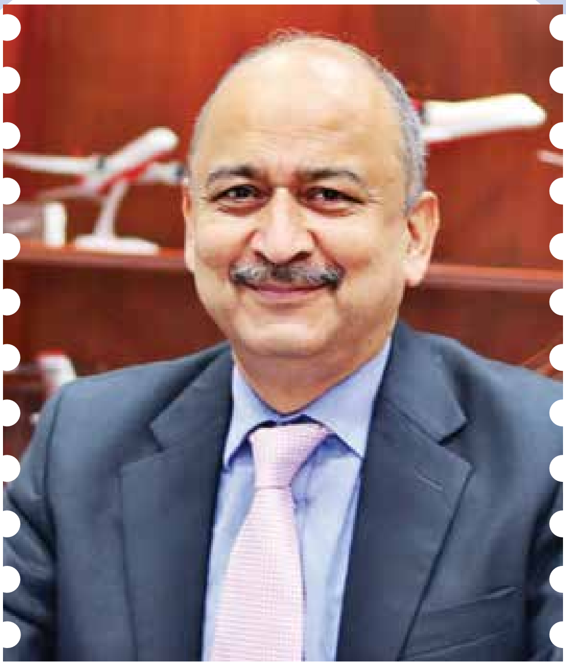

उम्मीद

देश के सबसे चर्चित नौकरशाहों में से एक प्रदीप सिंह खरोला देश की नागरिक उड्डयन व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। ये 1985 बैच के कर्नाटक कैडर के आईएएस अधिकारी हैं और देश के एविएशन सेक्रेटरी हैं। इससे पूर्व इन्हें एयर इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। ये प्रतष्ठित बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक भी रह चुके हैं।

मूल रूप से देहरादून के रहने वाले प्रदीप सिंह खरोला ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर मैनेजमेंट में डिप्लोमा भी किया है। ये कर्नाटक सरकार में विभिन्न पदों पर रह चुके हैं और इन्हें एक दूरदर्शी व ईमानदार अधिकारी के तौर पर जाना जाता है। 2015 में इन्हें पर्यटन विभाग, कर्नाटक सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। इससे पहले इन्हें 2013 में कर्नाटक अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन का चेयरमैन भी बनाया गया। जब 1997 में बैंगलोर मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन बनाया गया तो ये इसके प्रबंध निदेशक बनाये गये। ये बैंगलोर डेवलपमेंट ऑथारिटी कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम के भी मैनेजिंग डायरेक्टर रहे। कर्नाटक में एयर कंडीशन्ड बसें दौड़ा कर घाटे में चल रहे निगम को फायदे में बदलने का इनका करिश्मा आज भी याद किया जाता है। ये बेलगाम और उत्तर कर्नाटक के जिलाधिकारी भी रह चुके हैं।

प्रदीप सिंह खरोला ने आईआईएम लखनऊ, आईआईएम बैंगलोर व आईएएस अकादमी जैसे संस्थानों से शहरी प्लानिंग, इंटरप्राइज़ मैनेजमेंट, बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग व ई गवर्नेंस जैसे विषयों का विशेष प्रशिक्षण लिया है। जब वर्ष 2013 में बैंगलोर मेट्रो की प्लानिंग शुरू हुई तो ये सभी की पहली पसंद थे। इन्होंने बैंगलोर महानगर में सफलता पूर्वक मेट्रो का निर्माण व परिचालन भी करवाया। एक अर्से से ये तकनीक और प्रबंधन जैसे विषयों पर अंतर्राष्ट्रीय पत्र-पत्रिकाओं में शोधपत्र और लेख लिखते रहे हैं।

इन्हें देश का नागरिक उड्डयन विभाग का सचिव जैसा पद देना बताता है कि सरकार इनकी सूझबूझ और दूरदर्शिता की कितनी कायल है, क्योंकि अभी देश में एक ओर घरेलू उड्डयन को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता है वहीं भारी-भरकम घाटे से जूझ रही एयर इंडिया को सरकार की मंशा रणनीतिक विनिवेश के तौर तरीकों को अंतिम रूप देने की है।

अन्य प्रमुख नाम:

अमित खड़े
अनुप वधावन
आर सुब्रह्मण्यम
परिमल राय
मधुकर गुप्ता

(इस श्रेणी के सभी प्रमुख ब्यूरोक्रेटस की पूरी प्रोफाइल fameindia.co पर पब्लिश की जा रही है।)

फेम इंडिया मैगजीन- एशिया पोस्ट के प्रमुख मापदंड:

दूरदर्शिता - ✓
उत्कृष्ट सोच - ✓
जवाबदेह - ✓
गंभीरता - ✓
शानदार गवर्नेंस - ✓
व्यवहार कुशलता - ✓
फैसला लेने की क्षमता - ✓

इन सात मुख्य बिंदुओं पर किये गये वार्षिक सर्वे 'असरदार ब्यूरोक्रेट्स -2019' में प्रदीप सिंह खरोला प्रमुख स्थान पर हैं।

सर्वे स्रोत :- विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की राय पर आधारित

FAME INDIA

जल संसाधन और पर्यावरण के विशेषज्ञ हैं उपेंद्र प्रसाद सिंह

जागरूक

उपेंद्र प्रसाद सिंह का नाम आजकल हर तरफ चर्चा में है क्योंकि इन्हें जल बचाने की जिम्मेदारी दी गई है, कहा जाता है कि "जल बिन सब सून" इस बारे में सोचने और बचाने की मुहिम इनके जिम्मे है। बिहार के एक छोटे से गांव गोविंदपुर के किसान मजदूर परिवार में जन्मे उपेंद्र प्रसाद सिंह बचपन से ही मेधावी रहे हैं। आभावग्रस्त बचपन इनके इरादों को नहीं रोक पाया। खेत खलिहान से समय निकलने पर पढ़ाई करने के बावजूद इन्होंने मैट्रिकुलेशन और बोर्ड परीक्षा में पूरे राज्य में तीसरा स्थान प्राप्त किया।

पटना सांइस कालेज में पढ़ाई के बाद इन्होंने आईआईटी कानपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। उस समय आईआईटी पास करने वालों का ध्येय अमेरिका होता था, परन्तु इन्होंने युवा अवस्था से ही साधारण जन के लिए कुछ करने का प्रण कर रखा था।

लोक सेवा में आने की भावना से सिविल सर्विस के लिए प्रयास शुरू किया। इनका चयन करीब 34 वर्ष पहले यूपीएससी के लिए हुआ और आज इनकी पहचान देश के वरिष्ठ और कर्त्तव्यनिष्ठ ब्यूरोक्रेट के रूप में है।

ये1985 बैच के ओडिशा कैडर के आईएएस अधिकारी है। उपेंद्र प्रसाद सिंह को हिन्दी, अंग्रेजी के अलावा मिजो भाषा की भी अच्छी जानकारी है। पर्यावरण, जल और उससे जुड़ी जानकारी के मामले में इनका कोई सानी नहीं है। इन्होंने ओडिशा सरकार में प्रमुख सचिव जल संसाधन के रूप में लंबे समय तक काम किया है। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से पहले येओडिशा सरकार में प्रधान सचिव कृषि थे।

उपेंद्र प्रसाद सिंह 21 नवंबर, 2016 को भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव के पद पर स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन में महानिदेशक के रूप में नामित किए गए। इन्होंने वहां अपनी शानदार गवर्नेंस, उत्कृष्ट सोच का परिचय दिया। ये जहां भी रहे अपने दूरदर्शिता के लिए जाने जाते रहे। इसके अलावा उपेंद्र सिंह इस्पात मंत्रालय में भी पदस्थापित थे। पेट्रोलियम मंत्रालय के सार्वजनिक उपक्रम ऑयल इंडिया लिमिटेड के एमडी के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स में स्थानांतरित होने से पहले, यूपी सिंह मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड गैस में संयुक्त सचिव और फिर अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत थे। इन्होंने हर पद पर अपने कार्य की दक्षता सिद्ध की है।

इस वर्ष जून में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा के कायाकल्प करने का जिम्मा इन्हें सचिव के तौर पर दिया गया है जो वर्त्तमान सरकार और प्रधानमंत्री की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में एक है।

अन्य प्रमुख नाम:

दुर्गा शंकर मिश्रा
डॉ इंद्रजीत सिंह
समीर शर्मा
राजीव रंजन
अनिता प्रसाद

(इस श्रेणी के सभी प्रमुख ब्यूरोक्रेटस की पूरी प्रोफाइल fameindia.co पर पब्लिश की जा रही है।)

फेम इंडिया मैगज़ीन- एशिया पोस्ट के प्रमुख मापदंड:

- दूरदर्शिता - ✓
- उत्कृष्ट सोच - ✓
- जवाबदेह - ✓
- गंभीरता - ✓
- शानदार गवर्नेंस - ✓
- व्यवहार कुशलता - ✓
- फैसला लेने की क्षमता - ✓

इन सात मुख्य बिंदुओं पर किये गये वार्षिक सर्वे 'असरदार ब्यूरोक्रेट्स -2019' में उपेंद्र प्रसाद सिंह प्रमुख स्थान पर हैं।

सर्वे स्रोत :- विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की राय पर आधारित

FAME INDIA

दूरगामी योजना बनाने में माहिर हैं अंशु प्रकाश

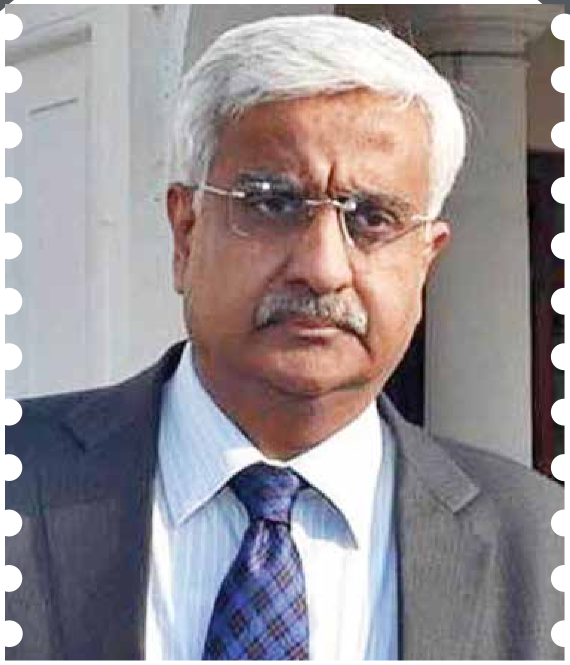

दूरदर्शी
★★★★★

आज के आधुनिक युग में टेलीफोन और मोबाइल के बढ़ते महत्त्व के मद्देनजर दूरसंचार एक ऐसा मंत्रालय बन गया है जिसे संभालना किसी तेज-तर्रार और बेहद समझदार अधिकारी के ही बस में है।

फिलहाल इस वक्त देश में टेलिकॉम सेक्टर सबसे ज्यादा चैलेंजिंग मोड़ पर है और शानदार गवर्नेंस और इनकी कार्यकुशल क्षमता के ही कारण मोदी सरकार ने इसकी कमान सेंट स्टीफेंस से ग्रेजुएट व प्रतिष्ठित फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ से एमबीए आईएएस अधिकारी अंशु प्रकाश को सौंपी है। ये इस विभाग में पहले भी अपनी योग्यता साबित कर चुके हैं। देश में 5जी को सफलतापूर्वक स्थापित करने और टेलिकॉम सेक्टर को मजबूत करने की जिम्मेदारी इनकी है।

1986 बैच के व्यवहार कुशल आईएएस अधिकारी अंशु प्रकाश न सिर्फ योग्य और कुशल प्रशासक हैं बल्कि एक स्वाभिमानी और अन्याय के खिलाफ डट कर लड़ने वाले इंसान भी हैं।

मूल रूप से दिल्ली के रहने वाले अंशु प्रकाश अरुणाचल-गोवा-मिजोरम एवं केंद्र शासित (एजीएमयूटी) कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में ये कई महत्त्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं और वहां इनकी बनायी नीतियों को आज भी बतौर मिसाल याद किया जाता है। स्वास्थ्य सेवाओं में इनके योगदान की देश भर में चर्चा रही है, मेंटल हेल्थ एक्ट सहित कई स्वास्थ्य संबंधित योजनाओं में इनका बड़ा योगदान रहा है।

ये दिल्ली सरकार के दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी डीटीसी के चेयरमैन सह मैनेजिंग डायरेक्टर भी रह चुके हैं। डीटीसी में बड़े बदलाव के लिए भी इन्हें जाना जाता है। इन्होंने ही दिल्ली में लो फ्लोर बसों का संचालन शुरु करवाया, इन्होंने डीटीसी में सुधारों के जो बीज बोये थे उनसे कुछ ही वर्षों में इस संस्थान ने मुनाफे का कारोबार शुरू कर दिया।

अंशु प्रकाश वित्त, सूचना व प्रसारण, पर्यटन जैसे कई महत्त्वपूर्ण मंत्रालयों में विभिन्न पदों पर रह चुके हैं। इसके अलावे ये दिल्ली, गोवा व अंडमान-निकोबार द्वीप समूह आदि के प्रशासन में भी तैनात रहकर उत्कृष्ट व यादगार सेवाएं दे चुके हैं।

अन्य प्रमुख नाम:

डॉ संजीव रंजन
किरन सोनी गुप्ता
डॉ छत्रपति शिवाजी
सतबीर बेदी
आलोक टंडन

(इस श्रेणी के सभी प्रमुख ब्यूरोक्रेट्स की पूरी प्रोफाइल fameindia.co पर पब्लिश की जा रही है।)

फेम इंडिया मैगजीन- एशिया पोस्ट के प्रमुख मापदंड:

- दूरदर्शिता - ✓
- उत्कृष्ट सोच - ✓
- जवाबदेह - ✓
- गंभीरता - ✓
- शानदार गवर्नेंस - ✓
- व्यवहार कुशलता - ✓
- फैसला लेने की क्षमता - ✓

इन सात मुख्य बिंदुओं पर किये गये वार्षिक सर्वे 'असरदार ब्यूरोक्रेट्स -2019' में अंशु प्रकाश प्रमुख स्थान पर हैं।

सर्वे स्रोत :- विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की राय पर आधारित

FAME INDIA

एयरपोर्ट अथॉरिटी को असरदार बनाया गुरु प्रसाद महापात्र ने

असरदार

इस साल जनवरी में डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी का नाम बदल कर डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (डीपीआईआईटी) कर दिया गया। जाहिर है नाम के साथ-साथ विभाग की जिम्मेदारियों और कार्यशैली में भी बदलाव आया। इस बदली हुई परिस्थिति में सरकार ने तैनात किया है एक योग्य अधिकारी के तौर पर गुरुप्रसाद महापात्र को। इन्हें देश में आंतरिक व्यापार बढ़ाने की महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गयी है। डीपीआईआईटी आने से पहले महापात्र करीब तीन साल तक एयरपोर्ट ऑथारिटी ऑफ इंडिया (एएआई) के चेयरमैन थे।

गुरुप्रसाद महापात्र देश को बड़े एयरपोर्टों के सफलतापूर्वक निजीकरण करने के लिये जाना जाता है। मूल रूप से उड़ीसा के रहने वाले गुरुप्रसाद महापात्र गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी हैं और इन्होंने 1986 में नौकरी ज्वाइन की थी। ये राजनीति शास्त्र में एमए और एमफिल हैं। इन्होंने एमबीए की डिग्री भी हासिल की है। इनकी महत्त्वपूर्ण नियुक्तियों में अहमदाबाद के म्युनिसिपल कमिश्नर का पद शामिल रहा है। ये गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर भी रह चुके हैं और प्रदेश में सेल्स टैक्स के स्पेशल कमिश्नर भी। इसके अलावे ये प्रदेश सरकार में कमर्शियल टैक्स और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जैसे महत्त्वपूर्ण विभागों के कमिश्नर के तौर पर सेवाएं दे चुके हैं। ये पॉवर सेक्टर से भी लंबे अरसे तक जुड़े रहे और गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को नया रूप देकर कई लाभकारी व आधुनिक कंपनियों में बदलने में इनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका रही। गुरुप्रसाद महापात्र गुजरात की प्रमुख खाद कंपनियों की कमान भी संभाल चुके हैं। बतौर म्युनिसिपल कमिश्नर इन्होंने गुजरात के सबसे प्रमुख व्यवसायिक नगरी सूरत की शक्ल-सूरत ही बदल डाली। वहां सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में इनके सुधारों ने सूरत को एक मॉडल बना दिया। ये वो दौर था जब पीएम मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे।

गुजरात में व्यापार और उद्योग को सफलता पूर्वक बढ़ाने में महापात्र की भूमिकाओं को देखते हुए ही जब नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार की कमान संभाली तो इन्हें कॉमर्स मंत्रालय में बतौर ज्वाइंट सेक्रेटरी नियुक्त करवाया। इसके दो वर्षों बाद ही इन्हें देश भर के हवाई अड्डों की कायापलट के लिये एयरपोर्ट ऑथारिटी ऑफ इंडिया की कमान सौंपी गयी। इस विभाग के पटरी पर दौड़ने के बाद इन्हें देश में आंतरिक व्यापार की बागडोर सौंपी गयी है। देश में तेजी से उभर रहे स्टार्टअप को बढ़ावा देने और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने में गुरुप्रसाद महापात्र की महत्त्वपूर्ण भूमिका होगी।

अन्य प्रमुख नाम:

- अतुल चतुर्वेदी
- जयश्री मुखर्जी
- आलोक सिन्हा
- वंदिता शर्मा
- अनिल कुमार कांची

(इस श्रेणी के सभी प्रमुख ब्यूरोक्रेटस की पूरी प्रोफाइल fameindia.co पर पब्लिश की जा रही है।)

फेम इंडिया मैगज़ीन- एशिया पोस्ट के प्रमुख मापदंड:

- दूरदर्शिता - ✓
- उत्कृष्ट सोच - ✓
- जवाबदेह - ✓
- गंभीरता - ✓
- शानदार गवर्नेंस - ✓
- व्यवहार कुशलता - ✓
- फैसला लेने की क्षमता - ✓

इन सात मुख्य बिंदुओं पर किये गये वार्षिक सर्वे 'असरदार ब्यूरोक्रेट्स -2019' में गुरुप्रसाद महापात्र प्रमुख स्थान पर हैं।

सर्वे स्रोत :- विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की राय पर आधारित

FAME INDIA

कर्मठता के लिए मशहूर रहे हैं विजय कुमार देव

कर्मठ

दिल्ली सरकार में मुख्य सचिव की ज़िम्मेदारी संभाल रहे आईएएस अफसर विजय कुमार देव की गिनती ऐसे अफसरों में कई जाती है, जिनके काम की तारीफ बार-बार होती है। दिल्ली के अंदर कई विभागों में अहम ज़िम्मेदारी निभा चुके विजय कुमार को राजधानी का सबसे अनुभवी अफसर भी कह सकते हैं।

विजय कुमार 1987 बैच और अरुणाचल - गोवा - मिजोरम एवं केंद्र शासित (एजीएमयूटी) कैडर के आईएएस आईआईटी दिल्ली के ग्रेजुएट हैं और अंग्रेज़ी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू समेत कई भाषाओं में माहिर भी हैं। सन 2017-18 में स्किल डेवेलपमेंट में डीजी के पद से लेकर दिल्ली परिवहन निगम के सीएमडी जैसी अहम भूमिकाओं में विजय कुमार ने बेहतरीन काम किया है। जब ये चंडीगढ़ के प्रशासक के सलाहकार थे तो आम लोगों से आसानी से मिलने-जुलने की वजह से बेहद लोकप्रिय रहे, साथ ही सोशल साइट्स पर काफी एक्टिव हैं। करियर के शुरुआती समय में गोवा और बाद में अरुणाचल में भी काम करने का अनुभव विजय कुमार देव को एक ऐसा ऑफिसर बनाता है जिसने देश के पश्चिमी सिरे से लेकर पूर्वी सिरे तक अपनी सेवाएं दी हैं। इनकी कर्मठता और क्षमता का सबूत ये है कि इनके नाम राष्ट्रपति अवार्ड और दो राज्यपाल गोल्ड मैडल भी हैं। एक गोल्ड मैडल तो चीन के बॉर्डर से लगे दूर दराज के गांव को बिजली से रौशन करने के लिए मिला। इस गांव में आज़ादी के 50 साल बाद भी अंधेरा था। दूसरा गोल्ड मेडल अरुणाचल की खस्ताहाल अर्थ व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए मिला। विजय कुमार देव तब अरुणाचल के वित्त सचिव हुआ करते थे। मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के रहने वाले विजय कुमार देव आईआईटी दिल्ली से ग्रेजुएट हैं। इनके पूरे करियर को अगर देखा जाए तो ये एक क्षमतावान, संकटमोचक और लक्ष्य को हासिल करने वाले एक तेज़ तर्रार, आक्रामक प्रशासनिक अधिकारी नज़र आते हैं। स्वभाव से शालीन विजय कुमार देव खबरों से दूर रह कर विकास के बड़े कार्य और सुधार करने वाले ब्यूरोक्रेट के तौर पर जाने जाते हैं।

अन्य प्रमुख नाम:

तरूण कपूर
सत्यजीत रंजन
एम सी जोहरी
के जय कुमार
बी एच अनिल कुमार

(इस श्रेणी के सभी प्रमुख ब्यूरोक्रेटस की पूरी प्रोफाइल fameindia.co पर पब्लिश की जा रही है।)

फेम इंडिया मैगजीन- एशिया पोस्ट के प्रमुख मापदंड:

- दूरदर्शिता - ✓
- उत्कृष्ट सोच - ✓
- जवाबदेह - ✓
- गंभीरता - ✓
- शानदार गवर्नेंस - ✓
- व्यवहार कुशलता - ✓
- फैसला लेने की क्षमता - ✓

इन सात मुख्य बिंदुओं पर किये गये वार्षिक सर्वे 'असरदार ब्यूरोक्रेट्स -2019' में विजय कुमार देव प्रमुख स्थान पर हैं।

सर्वे स्रोत :- विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की राय पर आधारित

FAME INDIA

विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं अवनीश कुमार अवस्थी

बेजोड़
★★★★★

उत्तर प्रदेश के सबसे असरदार ब्यूरोक्रेट में शुमार अवनीश कुमार अवस्थी 1987 बैच के यूपी कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। वर्तमान में अवस्थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रमुख सचिव हैं। इन्हें कार्यकुशल, साहसी और ईमानदार प्रशासनिक अधिकारी माना जाता है। शानदार ट्रैक रिकॉर्ड और साफ़ छवि के चलते ही इन्हें मुख्यमंत्री कार्यालय का प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया है।

आईआईटी कानपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी से ग्रेजुएट अवनीश कुमार अवस्थी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से पहले कैरियर के करीब 26 साल उत्तर प्रदेश के ही विभिन्न जिलों, विभागों और मंत्रालयों में पदस्थापित रहें। इसलिए कहा जाता है कि इन्हें राज्य के ज्यादातर इलाकों की समस्यायों और उनके समाधान का तरीका पता है।

ये मेरठ, वाराणसी, बदायूं, आजमगढ़, फैजाबाद और ललितपुर आदि जिलों में बतौर जिला अधिकारी कार्य कर चुके हैं। ये गोरखपुर के डीएम भी रहे, इस दौरान इनकी कार्यशैली, शानदार गवर्नेंस और दूरदर्शिता ने वहां के तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ को बेहद प्रभावित किया।इन्होंने राज्य सरकार में कई महत्त्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारियां भी निभाई।

वर्ष 2017 में इन्हें उत्तर प्रदेश के सूचना, धर्म और पर्यटन विभाग के मुखिया बनाने के साथ ही राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट एक्सप्रेस ये से जुड़े विभाग यूपीडा को भी संभालने का उत्तरदायित्व दिया गया। फिलहाल इनकी जिम्मेदारी को और बढ़ाते हुए यूपी की कानून व्यवस्था को संभालने की भी कर दी गई है।

वर्ष 2013 से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर सोशल जस्टिस एंड इंपावरमेंट मिनिस्ट्री में ज्वाइंट सेक्रेटरी अवनीश कुमार अवस्थी को योगी सरकार के बनते ही 2017 में कैडर में वापस बुला लिया गया। केंद्र के कार्यकाल के दौरान इन्होंने दिव्यांग व्यक्तियों के उत्थान और विकास के लिए बनी एडीआईपी योजना को अपग्रेड किया। तीन वर्षों के अंदर 5 लाख से ज्यादा ज़रूरतमंदों को जिसका लाभ मिला।

अपने सरल और मिलनसार स्वभाव के लिए जाने जाने वाले अवनीश कुमार अवस्थी समय के पक्के और अनुशासन प्रिय हैं। ये एक कुशल प्रशासक और बेहतरीन टीम लीडर हैं। इन्होंने हर काम को एक मिशन के रूप में लिया और उसे समय से पूरा किया है।

अन्य प्रमुख नाम:

बी बी आर सुब्रह्मण्यम
प्रवीर कृष्णा
राजीव रंजन मिश्रा
राम मोहन मिश्रा
रामेश्वर प्रसाद गुप्ता

(इस श्रेणी के सभी प्रमुख ब्यूरोक्रेटस की पूरी प्रोफाइल fameindia.co पर पब्लिश की जा रही है।)

फेम इंडिया मैगज़ीन- एशिया पोस्ट के प्रमुख मापदंड:

दूरदर्शिता - ✓
उत्कृष्ट सोच - ✓
जवाबदेह - ✓
गंभीरता - ✓
शानदार गवर्नेंस - ✓
व्यवहार कुशलता - ✓
फैसला लेने की क्षमता - ✓

इन सात मुख्य बिंदुओं पर किये गये वार्षिक सर्वे 'असरदार ब्यूरोक्रेट्स -2019' में अवनीश कुमार अवस्थी प्रमुख स्थान पर हैं।

सर्वे स्रोत :- विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की राय पर आधारित

FAME INDIA

अंदाजे बयां ही कुछ और है चितरंजन कुमार खेतान का

शख्सियत

छत्तीसगढ़ के तेज तर्रार आईएएस अधिकारी चितरंजन कुमार खेतान की गिनती उन गिने-चुने अधिकारियों में की जाती है जो प्रदेश के हर शासनकाल में सार्वाधिक लोकप्रिय रहे हैं। ये मूलरूप से बिहार के सीतामढ़ी के रहने वाले हैं और 1987 बैच में भारतीय प्रशासनिक सेवा के छत्तीसगढ़ कैडर में शामिल हुए थे। अपने लंबे कार्यकाल में इन्होंने कई ऐसे कार्य किये हैं जिनके लिये इन्हें बरसों याद रखा जायेगा।

बिहार विश्वविद्यालय से बीए में गोल्ड मेडल प्राप्त करने के बाद जब ये दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में एमए करने आये तो इन्होंने यहां भी पूरे विश्वविद्यालय में टॉप कर गोल्ड मेडल हासिल किया। इन्होंने एमफिल की डिग्री भी हासिल की। ये कुछ समय के लिये पत्रकारिता से भी जुड़े और प्रतिष्ठित पत्रिका इंडिया टुडे में बतौर सब एडीटर कार्य किया। 1987 में इनका चयन सर्वोच्च सेवा आईएएस के लिये हो गया। इसके बाद भी इन्होंने अपनी शिक्षा जारी रखी और ब्रिटेन के बर्मिंघम विश्वविद्यालय से एमबीए व नीदरलैंड के रॉथेर्डम विश्वविद्यालय से अर्बन प्लानिंग में डिस्टिंक्शन के साथ सर्टिफिकेट हासिल किया। बतौर जल संसाधन सचिव लागू की गई इनकी "पावर प्लांट द्वारा जल संरक्षण " पालिसी देश भर में चर्चा में रही है।

मध्यप्रदेश कैडर में चितरंजन खेतान ने इंदौर के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के प्रशासक के तौर पर अभूतपूर्व कार्य किया। इन्होंने न सिर्फ प्रॉपर्टी टैक्स की चोरी रोकी बल्कि अन्य विभागों के साथ मिल कर शॉपिंग मॉल्स भी बनवाये और आउटडोर पब्लिसिटी के जरिये आय की शुरुआत करवायी। वर्ल्ड बैंक के बाल विकास परियोजना से जुड़ कर इन्होंने छत्तीसगढ़ के पिछड़े इलाकों में काफी कार्य किये। छतरपुर के जिलाधिकारी के तौर पर इन्होंने खजुराहो के विकास की स्कीम तैयार की जिसके कारण यह पर्यटन स्थल आज अंतराष्ट्रीय पटल पर है। ये लघु उद्योग विभाग के निदेशक भी रहे जहां इन्होंने पहली बार एक स्टेट पॉलिसी बनायी। छत्तीसगढ़ सरकार के गठन के बाद ये रायपुर के जिलाधिकारी रहे। मीडिया से जुड़ाव और समझ के कारण इन्हें राज्य का सूचना निदेशक भी नियुक्त किया गया।

ये केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर परिवहन विभाग में ज्वाइंट सेक्रेटरी और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में नेशनल ट्रस्ट के सीईओ भी रहे। कई देशों के प्रशासनिक सिस्टम का अध्ययन भी किया है। फिलहाल ये बतौर अतिरिक्त मुख्य आयुक्त प्रदेश के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

FAME INDIA

अन्य प्रमुख नाम:

अमिर सुबहानी
डॉ वी पी जोय
आई एस एन प्रसाद
विपुल मित्रा
गौरी सिंह

(इस श्रेणी के सभी प्रमुख ब्यूरोक्रेटस की पूरी प्रोफाइल fameindia.co पर पब्लिश की जा रही है।)

फेम इंडिया मैगजीन- एशिया पोस्ट के प्रमुख मापदंड:

- दूरदर्शिता - ✓
- उत्कृष्ट सोच - ✓
- जवाबदेह - ✓
- गंभीरता - ✓
- शानदार गवर्नेंस - ✓
- व्यवहार कुशलता - ✓
- फैसला लेने की क्षमता - ✓

इन सात मुख्य बिंदुओं पर किये गये वार्षिक सर्वे 'असरदार ब्यूरोक्रेट्स -2019' में चितरंजन कुमार खेतान प्रमुख स्थान पर हैं।

सर्वे स्रोत :- विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की राय पर आधारित

लगन से कार्य करने वाली पहचान है नरेश कुमार की

लगनशील

★★★★★

भारत की पूर्वोत्तर सीमा पर स्थित सबसे अहम राज्य अरुणाचल प्रदेश की कमान संभाल रहे नरेश कुमार 1987 बैच के एक डायनमिक और कार्यकुशल आईएएस अधिकारी हैं। मिलनसार और मृदुभाषी नरेश कुमार इसके पहले चार वर्षों तक नयी दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) के अध्यक्ष रहे और इस दौरान इनके द्वारा उठाये गये कदमों की आज भी खासी प्रशंसा होती है।

एनडीएमसी में इन्होंने पीएम मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को इतने अनोखे और सफल तरीके से लागू किया कि वह कई मामलों में देश ही नहीं, दुनिया भर में एक मिसाल बन गया। इन्होंने दुनिया में पहली बार एनडीएमसी के शौचालयों को स्वच्छता केंद्र के तौर पर विकसित किया। इनके वाई-फाई वाले स्मार्ट शौचालयों की चर्चा पूरी दुनिया में हुई तो सीवर के पानी को पब्लिक-प्राइवेट मोड में साफ कर सिंचाई में उपयोग करने का मॉडल पूरे देश में अनुकरणीय बना। इन्होंने पूरे एनडीएमसी इलाके को वाई-फाई सुविधा दिलाने की जो पहल की वह अभी भी देश के महानगरों के लिये एक सपना भर है। मोदी सरकार के महत्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को बेहतरीन ढंग से लागू करने का इनका प्रयास सराहनीय रहा।

नरेश कुमार केंद्रीय माइनिंग मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी रह चुके हैं। दिल्ली खादी ग्रामोद्योग के अध्यक्ष भी रहे हैं। नरेश कुमार केंद्रीय गृह मंत्रालय, अरुणाचल प्रदेश और अंडमान-निकोबार में अहम पदों पर रहे हैं। साउथ दिल्ली के डीसी के अलावा कई महत्त्वपूर्ण पद पर भी वह काम कर चुके हैं।

मूल रूप से दिल्ली के रहने वाले नरेश कुमार ने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में एमबीए और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की हुई है। इन्होंने अमेरिका की ड्यूक युनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट कोर्स भी किया है। ये कर्म को पूजा के विचार को मानने वाले लगनशील ब्यूरोक्रेट है, जिनके कार्यों की एक लंबी सूची है।

अन्य प्रमुख नामः

अश्वनी कुमार
आर बिंचिलो थांग
नील कमल दरबारी
वीनू गुप्ता
सुनील कुमार गुप्ता

(इस श्रेणी के सभी प्रमुख ब्यूरोक्रेटस की पूरी प्रोफाइल fameindia.co पर पब्लिश की जा रही है।)

फेम इंडिया मैगज़ीन- एशिया पोस्ट के प्रमुख मापदंडः

- दूरदर्शिता - ✓
- उत्कृष्ट सोच - ✓
- जवाबदेह - ✓
- गंभीरता - ✓
- शानदार गवर्नेंस - ✓
- व्यवहार कुशलता - ✓
- फैसला लेने की क्षमता - ✓

इन सात मुख्य बिंदुओं पर किये गये वार्षिक सर्वे 'असरदार ब्यूरोक्रेट्स -2019' नरेश कुमार प्रमुख स्थान पर हैं।

सर्वे स्रोत :- विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की राय पर आधारित

FAME INDIA

अपनी व्यवहार कुशलता से बनाई खास पहचान राजेश भूषण ने

व्यवहार कुशल
★★★★★

कैबिनेट सचिवालय जैसे देश के सबसे महत्त्वपूर्ण विभाग में अतिरिक्त सचिव राजेश भूषण 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं. ये बिहार कैडर से हैं और कई वर्षों से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं। इससे पहले ये मनरेगा के ज्वाइंट सेक्रेटरी थे जो केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार का एक महत्त्वपूर्ण अंग है। उत्तराखंड के मूल निवासी राजेश भूषण ने आधुनिक भारतीय इतिहास विषय से एम ए किया है और 1987 में भारतीय प्रशासनिक सेवा से जुड़े।

राजेश भूषण ने संयुक्त बिहार-झारखंड के दौरान प्रदेश में सेवा शुरू की थी और कई जिलों में अत्यंत महत्त्वपूर्ण पदों पर रहे।इन्हें एक मृदुभाषी और लो-प्रोफाइल रहने वाले समझदार व कठोर फैसले लेने वाले दृढ़ अधिकारी के तौर पर जाना जाता है। नीतीश कुमार के शासन में बिहार पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन व एमडी, परिवहन विभाग के सचिव, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव व प्रधान सचिव के अलावा राज्य शिक्षा परियोजना के प्रोजेक्ट डायरेक्टर व प्रोजेक्ट को आर्डिनेटर रह चुके हैं।

राजेश भूषण वर्ष 2008 से 2012 तक तकरीबन चार वर्षों के लिये सूचना एवं जनसंपर्क विभाग एवं राज्य शिक्षा परियोजना के पद पर एक साथ रहे। खास बात ये रही कि दोनों ही विभागों में इन्होंने अपने जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। इस दौरान इनके नेतृत्व में सूचना भवन पटना में ऑडियो-विजुअल लाइब्रेरी की स्थापना हुई। आम लोगों को जागृत करने के लिए विभिन्न विषयों व योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिये प्रचारात्मक लघु फिल्मों का निर्माण किया गया. भोजपुरी फिल्म महोत्सव का आयोजन व जरूरतमंद पत्रकारों के बीच पत्रकार कल्याण कोष से सहायता राशि का विधिवत वितरण कराना महत्त्वपूर्ण उपलब्धि रही। राज्य शिक्षा परियोजना में रहते हुए इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा में गुणवता बढ़ाने के लिये समझे-सीखें कार्यक्रम का क्रियान्वयन को अमलीजामा पहनाया। मध्याह्न भोजन योजना के सफल क्रियान्वयन, बेहतर प्रबंधन, मूल्यांकन और अनुश्रवण के लिये निबंधित समिति का गठन किया।

राजेश भूषण को देश के कैबिनेट सचिवालय में कई महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गयी हैं जिनमें देश के लोक प्रशासन और सभी मंत्रालयों का लेखा-जोखा तैयार करने के अति विशिष्ट कार्य भी शामिल हैं। शानदार कार्यशैली और व्यवहार कुशलता के कारण उम्मीद की जाती है कि ये हमेशा की तरह यहां भी सफल होंगे।

अन्य प्रमुख नाम:

संजीव कुमार मित्तल
निशा सिंह
सुखदेव सिंह
वी मंजुला
ज्ञान पी उपाध्याय

(इस श्रेणी के सभी प्रमुख ब्यूरोक्रेटस की पूरी प्रोफाइल fameindia.co पर पब्लिश की जा रही है।)

फेम इंडिया मैगजीन- एशिया पोस्ट के प्रमुख मापदंड:

- दूरदर्शिता - ✓
- उत्कृष्ट सोच - ✓
- जवाबदेह - ✓
- गंभीरता - ✓
- शानदार गवर्नेंस - ✓
- व्यवहार कुशलता - ✓
- फैसला लेने की क्षमता - ✓

इन सात मुख्य बिंदुओं पर किये गये वार्षिक सर्वे 'असरदार ब्यूरोक्रेट्स -2019' में राजेश भूषण प्रमुख स्थान पर हैं।

सर्वे स्रोत :- विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की राय पर आधारित

FAME INDIA

दक्ष हैं वित्तीय विशेषज्ञता में अजय सेठ

दक्ष ★★★★★

मैकेनिकल इंजीनियरिंग से प्रशासनिक सेवा में आने वाले विलक्षण प्रतिभा के धनी अजय सेठ ने केवल 22 वर्ष की आयु में यूपीएससी की परीक्षा पास की। ये कर्नाटक कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वर्त्तमान में बैंगलोर मैट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक है। यह जिम्मेदारी इन्हें जुलाई 2018 को दी गई।

हिंदी , अंग्रेजी और कन्नड़ भाषा के जानकार अजय सेठ का जन्म 30 जून 1965 को उत्तर प्रदेश में हुआ। ये बचपन से ही मेधावी थे।इनके जवाबदेह कार्यशैली और शानदार गवर्नेंस की पहली छाप मैसूर में उपायुक्त के पद पर पोस्टिंग के समय पड़ी। मैसूर से बेल्लारी और फिर 2001 में ये केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर फाइनेंस मिनिस्ट्री आ गए। यहां इनका कार्यकाल 7 वर्षो का रहा। इनके तत्कालीन सहयोगियों ने बताया कि वित्त विभाग की इनकी समझ है और इस लिए इन्हें 2004 में चार वर्ष की फॉरेन पोस्टिंग पर सलाहकार पद पर एशियन डेवलपमेंट बैंक, मनीला भेजा गया। इन्होंने ऊर्जा के विषय में यूएसए से ट्रेनिंग भी ली है।

फॉरेन पोस्टिंग से लौटने के बाद 2008 में कर्नाटक कैडर में वापस आए, जहां इनकी वित्तीय दक्षता का लाभ राज्य सरकार ने उठाते हुए इन्हें फाइनेंस डिपार्टमेंट का सचिव और फिर प्रधान सचिव नियुक्त किया, इस बीच अजय सेठ को स्टेट येवरेजस कारपोरेशन का प्रबंध निदेशक भी बनाया गया। ये 2013 से 2015 तक वाणिज्य कर विभाग के आयुक्त रहे। जब भी जवाबदेही मिली इन्होंने हर जगह अपनी दक्षता सिद्ध की।

बीएमआरसीएल के एमडी बनाए जाने से पहले ये राज्य में हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत थे। अजय सेठ की छवि इमानदार के साथ साथ जुझारू ब्यूरोक्रेट की भी है, जो किसी ग़लत के सामने झुकना नहीं जानते।

FAME INDIA

अन्य प्रमुख नाम:

रजनीश गोयल
विनी महाजन
राजेश वर्मा
नीरव कुमार प्रसाद
लीना नंदन

(इस श्रेणी के सभी प्रमुख ब्यूरोक्रेटस की पूरी प्रोफाइल fameindia.co पर पब्लिश की जा रही है।)

फेम इंडिया मैगज़ीन- एशिया पोस्ट के प्रमुख मापदंड:

- दूरदर्शिता - ✓
- उत्कृष्ट सोच - ✓
- जवाबदेह - ✓
- गंभीरता - ✓
- शानदार गवर्नेंस - ✓
- व्यवहार कुशलता - ✓
- फैसला लेने की क्षमता - ✓

इन सात मुख्य बिंदुओं पर किये गये वार्षिक सर्वे 'असरदार ब्यूरोक्रेट्स-2019' में अजय सेठ प्रमुख स्थान पर हैं।

सर्वे स्रोत :- विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की राय पर आधारित

कामयाब ब्यूरोक्रेट हैं राजेश खुल्लर

कामयाब ★★★★★

1988 बैच के आईएएस अधिकारी राजेश खुल्लर की गिनती हरियाणा के सबसे योग्य और पॉवरफुल अधिकारियों में होती है। ये मुख्यमंत्री मनोहरलाल के प्रधान सचिव हैं और इन्हें प्रदेश में लगभग सभी प्रमुख कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी गयी है। इन्हें एक साथ 22 विभाग सौंपे गये। हालांकि मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के तौर पर आने से पहले हरियाणा आने से पहले ये केंद्र सरकार की प्रतिनियुक्ति पर ही थे। हरियाणा में पारदर्शिता व्यवस्था इन्होंनें बनाई है।

पंजाब विश्वविद्यालय से भौतिक शास्त्र में एमएससी कर चुके खुल्लर ने सरकारी सेवा में आने के बाद टोक्यो के ग्रिप्स से लोक प्रशासन में भी मास्टर्स डिग्री हासिल की। ये हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी के साथ ही संस्कृत भाषा के भी अच्छे जानकार हैं। इन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग और फिर हरियाणा सरकार के कृषि विभाग में निदेशक के तौर पर कार्य किया। कृषि के क्षेत्र में इनके कार्यकाल के दौरान, हरियाणा गेहूं के उत्पादकता के मामले में पंजाब को पछाड़ते हुए भारत का पहले नंबर का राज्य बन गया और वर्षों तक इस पोजीशन को बनाये रखा। ये सोनीपत, रोहतक के जिलाधिकारी भी रहे हैं, ये आधारभूत सुविधाओं और जनसाधारण उपयोगी कार्यक्रमों को जिले में लागू करने में सफल रहे और दोनों ही शहरों की कायापलट कर दी। हरियाणा में प्रशासनिक पारदर्शिता इनकी सबसे महत्त्वपूर्ण कामयाबी है।

केंद्र सरकार में राजेश खुल्लर वित्त मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी रह चुके हैं जहां ये राष्ट्रीय स्तर पर पीपीपी और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दों पर कार्यरत थे। इन्होंने राज्य सरकार में विभिन्न पदों पर काम किया है जैसे निदेशक (जनसंपर्क विभाग, हरियाणा), प्रबंध निदेशक (हरियाणा पर्यटन निगम), आयुक्त (फरीदाबाद नगर निगम), और बाद में गुड़गांव शहर। फरीदाबाद में इनके द्वारा चलाये ग्रीन ट्रांसपोर्ट मोड के लिए भारत सरकार द्वारा जेएल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन के तहत उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सन् 2008 में इन्होंने एचआईवी के डर और सामाजिक वर्जनाओं पर एक दिलचस्प किताब वाइरल मैच भी लिखी जो काफी चर्चित किताब रही।

हरियाणा सरकार की कमान संभालने के बाद राजेश खुल्लर ने प्रदेश में ऐतिहासिक रूप से विकास की बयार बहाई है। इन्होंने भ्रष्टाचार की जड़ माने जाने वाले तीन प्रमुख क्षेत्रों भर्ती, बदली और सीएलयू (लैंड ययूज के परिवर्तन) को पूरी तरह कंप्युटराइज्ड करवा दिया। इन्होंने पूर्व की सरकारों की पर्ची सिस्टम के विपरीत एक ऐसी पारदर्शी व्यवस्था बनवायी है जिसमें किसी को ट्रांसफर करवाने से लेकर बीपीएल राशन कार्ड बनवाने तक के लिये किसी अधिकारी या कर्मचारी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है।

अन्य प्रमुख नामः

तरूण बजाज
एन वी जयंती
अमिताभ जोशी
के राजेश्वर राव
शालनी मिश्रा

(इस श्रेणी के सभी प्रमुख ब्यूरोक्रेटस की पूरी प्रोफाइल fameindia.co पर पब्लिश की जा रही है।)

फेम इंडिया मैगजीन- एशिया पोस्ट के प्रमुख मापदंडः

- दूरदर्शिता - ✓
- उत्कृष्ट सोच - ✓
- जवाबदेह - ✓
- गंभीरता - ✓
- शानदार गवर्नेंस - ✓
- व्यवहार कुशलता - ✓
- फैसला लेने की क्षमता - ✓

इन सात मुख्य बिंदुओं पर किये गये वार्षिक सर्वे 'असरदार ब्यूरोक्रेट्स -2019' में राजेश खुल्लर प्रमुख स्थान पर हैं।

सर्वे स्रोत :- विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की राय पर आधारित

FAME INDIA

वाइब्रेंट गुजरात के योजनाकार रहे हैं अरविंद कुमार शर्मा

अनुभवी

★★★★★

सरल व्यक्तित्व के धनी 57 वर्षीय अरविंद कुमार शर्मा को प्रधानमंत्री कार्यालय का एक मजबूत स्तंभ माना जाता है। वर्तमान में प्रधानमंत्री कार्यालय नई दिल्ली में एडिशनल सेक्रेटरी अरविंद कुमार शर्मा 1988 बैच के गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। पालिटिकल साइंस में फर्स्ट क्लास से मास्टर डिग्री प्राप्त ब्यूरोक्रेट शर्मा का जन्म उत्तरप्रदेश के आज़मगढ़ में 11अप्रैल 1962 को हुआ।

वैसे तो इनके नाम कई सफलताएं दर्ज है जिनमें टाटा नैनो को गुजरात लाने, प्रदेश में निवेश और वाइब्रेंट गुजरात समिट के आयोजनों में इनकी भूमिका को प्रमुख माना जाता है। इन्होंने आस्ट्रेलिया से मास्टर आफ पब्लिक पॉलिसी और यूएसए से स्ट्रक्चरिंग टैरीफ की ट्रेनिंग भी ली है। इन्होंने आईं आई एम, बैंगलोर से मैनेजमेंट आफ इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोर्स भी किया हुआ है।

वर्ष 1989 में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के तौर पर इनकी पहली पोस्टिंग हुई। 1995 में ये मेहसाणा के कमिश्नर बनाए गए। इन्होंने विभिन्न विभागों में अपनी बेहतर कार्यक्षमता और शानदार गवर्नेंस का परिचय दिया। गुजरात में जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बने और उन्हे सचिव के तौर पर एक बेहद ही सुलझा हुआ ब्यूरोक्रेट चाहिए था। तब नरेंद्र मोदी ने 2001 में समझदार और दूरदर्शी अरविन्द कुमार शर्मा को मुख्यमंत्री कार्यालय में सचिव के तौर पर जिम्मेदारी दी। ये जनवरी 2006 तक इस पद पर रहे। वर्ष 2006 में अरविंद कुमार शर्मा ट्रेनिंग के लिए दस महीने के लिए विदेश गए। वहां से आने के बाद इन्हें पुनः मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया। वर्ष 2013 में पदोन्नति के बाद ये मुख्यमंत्री के एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाए गए। गुजरात इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड के सीईओ के तौर पर लम्बे समय तक काम करने वाले अरविंद कुमार शर्मा मोदी की विदेश यात्राओं का हिस्सा हुआ करते थे।

आम तौर पर 'एके' के नाम से जाने जाने वाले अरविंद कुमार शर्मा के बारे में मशहूर है कि ये वर्त्तमान प्रधानमंत्री के सबसे विश्वस्त ब्यूरोक्रट में एक है और पिछले 18 सालों से मोदी के भरोसेमंद बने हुए हैं।

जून 2014 से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर आने वाले अरविंद कुमार शर्मा प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव के तौर पर नियुक्ति किए गए, 2017 में पदोन्नति के साथ ये वर्त्तमान में प्रधानमंत्री कार्यालय में एडिशनल सेक्रेटरी है। इन्हें वित्त और फारेन अफेयर्स का विशेषज्ञ माना जाता है।

FAME INDIA

अन्य प्रमुख नामः

आई रानी कुमुदिनी
जितेंद्र नाथ सविन
अनुराधा मल्ल
टी वी एस एन प्रसाद
अली रज़ा रिज्वी

(इस श्रेणी के सभी प्रमुख ब्यूरोक्रेटस की पूरी प्रोफाइल fameindia.co पर पब्लिश की जा रही है।)

फेम इंडिया मैगज़ीन- एशिया पोस्ट के प्रमुख मापदंडः

- दूरदर्शिता - ✓
- उत्कृष्ट सोच - ✓
- जवाबदेह - ✓
- गंभीरता - ✓
- शानदार गवर्नेंस - ✓
- व्यवहार कुशलता - ✓
- फैसला लेने की क्षमता - ✓

इन सात मुख्य बिंदुओं पर किये गये वार्षिक सर्वे 'असरदार ब्यूरोक्रेट्स -2019' में अरविंद कुमार शर्मा प्रमुख स्थान पर हैं।

सर्वे स्रोत :- विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की राय पर आधारित

मजबूत इच्छाशक्ति वाले ब्यूरोक्रेट हैं भगवान शंकर

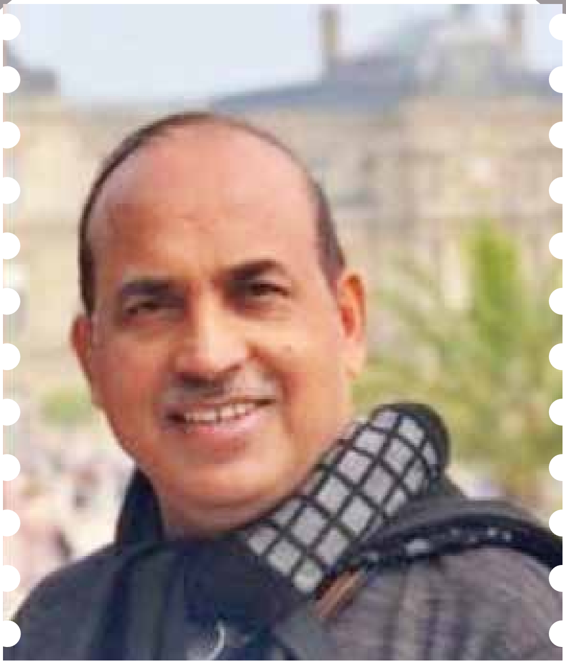

मजबूत

सिक्किम कैडर के 1988 बैच के ब्यूरोक्रेट भगवान शंकर को पावर कारिडोर में एक समझदार और बेहद जानकार आईएएस अधिकारी माना जाता है। आईआईटी कानपुर से सिविल इंजीनियरिंग में बी-टेक में अव्वल करने के बावजूद भगवान शंकर के मन में जनसामान्य के लिए काम करने की इच्छा थी, और यही इन्हें सिविल सर्विसेज की ओर खिंच लाई, इन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स भी किया है।

वर्तमान में सिक्किम सरकार की ओर से दिल्ली में पदस्थापित है और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के तौर पर इनकी जवाबदेही राज्य के विकास के लिए राज्य सरकार और केंद्र के बीच समन्वय का है। केंद्र एंव राज्य सेवा में 31 वर्षों से महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे भगवान ने सबडिविजनल मजिस्ट्रेट के तौर पर अपना सफर शुरू किया था। गैंगटोक एडीएम के बाद ये साउथ सिक्किम के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाए गए, बताया जाता है कि इस दौरान इन्होंने साउथ सिक्किम के विकास में बहुत कार्य किया। 1998 में इन्हें इंटर स्टेट डेप्यूटेशन पर उत्तर प्रदेश भेजा गया, जो कार्यकाल पांच साल का रहा, इस दौरान इन्होंनें महाराजगंज, सोनभद्र के जिलाधिकारी के साथ ही कई विभागों में महत्त्वपूर्ण पदों पर योगदान दिया। इन्हें जानने समझने की जिज्ञासा वाला ब्यूरोक्रेट माना जाता है, जिस वजह से इन्होंने देश विदेश के विभिन्न संस्थानों से समय समय पर कई ट्रेनिंग और स्पेशल कोर्स किए हैं, जिनमें यूनाईटेड किंगडम से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लिडरशिप एंड स्ट्राटेजिक ट्रेनिंग, यूएसए से फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आईसीसीजी से इथिक इन पब्लिक सर्विस, टीआईएसएस से सोशल पालिसी एंड गवर्नेंस के साथ समय समय पर आईआईएम, बैंगलोर, आईआईएफटी नई दिल्ली से की गई कोर्स और ट्रेनिंग महत्वपूर्ण रहे हैं।

इन्होंने राज्य सरकार में कई विभागों में एडिशनल सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी सहित सेक्रेटरी के पद पर भी कार्य किया है। हर जगह इन्होंने अपने उत्कृष्ट कार्यशैली की छाप छोड़ी, मिल्क यूनियन और स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम के प्रबंध निदेशक भी रहे। इन्होंनें केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है जिनमें संयुक्त सचिव के तौर पर गृहमंत्रालय में इनके कार्य की सराहना इनके सहयोगी भी करते हैं। भगवान शंकर को भारत के राष्ट्रपति द्वारा वर्ष 2013 में सेंशश में विशिष्ट कार्य के लिए रजत पदक से सम्मानित किया गया। मजबूत इच्छाशक्ति वाले भगवान शंकर को व्यवहार कुशल और दूरदर्शी ब्यूरोक्रेट माना जाता है।

अन्य प्रमुख नाम:

तरूण बजाज
एन वी जयंती
अमिताभ जोशी
के राजेश्वर राव
शालनी मिश्रा

(इस श्रेणी के सभी प्रमुख ब्यूरोक्रेटस की पूरी प्रोफाइल fameindia.co पर पब्लिश की जा रही है।)

फेम इंडिया मैगजीन- एशिया पोस्ट के प्रमुख मापदंड:

- दूरदर्शिता - ✓
- उत्कृष्ट सोच - ✓
- जवाबदेह - ✓
- गंभीरता - ✓
- शानदार गवर्नेंस - ✓
- व्यवहार कुशलता - ✓
- फैसला लेने की क्षमता - ✓

इन सात मुख्य बिंदुओं पर किये गये वार्षिक सर्वे 'असरदार ब्यूरोक्रेट्स -2019' में भगवान शंकर प्रमुख स्थान पर हैं।

सर्वे स्रोत :- विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की राय पर आधारित

FAME INDIA

केरल की बेहतर अर्थव्यवस्था की जिम्मेदारी हैं मनोज जोशी पर

जिम्मेदार
★★★★★

केरल के वित्त सचिव मनोज जोशी को राज्य सरकार ने अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी दी गई है और 52 वर्षीय जोशी उस पर पूर्णत: खरे उतरे। केवल 22 वर्ष की आयु में यूपीएससी की परीक्षा पास करने वाले मनोज जोशी राजस्थान के रहने वाले हैं। वर्ष 1989 में इन्हें केरल कैडर मिला। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने वाले मनोज को एक सुलझा हुआ ब्यूरोक्रेट माना जाता है।

फाइनेंस की बेहतर समझ रखने वाले मनोज जोशी का अबतक का ज्यादातर कार्यकाल वित्त, उद्योग और वाणिज्य से जुड़े विभागों में रहा है। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट में पहली पोस्टिंग के बाद इनकी नियुक्ति डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर में जेनरल मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर इंस्टिच्युशनल फाइनेंस और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के तौर पर हुई। 1999 में इन्हें केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया, जहां से 2004 में इन्हें चार वर्षों के लिए फारेन पोस्टिंग पर वाशिंगटन डीसी स्थित कामर्स एम्बेसी में काउंसलर नियुक्त किया गया। वहां से लौटने के बाद ये केरल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए।

2008 से 2011 तक इन्होंने विभिन्न विभागों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई जिनमें मुख्यमंत्री के सेक्रेटरी से लेकर पीडब्ल्यूडी, पोर्ट सहित कई विभाग शामिल थे। वर्ष 2012 में पुन: ये केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर पांच साल के लिए गए। जिसमें इन्होंने ज्वाइंट सेक्रेटरी के तौर पर डीओपीटी, फाइनेंस और एमएसएमई में कई महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

2017 में कैडर में लौटने के बाद से ही इन्हें वित्त विभाग से जोड़ दिया गया और इनके नेतृत्व में केरल देश के सभी राज्यों से वित्तीय विकास में अव्वल बन गया है।

इन्होंने स्विटजरलैंड से कामर्स में डब्लूयटीओ की ट्रेनिंग की है साथ ही आइआइएम, बैंगलोर से ई गवर्नेंस अपर्चूनिटी एंड चैलेंज का कोर्स भी किया है। इन्हें शानदार गवर्नेंस और दूरदर्शी सोच का असरदार ब्यूरोक्रेट माना जाता है

अन्य प्रमुख नाम:

जी अशोक राव
वीरा राणा
अनिता प्रवीण
लोक रंजन
विवेक कुमार सिंह

(इस श्रेणी के सभी प्रमुख ब्यूरोक्रेटस की पूरी प्रोफाइल fameindia.co पर पब्लिश की जा रही है।)

फेम इंडिया मैगज़ीन- एशिया पोस्ट के प्रमुख मापदंड:

- दूरदर्शिता - ✓
- उत्कृष्ट सोच - ✓
- जवाबदेह - ✓
- गंभीरता - ✓
- शानदार गवर्नेंस - ✓
- व्यवहार कुशलता - ✓
- फैसला लेने की क्षमता - ✓

इन सात मुख्य बिंदुओं पर किये गये वार्षिक सर्वे 'असरदार ब्यूरोक्रेट्स -2019' में मनोज जोशी प्रमुख स्थान पर हैं।

सर्वे स्रोत :- विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की राय पर आधारित

FAME INDIA

नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की रणनीतिकार रही हैं शुभ्रा सिंह

शक्ति

नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (एनपीपीए) की वर्तमान चैयरमैन शुभ्रा सिंह की गिनती पॉवर कॉरिडोर में समझदार महिला आईएएस अधिकारी के तौर पर होती है। साथ ही इन्हें इनके सहयोगी सौम्य और अनुशासन प्रिय मानते है। 2013 में रजत पदक से भारत के राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित शुभ्रा सिंह राजस्थान कैडर की 1989 बैच की आईएएस है। मूल रूप से उत्तरप्रदेश के मेरठ की रहने वाली है। वर्तमान में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं।

पालिटिकल साइंस में फर्स्ट डिवीजन से पोस्ट ग्रेजुएट शुभ्रा ने शुरुआत में ही सिविल सर्विस को अपना गंतव्य निर्धारित कर लिया था।

करौली में कलेक्टर के तौर पर हो या स्पेशल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, सेक्रेटरी डेयरी डेवलपमेंट एंड फिशरी डिपार्टमेंट या फिर कमिश्नर डीपीईपी इन्होंने हर पद पर बेहतर नतीजे दिए। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भी इन्होंने सदैव अच्छा कार्य किया। 2011 में राजस्थान के सेंसेक्स आपरेशन में बेहतर प्रदर्शन के लिए ही इन्हें राष्ट्रपति द्वारा रजत पदक दिया गया था। शुभ्रा सिंह के पास प्रो-इंडस्ट्री क्रेडेंशियल्स हैं, इसलिए सेंट्रल डेप्यूटेशन पर मिनिस्ट्री ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज में इन्हें ज्वाइंट सेक्रेटरी डीआईपीपी और फिर एक्जक्यूटीव डायरेक्टर इंडिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन की महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। इनके पूर्व के कार्यो और किये गए महत्त्वपूर्ण फैसलों के अनुभव को देखते हुए इन्हें नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग आथरिटी की महत्त्वपूर्ण भूमिका सौंपी गई। इन्होंने नियुक्ति के साथ ही कई चुनौतियों का सफलतापूर्वक समाधान निकाला। मार्च 2019 में 42 कैंसर रोधी दवाओं के लिए ट्रेड मार्जिन कम करवा कर उपभोक्ताओं को लगभग 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा की राहत दिला कर मानवीय मूल्यों की उत्कृष्टता का सबूत दिया।

संवेदनशील और कुशल व्यवहार की धनी शुभ्रा सिंह मीडिया फ्रेंडली और खुलकर अपनी बात रखने के लिए भी जानी जाती है।

इन्होंने यूएसए से प्राइवेट हेल्थ केयर डेवलपिंग सक्सेसफुल एंड प्रोग्राम के साथ ही युनाईटेड किंगडम से कैम्ब्रिज लिडरशीप एंड स्ट्रेटेजिक थिंकिंग प्रोग्राम की भी ट्रैनिंग की है। इसके अलावा अपनी प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाने के लिए समय समय पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फारेन ट्रेड, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पालिसी और अन्य संस्थानों से कई कोर्स एंव ट्रेनिंग करती रही है। दूरदृष्टि और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता इन्हें असरदार ब्यूरोक्रेट्स बनाती है।

अन्य प्रमुख नाम:

संजय आर भूषणरेड्डी
मो नसीमुद्दीन
अरूण कुमार
देवेंद्र कुमार सिंह
एडवीना कुलभूषण माझी

(इस श्रेणी के सभी प्रमुख ब्यूरोक्रेटस की पूरी प्रोफाइल fameindia.co पर पब्लिश की जा रही है।)

फेम इंडिया मैगजीन- एशिया पोस्ट के प्रमुख मापदंड:

- दूरदर्शिता - ✓
- उत्कृष्ट सोच - ✓
- जवाबदेह - ✓
- गंभीरता - ✓
- शानदार गवर्नेंस - ✓
- व्यवहार कुशलता - ✓
- फैसला लेने की क्षमता - ✓

इन सात मुख्य बिंदुओं पर किये गये वार्षिक सर्वे 'असरदार ब्यूरोक्रेट्स -2019' में शुभ्रा सिंह प्रमुख स्थान पर हैं।

सर्वे स्रोत :- विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की राय पर आधारित

FAME INDIA

सूझबूझ के साथ लेखनी के भी धनी हैं के.श्रीनिवास

विकासशील

गुजरात कैडर के आईएएस श्रीनिवास रामास्वामी कातिकिथाला (के श्रीनिवास) को अध्ययनशील और कर्मठ अधिकारी माना जाता है। ये करीब दो वर्षों से देश भर के आईएएस अधिकारियों को नियंत्रित करने वाले विभाग डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग में बतौर ऐडिशनल सेक्रेटरी पदस्थापित हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे तो ये प्रदेश के पर्सनल विभाग के सचिव थे। इन्हें मोदी के करीबी अधिकारियों में माना जाता है।

12 जुलाई 1967 को हैदराबाद में जन्मे व पले-बढ़े के श्रीनिवास पढ़ाई में काफी तेज थे। हैदराबाद युनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने गुलबर्गा युनिवर्सिटी से एलएलबी और गुंटूर के आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय से कॉन्सटिच्युनल लॉ में एलएलएम किया। इसके अलावा इन्होंने हैदराबाद से ही इकोनॉमिक्स में डिसटिंक्शन के साथ डिप्लोमा भी हासिल किया है। सेवा में आने के बाद इन्होंने नॉर्थ कैरोलीना के ड्यूक युनिवर्सिटी से इंटनेशनल डेवलपमेंट पॉलिसी में मास्टर्स डिग्री भी ली।

1989 बैच में आईएएस में चयन के बाद पोरबंदर के असिसस्टेंट कलेक्टर के तौर पर नौकरी शुरू की थी। राजकोट, साबरकांठा और अहमदाबाद में प्रशासन की कमान संभाली और ये हाउसिंग, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण व मेडिकल एजुकेशन आदि विभागों से भी जुड़े रहे। वर्ष 2004 से 2009 तक ये गुजरात अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरशन के मैनेजिंग डायरेक्टर रहे। इस दौरान प्रदेश भर में कई महानगरों को योजनाबद्ध तरीके से बसाया गया। कहते हैं इस दौरान पूरे प्रदेश का जीर्णोद्धार हुआ और हर शहर किसी महानगर की तरह चमक-दमक से भर गया। वर्ष 2009 से 2012 तक ये सरदार सरोवर नर्मदा निगम के ज्वाइंट एमडी रहे।

वर्ष 2012 से 2015 तक ये गुजरात के पर्सनल विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे। वर्ष 2015 से 2017 में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने से पहले तक ये रेवेन्यु विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाये गये। ये वर्ष 2017 में प्रकाशित 'गुजरात के लैंड रेवेन्यु ऐडमिनिस्ट्रेशन का सारांश' नामक दस्तावेजी पुस्तक के प्रधान संपादक भी रहे। ये सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट के सचिव भी बने और इस दौरान सरदार पटेल से जुड़े दस्तावेजों को संकलित करने का कार्य किया। इस संकलन को सरदार पटेल के शताब्दी समारोह पर प्रकाशित किया गया था।

अन्य प्रमुख नाम:

सुमिता मिश्रा
संजीव चोपड़ा
अनिरुद्ध तिवारी
मनीष पवार
राम प्रकाश सिसोदिया

(इस श्रेणी के सभी प्रमुख ब्यूरोक्रेटस की पूरी प्रोफाइल fameindia.co पर पब्लिश की जा रही है।)

फेम इंडिया मैगज़ीन- एशिया पोस्ट के प्रमुख मापदंड:

- दूरदर्शिता - ✓
- उत्कृष्ट सोच - ✓
- जवाबदेह - ✓
- गंभीरता - ✓
- शानदार गवर्नेंस - ✓
- व्यवहार कुशलता - ✓
- फैसला लेने की क्षमता - ✓

इन सात मुख्य बिंदुओं पर किये गये वार्षिक सर्वे 'असरदार ब्यूरोक्रेट्स -2019' में के श्रीनिवास प्रमुख स्थान पर हैं।

सर्वे स्रोत :- विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की राय पर आधारित

लोकप्रिय ब्यूराक्रेट रहे हैं अनुराग जैन

लोकप्रिय

अपनी दूरदर्शिता और कार्यकुशलता से लोहा मनवाने वाले अधिकारी के तौर पर मशहूर अनुराग जैन मध्य प्रदेश सरकार में अपर मुख्य सचिव हैं। चाहे किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, अनुराग जैन की महत्ता और लोकप्रियता हमेशा बरकरार रही। ये अपने कार्यों के दम पर हर सरकार के लिये पहली पसंद बने रहे।

अनुराग जैन मूल रूप से मध्य प्रदेश के निवासी हैं। ये आईआईटी खड़गपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में बीटेक कर चुके हैं। सेवा में आने के बाद इन्होंने अमेरिका के मैक्सवेल स्कूल ऑफ सिरैक्यूज़ से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में गोल्ड मेडल के साथ मास्टर्स की डिग्री हासिल की। इन्होंने मध्य प्रदेश के मंडला, मंदसौर और भोपाल में कलेक्टर के रूप में कार्य किया। मध्य प्रदेश में ये स्वास्थ्य विभाग में आयुक्त थे और सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव भी थे। अनुराग जैन कार्य के प्रति समर्पित भरोसेमंद अफसरों में गिने जाते थे। उनके पहले और दूसरे कार्यकाल में लगभग पांच साल तक जैन सीएम के सचिव पद पर रहे। मध्यप्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की लाडली लक्ष्मी योजना और राज्य की सबसे अहम "पब्लिक सर्विस डिलेवरी गारंटी एक्ट" के योजनाकार इन्हें ही माना जाता है।

अनुराग जैन जिस विभाग में रहे वहां इन्होंने अपने कार्यों से खुद को साबित किया। वर्ष 2015 में पीएमओ में जवाइंट सेक्रेटरी बनने से पहले ये केंद्रीय वित्त मंत्रालय में इसी पद पर थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी जनधन खाता योजना का कॉन्सेप्ट बनाने से लेकर कार्यरूप देने तक में अनुराग जैन की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। ये एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक के एमडी और नेशनल हाउसिंग बैंक और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी सहित कई संस्थाओं के बोर्ड मेम्बर भी रहे हैं। वर्तमान कमलनाथ सरकार में भी इन्हें ईमानदार अफसर माना जाता है। अपने ताजा कार्यकाल के दौरान सरकार की फाइनैंशियल प्लानिंग और कई योजनाओं के क्रियान्वयन में इन्होंने अच्छी भूमिका अदा की हैं। इन्होंने निजी उपलब्धियों के कारण और संस्थानों के प्रमुख के तौर पर कई पुरस्कार प्राप्त किया है।

अन्य प्रमुख नाम:

आनंद मधुकर लिमेय
प्रदीप कुमार जेना
रवनीत कौर
विजय कुमार जंजुआ
के राजा रमण

(इस श्रेणी के सभी प्रमुख ब्यूरोक्रेटस की पूरी प्रोफाइल fameindia.co पर पब्लिश की जा रही है।)

फेम इंडिया मैगजीन- एशिया पोस्ट के प्रमुख मापदंड:

दूरदर्शिता - ✓
उत्कृष्ट सोच - ✓
जवाबदेह - ✓
गंभीरता - ✓
शानदार गवर्नेंस - ✓
व्यवहार कुशलता - ✓
फैसला लेने की क्षमता - ✓

इन सात मुख्य बिंदुओं पर किये गये वार्षिक सर्वे 'असरदार ब्यूरोक्रेट्स -2019' में अनुराग जैन प्रमुख स्थान पर हैं।

सर्वे स्रोत :- विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की राय पर आधारित

कर्मयोद्धा अधिकारी हैं भूषण ए गगराणी

कर्मयोद्धा

महाराष्ट्र के आईएएस अधिकारी भूषण अशोक गगराणी एक डायनमिक, जोशीले आईएएस अधिकारी हैं। ये 1990 बैच के महाराष्ट्र कैडर के अधिकारी हैं और अबतक ये जहां भी रहे, वहां अपनी ऊर्जा से माहौल को जीवंत बना कर रखा। मई 2018 में इस पद पर आने से पूर्व ये सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर पद पर थे। 25 मार्च 1966 में महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ।

शानदार गवर्नेंस और उत्कृष्ट कार्यशैली से पहचान कायम करने वाले गगराणी ने सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, चंद्रपुर के रूप में कैरियर की शुरुआत से ही अपने कार्यशैली की छाप छोड़ी। इसके बाद इन्हें जब भी जहां भी पोस्टिंग दी गई, इन्होंने कर्त्तव्यनिष्ठा से अपनी अलग पहचान बनायी। ये सिडको के उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सीईओ रहे हैं। ये राज्य के हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मेडिकल एजुकेशन एंड ड्रग के साथ ही टूरिज्म डिपार्टमेंट के भी सेक्रेटरी भी रहे हैं। औरंगाबाद, पुणे, सिंधू दुर्ग हर पदस्थापना पर इनकी कार्यनिष्ठा स्पष्ट नजर आयी। भूषण गगराणी का अब तक का पूरा कार्यकाल इनके कैडर में ही रहा है। ये कभी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर नहीं गये।

गगराणी की विशेषता यह भी है कि हमेशा खुद को अपडेट रखते हैं। दो विषयों में मास्टर डिग्री प्राप्त भूषण अशोक गगराणी ने दक्षता और कार्यकुशलता बनाए रखने के लिए समय समय पर कई ट्रेनिंग और कोर्स किया है, जिनमें नीदरलैंड और यूनाईटेड किंगडम से पब्लिक ऐडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कैपिटल मार्केट्स से फाइनैंशियल मार्केट रेगुलेशन, आईसीसीजी से इथिक इन पब्लिक गवर्नेंस जैसे महत्त्वपूर्ण कोर्स शामिल हैं।

मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा के जानकार और जानदार पर्सनैलिटी के स्वामी भूषण अशोक गगराणी एक अच्छे वक्ता भी हैं और इन्होंने समय-समय पर निवेशकों और उद्यमियों के सामने सरकार के प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन बेहद प्रभावशाली ढंग से रखने और इन्हें प्रभावित करने में सफलता पायी है। सिडको ने जब नवी मुंबई एयरपोर्ट इंफ्लुएंस नोटिफाइड एरिया को डेवलप किया तो इनके एक प्रेजेंटेशन ने अरबों रुपये का निवेश करवाने में सफलता हासिल की। ये अक्सर महाराष्ट्र के प्रतियोगी छात्रों का भी हौसला बढ़ाते रहे हैं। इन्हें एक ऐसे अधिकारी के तौर पर जाना जाता है जो सही का सम्मान और गलत के विरोध करने में समय नहीं लगाते।

अन्य प्रमुख नाम:

विजय भूषण पाठक
डॉ रजत भार्गव
के एस जवाहर रेड्डी
ज्योति कलश
गंजी कमल वी राव

(इस श्रेणी के सभी प्रमुख ब्यूरोक्रेटस की पूरी प्रोफाइल fameindia.co पर पब्लिश की जा रही है।)

फेम इंडिया मैगज़ीन- एशिया पोस्ट के प्रमुख मापदंड:

- दूरदर्शिता - ✓
- उत्कृष्ट सोच - ✓
- जवाबदेह - ✓
- गंभीरता - ✓
- शानदार गवर्नेंस - ✓
- व्यवहार कुशलता - ✓
- फैसला लेने की क्षमता - ✓

इन सात मुख्य बिंदुओं पर किये गये वार्षिक सर्वे 'असरदार ब्यूरोक्रेट्स -2019' में भूषण अशोक गगराणी प्रमुख स्थान पर हैं।

सर्वे स्रोत :- विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की राय पर आधारित

FAME INDIA

भ्रष्टाचार के खिलाफ बेहद जज्बाती हैं जितेंद्र नारायण

जज्बा

1990 बैच के आईएएस अधिकारी जितेंद्र नारायण की पहचान एक ऐसी शख्सियत की है जिसने अपनी दूरदर्शिता व योग्यता से हर जगह सुधारवादी मुहिम छेड़ी और कामयाब रहे। जितेंद्र नारायण लंबे अरसे तक दिल्ली और केंद्र सरकार में विभिन्न पदों पर तैनात रहे। अरुणाचल सरकार की तरफ से भी इन्हें दिल्ली में ही पदस्थापित किया गया है।

बिहार के बेगूसराय में प्रतिष्ठित राय बहादुर परिवार में 19 अक्टूबर 1966 को जन्मे जितेंद्र नारायण की स्कूली शिक्षा दार्जिलिंग के सेंट पॉल स्कूल में हुई। दिल्ली के सेंट स्टीफन्स कॉलेज के छात्र रहे नारायण ने इतिहास में बीए व एमए किया। ये 1 जुलाई 1990 को भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल हुए और इन्हें केंद्र शासित प्रदेश कैडर प्राप्त हुआ।

दिल्ली में इनकी पोस्टिंग सदैव भ्रष्टाचारियों और इन्हें संरक्षण देने वाले राजनेताओं के लिये चिंता का विषय रही। कई दशक पहले चंद्रास्वामी के आश्रम पर रेड करने वाले हिम्मती अधिकारी के तौर पर इनकी पहचान बनी। शीला दीक्षित के मुख्यमंत्रित्व काल में इन्होंने कुछ हाई-प्रोफाइल एडॉप्शन हाउसों पर छापा मार कर सनसनी फैला दी थी। जब इन्हें दिल्ली नगर निगम भेजा गया तो इन्होंने गाजीपुर स्लॉटर हाउस के टेंडर में कड़ाई से पारदर्शिता लागू कर भ्रष्टाचारियों की नाक में दम कर दिया। इन्होंने श्रम कानूनों का उल्लंघन करने वाली दिल्ली की एक बड़ी बिल्डर कंपनी को सील कर दिया। एक पावरफुल पूर्व केंद्रीय खाद्य मंत्री के समय इन्होंने 11800 करोड़ रुपये के कंप्युटराइज्ड टीपीडीएस टेंडर को महज 300 करोड़ में एनआईसी को देने की सिफारिश कर तहलका मचा दिया था।

27 वर्ष के सेवाकाल के दौरान जितेंद्र नारायण ने बेहतरीन योजनाकार और नीति-निर्माता के रूप में प्रशासनिक हलकों में अपनी विशेष पहचान स्थापित कर लिया हैं। ये दिल्ली के शुरुआती प्रशासनिक अधिकारियों में से थे जिन्होंने राजधानी को नौ जिलों में बांटने में अहम भूमिका निभायी। अंडमान के नील द्वीपसमूह में पहली बार मतदाता पहचान पत्र शुरू करने का काम इन्होंने ही शुरू करवाया। इन्हें प्रतिष्ठित कॉमनवेल्थ एसोशिएसन फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट रिकॉगजानेशन भी प्राप्त हो चुका है। इनके ऑफिस मैनेजमेंट 'कर्मोदय' को भारत सरकार के प्रशासनिक विभाग ने सर्वश्रेष्ठ प्रणालियों में से माना।

अन्य प्रमुख नाम:

- के के पाठक
- अरूण कुमार सोलंकी
- गौरव गुप्ता
- विनित गर्ग
- डॉ जी अनुपमा

(इस श्रेणी के सभी प्रमुख ब्यूरोक्रेटस की पूरी प्रोफाइल fameindia.co पर पब्लिश की जा रही है।)

फेम इंडिया मैगजीन- एशिया पोस्ट के प्रमुख मापदंड:

- दूरदर्शिता - ✓
- उत्कृष्ट सोच - ✓
- जवाबदेह - ✓
- गंभीरता - ✓
- शानदार गवर्नेंस - ✓
- व्यवहार कुशलता - ✓
- फैसला लेने की क्षमता - ✓

इन सात मुख्य बिंदुओं पर किये गये वार्षिक सर्वे 'असरदार ब्यूरोक्रेट्स -2019' में जितेंद्र नारायण प्रमुख स्थान पर हैं।

सर्वे स्रोत :- विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की राय पर आधारित

FAME INDIA

बेहतर कार्ययोजनाओं से बनाई अलग पहचान अल्केश कुमार शर्मा ने

बेहतर
★★★★★

कोच्चि मेट्रो के नवनियुक्त मैनेजिंग डायरेक्टर अल्केश कुमार शर्मा ऐसे जानकार व कुशल प्रबंधक के तौर पर जाने जाते हैं जो किसी भी परियोजना में लगाये गये तो उसे सफलता पूर्वक पूरा कर दिखाया। पिछले चार वर्षों से ये दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरीडोर के सीईओ व मैनेजिंग डायरेक्टर थे। इन्हें केरल सरकार की ओर से बेस्ट सीईओ अवॉर्ड, सर्वश्रेष्ठ जिला जनगणना अधिकारी का राष्ट्रपति पदक और केरल सरकार का बेस्ट परफॉरमेंस पुरस्कार मिल चुका है।

राजस्थान के रहने वाले अल्केश शर्मा ने कृषि विज्ञान में गोल्ड मेडल के साथ ग्रेजुएशन किया है। ये रूरल मैनेजमेंट में एमबीए भी कर चुके हैं। 1990 बैच में केरल कैडर से जुड़ने के बाद इन्हें केरल सरकार के खाद्य आपूर्ति व पर्यटन विभाग से जुड़ने का मौका मिला। त्रिशूर व मलपुरम जिलों में जिलाधिकारी रहने के बाद ये एक बार फिर पर्यटन विभाग से जुड़े। इस बार पहले ये विभाग के निदेशक बने और फिर एडिशनल सेक्रेटरी। केरल को 'गॉड्स ओन कंट्री' के ब्रांड के तौर पर स्थापित करने में इनकी प्रमुख भूमिका रही और इनके कार्यकाल में प्रदेश को भारत सरकार व कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से बेस्ट टूरिज्म स्टेट का अवार्ड भी मिला।

अल्केश शर्मा की क्षमताओं को देखते हुए वर्ष 2004 में यूपीए वन सरकार के दौरान राज्य मंत्री बनी कुमारी शैलजा ने इन्हें बतौर निजी सचिव प्रतिनियुक्ति पर बुलाया। वर्ष 2007 में शर्मा को युनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का नेशनल प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया गया। वर्ष 2009 में ये केरल के उद्योग सचिव बने। वर्ष 2011 में संस्कृति विभाग से जुड़े फिर वर्ष 2012 में दोबारा केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर सड़क परिवहन मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी बने। वर्ष 2015 में केंद्रीय कॉमर्स मंत्रालय ने दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरीडोर बनाने की महत्वाकांक्षी परियोजना तैयार की तो अल्केश शर्मा को ही इसका सर्वेसर्वा बनाया गया। यहां इन्होंने प्रोजेक्ट का अधिकतर कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया है।

इनकी नयी जिम्मेदारी में कोच्चि मेट्रो के द्वितीय चरण में बहुचर्चित वॉटर मेट्रो लाने की घोषणा है। खास बात यह है कि कई कदमों को केंद्र सरकार से मंजूरी व फंड अभी तक नहीं मिली है जिसे तय समय-सीमा में लाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।

FAME INDIA

अन्य प्रमुख नाम:

मीता आर लोचन
संजय कुमार राकेश
अर्चना अग्रवाल
देव श्री मुखर्जी
सुमिता देवरा

(इस श्रेणी के सभी प्रमुख ब्यूरोक्रेटस की पूरी प्रोफाइल fameindia.co पर पब्लिश की जा रही है।)

फेम इंडिया मैगज़ीन- एशिया पोस्ट के प्रमुख मापदंडः

दूरदर्शिता - ✓
उत्कृष्ट सोच - ✓
जवाबदेह - ✓
गंभीरता - ✓
शानदार गवर्नेंस - ✓
व्यवहार कुशलता - ✓
फैसला लेने की क्षमता - ✓

इन सात मुख्य बिंदुओं पर किये गये वार्षिक सर्वे 'असरदार ब्यूरोक्रेट्स -2019' में अल्केश कुमार शर्मा प्रमुख स्थान पर हैं।

सर्वे स्रोत :- विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की राय पर आधारित

राजस्थान के पॉवर सेक्टर में क्रांति के अग्रदूत संजय मल्होत्रा

अग्रदूत
★★★★★

अगर राजस्थान के प्रशासन तंत्र और ब्युरोक्रैसी को करीब से जानने वालों से पूछा जाये कि प्रदेश के सबसे ऊर्जावान और कर्मठ अधिकारी का नाम बतायें तो दस में से कम से कम आठ लोग संजय मल्होत्रा का नाम सुझायेंगे। शायद यही कारण है कि सरकारों के बदलने के बावजूद इनकी लोकप्रियता और प्रभाव में कोई कमी नहीं आयी है। वर्तमान में राजस्थान सरकार के रेवेन्यु, कॉलोनाइजेशन व सैनिक कल्याण जैसे कई महत्त्वपूर्ण विभागों को संभाल रहे हैं राज्य के प्रिंसिपल सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा।

मूल रूप से राजस्थान के निवासी संजय मल्होत्रा आईआईटी कानपुर से कंप्युटर साइंस व इंजीनियरिंग में बीटेक रहे हैं। 1990 बैच में इन्होंने आईएएस चुनने वालों में टॉप किया और इन्हें पसंदीदा कैडर अपना गृह प्रदेश राजस्थान ही मिला। ये राजस्व, स्वास्थ्य और कृषि जैसे विभागों से जुड़े। जब 1999 में राजस्थान से तत्कालीन सांसद वसुंधरा राजे को वाजपेयी मंत्रिमंडल में जगह मिली तो इन्होंने इस डायनैमिक अधिकारी को दिल्ली बुलाकर अपने मंत्रालय में कार्यभार दिया। वर्ष 2003 में संजय मल्होत्रा को संयुक्त राष्ट्र डिवलपमेंट प्रोग्राम का प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर बनाया गया। वर्ष 2006 में इन्हें दोबारा प्रदेश में वित्त और राजस्व का विशेष सचिव और वर्ष 2007 में राजस्थान का कार्मिक सचिव बनाया गया। वर्ष 2008 -2009 में ये प्रिनेकशन युनिवर्सिटी से मास्टर इन पब्लिक पॉलिसी की डिग्री ली. फिर 2009 में वापस लौटे तो इन्हें माइन्स कारपोरेशन का कार्यभार मिला। वर्ष 2010 में इन्हें राज्य का आईटी सचिव बनाया गया। प्रदेश में कंप्युटरीकरण और ई-गवर्नेंस की दिशा में इन्होंने काफी कार्य किये।

वर्ष 2013 में संजय मल्होत्रा को कमिश्नर कामर्शियल टैक्स बनाए गए और वर्ष 2014 के अंत में पॉवर विभाग की कमान सौंपी गयी। इन्होंने ऊर्जा विभाग में बतौर प्रमुख सचिव बिजली कंपनियों में बेहतरीन कार्य किया। इनके कार्यकाल में बिजली उत्पादन में अच्छी बढ़ोत्तरी हुई। ये 4 साल से भी ज्यादा समय तक ऊर्जा विभाग में रहे। इनके कार्यकाल के दौरान प्रदेश में उदय स्कीम लागू की गयी और विद्युत कंपनियों का हजारों करोड़ों का घाटा कम हुआ। ऊर्जा क्षेत्र में इनके उल्लेखनीय कार्यों के लिये भारत सरकार ने इन्हें सेंट्रल बोर्ड फॉर इरीगेशन एंड पावर (सीबीआईपी) अवार्ड-2019 से नवाजा है।

अन्य प्रमुख नाम:

अनुराग रस्तोगी
आरती आहुजा
मनोज कुमार अग्रवाल
सी के अनिल
अपूर्व कुमार सिंह

(इस श्रेणी के सभी प्रमुख ब्यूरोक्रेटस की पूरी प्रोफाइल fameindia.co पर पब्लिश की जा रही है।)

फेम इंडिया मैगजीन- एशिया पोस्ट के प्रमुख मापदंड:

दूरदर्शिता - ✓
उत्कृष्ट सोच - ✓
जवाबदेह - ✓
गंभीरता - ✓
शानदार गवर्नेंस - ✓
व्यवहार कुशलता - ✓
फैसला लेने की क्षमता - ✓

इन सात मुख्य बिंदुओं पर किये गये वार्षिक सर्वे 'असरदार ब्यूरोक्रेट्स -2019' में संजय मल्होत्रा प्रमुख स्थान पर हैं।

सर्वे स्रोत :- विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की राय पर आधारित

FAME INDIA

हौसलामंद ब्यूरोक्रेट हैं प्रत्यय अमृत

हौसला

बिहार के सबसे तेज़-तर्रार, काबिल और टारगेट के मुताबिक काम करने वाले अफसरों की गिनती में 1991 बैच के आईएएस अधिकारी प्रत्यय अमृत का नाम प्रमुखता से शामिल है। वर्तमान में प्रत्यय अमृत बिहार के ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव हैं। इन्होंने राज्य सरकार के सात निश्चयों में सबसे प्रमुख हर घर बिजली के वादे को रिकार्ड समय में पुरा कर यह साबित कर दिया की इन्हें अहम फैसले लेने की त्वरित क्षमता वाला दूरदर्शी ब्यूरोक्रेट यूं ही नहीं माना जाता।

दिल्ली विश्वविद्यालय के हिन्दू कॉलेज से हिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएट व्यवहार कुशल प्रत्यय अमृत डीयू के टॉपर रहे हैं। बिहार के गोपालगंज ज़िले के रहने वाले प्रत्यय अमृत ने पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद साउथ कैंपस के नामी वेंकेटेश्रर कॉलेज में लेक्चरर के पद पर ज्वाइन किया। परन्तु जल्दी ही इनका सलेक्शन सिविल सेवा के लिए हो गया। ट्रेनिंग के बाद पहली पोस्टिंग 1993 में सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट के तौर पर हुई। 1997 में सारण के जिला अधिकारी बनाए गए। 1997 से नवंबर 2000 तक मात्र तीन वर्ष में इन्हें चार बार ट्रांसफर कर दिया गया। इस दौरान ये सारण, जहानाबाद, पटना व कटिहार के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बने, हर जगह उनका कार्य उत्कृष्ट ही रहा।

वर्ष 2000 में पहली बार ये राज्य विद्युत बोर्ड के सचिव बनाए गए, परन्तु जल्दी ही ये केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर नई दिल्ली चले गए।

2006 में ये अपने कैडर बिहार वापस आए और तब राज्य अपनी सबसे बड़ी समस्या टूटी-फूटी सड़क एवं जर्जर पुलों से जुझ रहा था। तत्कालीन मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने इन्हें सबसे चुनौतीपूर्ण राज्य पथ एंव पुल निर्माण विभाग का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया। इन्होंने जुलाई 2009 तक परिस्थिति बदल दी। वर्ष 2009 में इन्हें पथ निर्माण विभाग का सचिव सह परियोजना निदेशक बनाया गया। जहां ये 2013 तक रहे। प्रत्यय अमृत को साल 2011 में प्रधानमंत्री लोक प्रशासन उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए चुना गया।

जून 2014 में इन्हें बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर और ऊर्जा विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाए गए। नवंबर 2018 में बिहार के सभी गांवों के बिजलीकरण का काम इनकी अगुवाई में ही पूरा हुआ। आजकल प्रत्यय वैकल्पिक ऊर्जा पर काम कर रहे हैं।

FAME INDIA

अन्य प्रमुख नाम:

शमशेर सिंह रावत
संजीव कौशिक
मनीषा मयस्कर
अनिल कुमार सिंघल
नीरजा शेखर

(इस श्रेणी के सभी प्रमुख ब्यूरोक्रेटस की पूरी प्रोफाइल fameindia.co पर पब्लिश की जा रही है।)

फेम इंडिया मैगज़ीन- एशिया पोस्ट के प्रमुख मापदंड:

- दूरदर्शिता - ✓
- उत्कृष्ट सोच - ✓
- जवाबदेह - ✓
- गंभीरता - ✓
- शानदार गवर्नेंस - ✓
- व्यवहार कुशलता - ✓
- फैसला लेने की क्षमता - ✓

इन सात मुख्य बिंदुओं पर किये गये वार्षिक सर्वे 'असरदार ब्यूरोक्रेट्स -2019' में प्रत्यय अमृत प्रमुख स्थान पर हैं।

सर्वे स्रोत :- विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की राय पर आधारित

कर्त्तव्यनिष्ठ ब्यूरोक्रेट हैं अशोक वर्णवाल

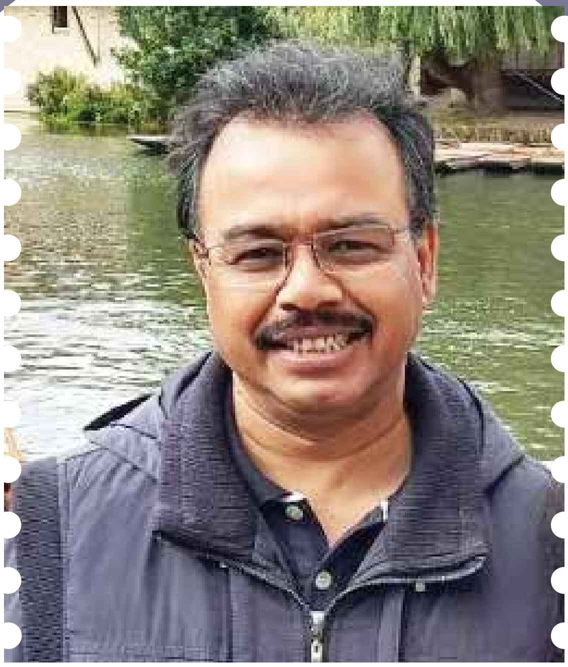

कर्त्तव्यनिष्ठ

मध्य प्रदेश के ईमानदार और कर्त्तव्यनिष्ठ ब्यूरोक्रेट में शुमार अशोक वर्णवाल वर्तमान में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के साथ ही राज्य के विजन 2025 के समन्वयक भी है। राज्य में ई गवर्नेंस को लागू करवाने में मध्य प्रदेश कैडर के 1991 बैच के आईएएस अधिकारी 52 वर्षीय अशोक वर्णवाल का महत्त्वपूर्ण योगदान हैं। माइनिंग इंजीनियरिंग से प्रथम श्रेणी में ग्रेजुएट अशोक सबसे पहले तब चर्चा में आए, जब 1998 में अविभाजित मध्यप्रदेश में बस्तर के तत्तकालीन जिलाधिकारी रहते एक अनियमितता की जांच में दो आईएएस अधिकारियों को दोषी पाया और इनके विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा की।

अशोक वर्णवाल गुना,देवास, शहडोल के जिलाधिकारी रहे हैं और हर पोस्टिंग पर इन्होंने अपनी कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया। 2004 में ये पहली बार एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पर मुख्यमंत्री सचिवालय आए और विभाग की समझ ऐसी की सभी को कायल बना गए। वर्ष 2008 में करीब ढाई साल के लिए केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने से पहले ये राज्य में मिशन कार्डिनेटर राजीव गांधी वाटरशेड मिशन, एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, सेक्रेटरी इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस थे। कैडर में वापस आने के बाद इन्हें आयुक्त राज्य शिक्षा मिशन और फिर स्टेट कोआपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया। अशोक वर्णवाल ने 2012-13 में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से ई गवर्नेंस इनेशेटिव इन एडमिनिस्ट्रेशन की ट्रेनिंग भी ली है।

2013 में इन्हें राज्य के खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया और इस दौरान इन्होंने राज्य में इन विभागों में जो महत्त्वपूर्ण कार्य किए, कई राज्यों ने उस माडल का अनुकरण किया। अगस्त 2016 में अशोक वर्णवाल को राज्य सरकार में मुख्यमंत्री सचिवालय का प्रधान सचिव भी नियुक्त किया गया। ये सीएम सेक्रेटेरिएट के साथ ही फूड और हार्टिकल्चर के भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। उन पर राज्य सरकारों का भरोसा लगातार बढ़ता गया। वर्ष 2018 के अंत में राज्य के चुनाव में सत्ता बदली परन्तु अशोक वर्णवाल का कद और पद मुख्यमंत्री सचिवालय सहित अन्य विभागों में बढ़ता ही गया। नई सरकार ने भी उन पर ही भरोसा जताया, मध्य प्रदेश में अगले पांच साल के विकास के बनाए गए रोड मैप "विजन 2025" के लिए समन्वय का जिम्मा वर्त्तमान मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अशोक वर्णवाल को ही दिया गया है। इसके अलावा विधानसभा मुख्यमंत्री कार्यालय, कैबिनेट संबंधित व अन्य कार्य (जो किसी को आवंटित नहीं) की जिम्मेदारी भी इन्हें ही दी गई है। साथ ही जिम्मा है मुख्यमंत्री के द्वारा सौंपे गए कार्य और अन्य समन्वय का। हर जवाबदेही में इनकी दूरदर्शिता, निर्णय लेने की क्षमता, उत्कृष्ट कार्यशैली और प्रबंधन क्षमता प्रदर्शित होती रही है।

अन्य प्रमुख नाम:

चंचल कुमार
विजय कुमार
नीलम शामी राव
रश्मी प्रमोद श्रीवास्तव
संजय जाजू

(इस श्रेणी के सभी प्रमुख ब्यूरोक्रेटस की पूरी प्रोफाइल fameindia.co पर पब्लिश की जा रही है।)

फेम इंडिया मैगजीन- एशिया पोस्ट के प्रमुख मापदंड:

दूरदर्शिता - ✓
उत्कृष्ट सोच - ✓
जवाबदेह - ✓
गंभीरता - ✓
शानदार गवर्नेंस - ✓
व्यवहार कुशलता - ✓
फैसला लेने की क्षमता - ✓

इन सात मुख्य बिंदुओं पर किये गये वार्षिक सर्वे 'असरदार ब्यूरोक्रेट्स -2019' में अशोक वर्णवाल प्रमुख स्थान पर हैं।

सर्वे स्रोत :- विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की राय पर आधारित

विशिष्ट कार्यशैली ने दी पहचान निधि खरे को

विशिष्ट

झारखंड कैडर की 1992 बैच की निधि खरे को इनकी उत्कृष्ट कार्यशैली और दूरदर्शिता के साथ ही बेहद ईमानदार ब्यूरोक्रेट के तौर पर जाना जाता है। मूल रूप से जम्मू-कश्मीर निवासी निधि खरे वर्तमान में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर है और पर्यावरण और वन मंत्रालय में संयुक्त सचिव के तौर पर पदस्थापित है। ये बायो केमिस्ट्री में टाप रेंकिंग से पोस्ट ग्रेजुएट हैं, साथ ही इन्होंने न्यूयॉर्क से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एमपीए की डिग्री ग्रेड ए से प्राप्त की है।

निधि खरे को 1992 में यूपीएससी में पास करने के बाद इन्हें बिहार कैडर मिला, डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग के बाद अविभाजित बिहार के पूर्वी सिंहभूम जिले में बतौर डीडीसी पदस्थापित हुई। जिलाधिकारी के तौर पर पहली पोस्टिंग मधुबनी जिले में हुई और वहां की मशहूर पेंटिंग के कलाकारों के कल्याण और जिले में किए गए अन्य कई बड़े विकास कार्यों के लिए वहां के लोग इन्हें आज भी याद करते हैं। राज्य के बंटवारे के बाद इन्हें झारखंड कैडर मिला और वर्ष 2001 से 2008 के बीच इन्हें दुमका, पूर्वी सिंहभूम की जिलाधिकारी, श्रम आयुक्त, पर्यटन विभाग की अपर सचिव, झारखंड शिक्षा परियोजना की राज्य परियोजना निदेशक, उपाध्यक्ष - नगर विकास विभाग और स्वास्थ्य एंव महिला विकास की विशेष सचिव बनाया गया। 2008 में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से पहले ये रांची की डिविजनल कमिश्नर थी। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति का वह कार्यकाल सात साल का था, जिसमें इन्होंने विभिन्न मंत्रालयों में संयुक्त सचिव, सलाहकार और निदेशक के पद पर रही। इन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, अहमदाबाद से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड फाइनेंसिंग और डॉ रघुनंदन सिंह टोलिए उत्तराखंड एकेडमी ऑफ ऐडमिस्ट्रेशन से कम्यूनिटी मोब्लाइजेशन एंड पार्टिसिपेटरि मैनेजमेंट की ट्रेनिंग भी ली है। 2008 में झारखंड लौटने पर इन्हें वाणिज्य कर आयुक्त बनाया गया और फिर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राज्यभाषा विभाग की प्रधान सचिव और सरकार की प्रवक्ता के पद पर पदस्थापित किया गया। सभी पदों पर पदस्थापना के साथ ही इन्होंने सकारात्मक प्रयास शुरू किए। दो वर्ष बाद इन्हें स्वास्थ्य विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में महज साढ़े सात महीने के इनके छोटे से कार्यकाल को लोगो ने बेहतर बताया, राज्य में साफ सफाई, आयुष्मान भारत योजना, रिम्स के अपग्रेडेशन और अन्य स्वास्थ्य सुविधा को लेकर इन्होंने बहुत से बड़े कदम उठाए। अक्टूबर 2018 में इन्हें पुनः केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर पांच साल के लिए भेजा गया, जहां पहले इन्हें गृहमंत्रालय और फिर पर्यावरण मंत्रालय में संयुक्त सचिव बनाया गया। निधि खरे की खासियत ईमानदार, उत्कृष्ट कार्यशैली के साथ शानदार गवर्नेंस की भी रही है।

अन्य प्रमुख नामः

के आर ज्योतिलाल
दीप्ति उमाशंकर
आभा शुक्ला
दीप्ति गौड़ मुखर्जी
शिखर अग्रवाल

(इस श्रेणी के सभी प्रमुख ब्यूरोक्रेटस की पूरी प्रोफाइल fameindia.co पर पब्लिश की जा रही है।)

फेम इंडिया मैगज़ीन-एशिया पोस्ट के प्रमुख मापदंडः

दूरदर्शिता -	✓
उत्कृष्ट सोच -	✓
जवाबदेह -	✓
गंभीरता -	✓
शानदार गवर्नेंस -	✓
व्यवहार कुशलता -	✓
फैसला लेने की क्षमता -	✓

इन सात मुख्य बिंदुओं पर किये गये वार्षिक सर्वे 'असरदार ब्यूरोक्रेट्स -2019' में निधि खरे ने प्रमुख स्थान पर हैं।

सर्वे स्रोत :- विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की राय पर आधारित

उसूलों के पक्के हैं तेजवीर सिंह

योग्य
★★★★★

पंजाब के तेज-तर्रार आईएएस अधिकारी तेजवीर सिंह अपनी समझदारी और मिलनसार स्वभाव के लिये जाने जाते हैं। ये मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं और लो प्रोफाइल रह कर चुपचाप अपना कार्य करने के पक्षधर हैं। तेजवीर सिंह को मुख्यमंत्री के विश्वस्त लोगों में जाना जाता है।

चंडीगढ़ के मूल निवासी तेजवीर सिंह को हिंदी और अंग्रेजी के अलावे पंजाबी व मराठी में भी दक्षता हासिल है। ये दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और 1994 बैच में आईएएस में चयनित होने पर इन्हें महाराष्ट्र कैडर मिला, लेकिन बाद में इन्हें कैडर रिव्यु के बाद पंजाब मिल गया। ये शुरूआत से ही वित्तीय और प्रशासनिक मामलों के विशेषज्ञ माने जाते रहे हैं। महाराष्ट्र के नासिक में ये 1996-1998 के दौरान करीब दो साल असिस्टेंट कलेक्टर रहे।

तेजवीर सिंह पंजाब सरकार में पब्लिक रिलेशन विभाग के निदेशक पद पर रहे हैं और प्रेस के साथ इनके हमेशा मधुर संबंध रहे हैं। ये लंबे अर्से तक कैप्टन अमरिंदर सिंह के गृह जिले पटियाला के जिलाधिकारी रह चुके हैं और वहां के लोगों का दुखदर्द भली-भांति समझते हैं। ये दोनों ही वजहें इनकी योग्यता में चार चांद लगाती हैं और मुख्यमंत्री को इसकी जरूरत भी है।

तेजवीर सिंह ने सेवा में रहते हुए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस से लोक प्रबंधन व गवर्नेंस में एम एससी की डिग्री हासिल की है। ये केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर मसूरी स्थित भारत सरकार की अकादमी में करीब आठ साल रहे और इन्होंने वहां कई सुधार कार्य किये। अपने पंजाब कैडर में इनकी पोस्टिंग हमेशा चर्चा में रही। ये अमृतसर में चुनावों के दौरान डीसी बनाये गये थे और ये जिले के चुनिंदा गैर सिख जिलाधिकारियों में से थे। ये चंडीगढ़ और पटियाला के डीसी भी रहे व आनंदपुर साहिब में एसडीएम। ये एक अच्छे योजनाकार माने जाते हैं सरकार ने प्लैनिंग विभाग में बतौर स्पेशल सेक्रेटरी इनकी सेवाओं का लाभ लिया है। इन्हें उसूलों का पक्का और योग्य ब्यूरोक्रेट माना जाता है।

अन्य प्रमुख नाम:

विवेक अग्रवाल
पीयूष गोयल
सुशील कुमार लोहानी
संजय कुमार
वर्षा जोशी

(इस श्रेणी के सभी प्रमुख ब्यूरोक्रेट्स की पूरी प्रोफाइल fameindia.co पर पब्लिश की जा रही है।)

फेम इंडिया मैगजीन- एशिया पोस्ट के प्रमुख मापदंड:

- दूरदर्शिता - ✓
- उत्कृष्ट सोच - ✓
- जवाबदेह - ✓
- गंभीरता - ✓
- शानदार गवर्नेंस - ✓
- व्यवहार कुशलता - ✓
- फैसला लेने की क्षमता - ✓

इन सात मुख्य बिंदुओं पर किये गये वार्षिक सर्वे 'असरदार ब्यूरोक्रेट्स -2019' में तेजवीर सिंह प्रमुख स्थान पर हैं।

सर्वे स्रोत :- विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की राय पर आधारित

FAME INDIA

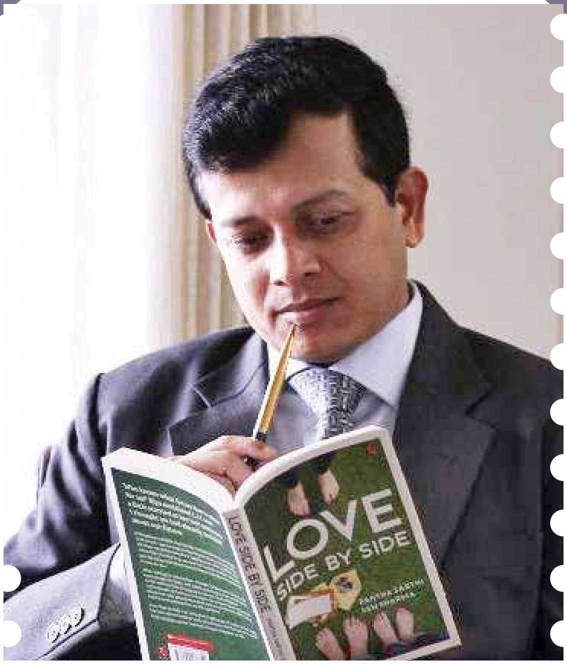

बहु-आयामी प्रतिभा से भरपूर पार्थ सारथी सेनशर्मा

कलात्मक

★★★★★

असरदार ब्यूरोक्रेट्स की बात होती है तो उत्तर प्रदेश कैडर के 1994 बैच के आईएएस अधिकारी पार्थ सारथी सेनशर्मा का नाम इनकी प्रशासनिक दक्षता की वजह से आता है। वर्तमान में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर है पार्थ सारथी सेनशर्मा, और भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर में ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर हैं। साथ ही इनकी जिम्मेदारी प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड के सीएमडी की भी है।

दिल्ली के समृद्ध बंगाली परिवार में पार्थ सारथी सेनशर्मा का जन्म 30 जून 1970 को हुआ, बचपन से मेधावी पार्थ दिल्ली कालेज आफ इंजीनियरिंग से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट और स्लोवेनिया युनिवर्सिटी से एमबीए डिग्री धारी हैं। आईएएस अधिकारी बनने से पहले टाटा ग्रुप में इंजीनियर के तौर पर कार्य भी किया। 1994 में यूपीएससी पास करने के बाद वाराणसी में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के तौर पर पहली बार पोस्टिंग हुई। वाराणसी में पहली ही पोस्टिंग के दौरान इन्होंने अपनी काबिलियत और दूरदर्शिता का परिचय दिया। फिर सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट इलाहाबाद, सीडीओ अल्मोड़ा और कौशांबी और कानपुर देहात के जिलाधिकारी के तौर पर भी इन्होंने बेहतरीन कार्य किया। इनकी कार्य कुशलता और गवर्नेंस की क्षमता को देखते हुए राज्य में हर सरकार में इन्हें लगातार बड़ी जवाबदेही दी जाती रही। योगी सरकार हो या सपा या बसपा सभी सरकार में इन्हें बेहतर आफिसर माना। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने से पहले ये ग्रेटर नॉएडा के सीईओ थे और इससे पहले प्रदेश के रूरल डेवलपमेंट विभाग में कमिश्नर और इसी विभाग के कम्यूनिटी प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी थे। ये सपा सरकार में मुख्यमंत्री सचिवालय के सचिव रहे हैं। सेक्रेटरी सकेंडरी स्कूल के तौर पर इन्होंने ही उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय लैपटॉप योजना की शुरुआत की थी।

इन्होंने 2007-08 में लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ ऐडमिस्ट्रेशन इथिक इशू इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की ट्रेनिंग की है।

आईएएस अधिकारी होने के साथ पार्थ सारथी सेन शर्मा चर्चित लेखक भी हैं। इन्होंने "ए पैसेज एक्रास यूरोप" और "लव - साइड बाइ साइड" के साथ ही एवरी माईल ए मेमोरी" नाम से किताबें लिखी हैं। इन किताबों में दो का हिंदी अनुवाद "मुसाफिर हूं यारों" और "हम है राही प्यार के" से भी आ चुके हैं। इनकी बहुआयामी प्रतिभा इन्हें असरदार ब्यूरोक्रेट के तौर पर स्थापित करती है।

अन्य प्रमुख नाम:

अरविंद श्रीवास्तव
रंजना चोपड़ा
एल एस चंगसन
भरत हरवंश लाल खेर
डॉ नितिन मदन कुलकर्णी

(इस श्रेणी के सभी प्रमुख ब्यूरोक्रेटस की पूरी प्रोफाइल fameindia.co पर पब्लिश की जा रही है।)

फेम इंडिया मैगज़ीन-एशिया पोस्ट के प्रमुख मापदंड:

- दूरदर्शिता - ✓
- उत्कृष्ट सोच - ✓
- जवाबदेह - ✓
- गंभीरता - ✓
- शानदार गवर्नेंस - ✓
- व्यवहार कुशलता - ✓
- फैसला लेने की क्षमता - ✓

इन सात मुख्य बिंदुओं पर किये गये वार्षिक सर्वे 'असरदार ब्यूरोक्रेट्स -2019' में पार्थ सारथी सेन शर्मा प्रमुख स्थान पर हैं।

सर्वे स्रोत :- विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की राय पर आधारित

उम्दा स्कॉलर और क्षमताओं से भरपूर अनुराधा ठाकुर

क्षमतावान

भारत सरकार के निवेश और पब्लिक एसेट मैनेजमेंट विभाग में ज्वाइंट सेक्रेटरी अनुराधा ठाकुर की गिनती देश के जानकार व तेज-तर्रार अधिकारियों में होती है। ये उन चुनिंदा अधिकारियों में से हैं जो विश्व बैंक में तीन वर्षों तक एडवाइजर रह चुकी हैं। देश की आर्थिक नीतियों के निर्धारण व अनुपालन के लिये केंद्र सरकार ने इन्हें दोबारा प्रतिनियुक्ति पर बुलाया है।

मूल रूप से बिहार की रहने वाली अनुराधा ठाकुर ने दिल्ली विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान में एमए किया है, लेकिन 1994 बैच में हिमाचल कैडर की आईएएस बनने के बाद से ये लगातार रेवेन्यु व कॉमर्स जैसे विभागों से जुड़ी रहीं। इन्होंने कांगड़ा में बतौर एडिशनल डीसी व हमीरपुर जिले में बतौर डिप्टी कमिश्नर कार्य किया। हिमाचल सरकार के पंचायती राज, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग में भी अपनी सेवाएं दीं। इन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस से डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में सर्टिफिकेट कोर्स किया। इसके अलावा ये हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से फ्रेंच भाषा में भी सर्टिफिकेट हासिल कर चुकी हैं।

ये वर्ष 2008 में केंद्र सरकार की प्रतिनियुक्ति पर वित्त मंत्रालय में बतौर डिप्युटि सेक्रेटरी पदस्थापित हुईं और वहीं डायेक्टर भी बनीं। वर्ष 2011 में ये विश्व बैंक में एक्जीक्युटिव डायरेक्टर की एडवाइजर के तौर पर वाशिंगटन गयीं। वर्ष 2015 में ये हिमाचल प्रदेश सरकार में सोशल जस्टिस एंड इंपॉवरमेंट सेक्रेटरी बनीं। वर्ष 2016 में इन्हें सिंचाई व लोक स्वास्थ्य विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का भी कार्यभार सौंपा गया। वर्ष 2017 से ये भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में प्रतिनियुक्ति पर हैं।

अनुराधा ठाकुर को एक जानकार अधिकारी के साथ-साथ उम्दा स्कॉलर भी माना जाता है। इन्होंने हिमाचल प्रदेश में जल संरक्षण का करीब से अध्ययन किया है और उस विषय पर कई लेख लिख चुकी हैं। सामजिक, आर्थिक और जल प्रबंधन जैसे विषयों पर इनके लिखे आलेख योजना, इकोनॉमिक टाइम्स, ट्रिब्यून व हिन्दू बिजनेस जैसे प्रतिष्ठित पब्लिकेशनों में छपते रहे हैं।

अन्य प्रमुख नाम:

राजीव चंद्र जोशी
संजीव खैरवार
अर्चना वर्मा
संध्या वी शर्मा
मृत्युंजय कुमार नारायण

(इस श्रेणी के सभी प्रमुख ब्यूरोक्रेट्स की पूरी प्रोफाइल fameindia.co पर पब्लिश की जा रही है।)

फेम इंडिया मैगजीन- एशिया पोस्ट के प्रमुख मापदंड:

- दूरदर्शिता - ✓
- उत्कृष्ट सोच - ✓
- जवाबदेह - ✓
- गंभीरता - ✓
- शानदार गवर्नेंस - ✓
- व्यवहार कुशलता - ✓
- फैसला लेने की क्षमता - ✓

इन सात मुख्य बिंदुओं पर किये गये वार्षिक सर्वे 'असरदार ब्यूरोक्रेट्स -2019' में अनुराधा ठाकुर प्रमुख स्थान पर हैं।

सर्वे स्रोत :- विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की राय पर आधारित

FAME INDIA

उत्तर पूर्व में खासी शोहरत प्राप्त आईएएस हैं संजय लोहिया

शोहरत

★★★★★

असम के मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी संजय लोहिया की पहचान एक गंभीर और अनुभवी अधिकारी की है। 1994 बैच के असम-मेघालय कैडर के लोहिया आईटी, कृषि, टैक्सेशन और सामान्य प्रशासन के विशेषज्ञ माने जाते हैं। ये मुख्यमंत्री के विश्वस्त और असम के लोकप्रिय अधिकारियों में से एक हैं और इन्हें सरकार में काफी प्रभावशाली अधिकारी माना जाता है।

संजय लोहिया मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले हैं और इन्होंने भौतिकी से स्नातक की पढ़ाई की है। 30 अगस्त 1969 को जन्मे संजय ने युवावस्था में ही आईएएस की परीक्षा में सफलता हासिल कर 1994 में असम-मेघालय कैडर ज्वाइन किया। इन प्रदेशों के लोगों की समस्याओं को समझने और उनसे करीबी संपर्क रखने के लिये इन्होंने हिन्दी और अंग्रेजी को अलावे असमिया और बंगाली भाषा में भी दक्षता हासिल की।

वर्ष 2007 से 2011 तक ये राज्य के कमर्शियल टैक्स कमिश्नर रहे और इस दौरान राज्य में इन करों की वसूली में सबसे अधिक वृद्धि हुई। इन्होंने पहली बार ऑन लाइन टैक्स जमा करने की प्रक्रिया शुरू करवायी। जब वर्ष 2003 में उल्फा उग्रवादियों ने बीस बिहारी मजदूरों को मौत के घाट उतार दिया था तब ये गुवाहाटी के म्युनिसिपल कमिश्नर थे। इनकी प्रशासनिक क्षमताओं को देखते हुए इन्हें विशेष रूप से तिनसुकिया के जिलाधिकारी का कार्यभार भी सौंपा गया था। बतौर म्युनिसिपल कमिश्नर इन्होंने ही गुवाहाटी नगर निगम के रिकॉर्डों का कंप्युटराइजेशन करवाया जिससे आमदनी में भारी इजाफा हुआ।

संजय लोहिया को पूर्वोत्तर भारत के कई संवेदनशील जिलों में सफलता-पूर्वक प्रशासन संभालने का पुराना अनुभव है। दरांग, सोनितपुर, डिब्रूगढ़ व तिनसुकिया में बतौर जिलाधिकारी ये सफल प्रशासन की कमान संभाल चुके हैं। ये प्रदेश के कृषि विभाग और वर्ल्ड बैंक के विशेष प्रोजेक्ट के इंचार्ज रह चुके हैं। सरकार को औद्योगिक नीति, आईटी नीति, सोलर नीति और कृषि आदि से संबधित कोई भी नीति तैयार करनी होती है तो संजय लोहिया को सलाह के लिये अवश्य रखा जाता है।

इनकी क्षमताओं की वजह से इन्हें वर्ष 2011 में विशेष तौर पर पीएमओ का डायरेक्टर बनाया गया था। इस दौरान इन्होंने खनिज, कोयला, योजना आयोग, वन एवं पर्यावरण जैसे कई विभागों को सर्वोच्च स्तर पर संचालित किया। ये भारत सरकार के कृषि मंत्रालय से भी जुड़े। वर्ष 2016 से प्रदेश के विकास में संलग्न हैं।

अन्य प्रमुख नामः

- कुलदीप रांका
- नरेश पाल गंगवार
- मनीष जैन
- एम महेश्वर राव
- राधिका रस्तोगी

(इस श्रेणी के सभी प्रमुख ब्यूरोक्रेटस की पूरी प्रोफाइल fameindia.co पर पब्लिश की जा रही है।)

फेम इंडिया मैगज़ीन- एशिया पोस्ट के प्रमुख मापदंडः

- दूरदर्शिता - ✓
- उत्कृष्ट सोच - ✓
- जवाबदेह - ✓
- गंभीरता - ✓
- शानदार गवर्नेंस - ✓
- व्यवहार कुशलता - ✓
- फैसला लेने की क्षमता - ✓

इन सात मुख्य बिंदुओं पर किये गये वार्षिक सर्वे 'असरदार ब्यूरोक्रेट्स -2019' में संजय लोहिया प्रमुख स्थान पर हैं।

सर्वे स्रोत :- विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की राय पर आधारित

FAME INDIA

चुनौतियों को अवसर में बदलने वाले ब्यूरोक्रेट हैं श्रीवत्स कृष्णा

बाजीगर

★★★★★

श्रीवत्स कृष्णा का जन्म 24 अक्टूबर, 1968 को एक दक्षिण भारतीय परिवार में दिल्ली में हुआ था। ये सुर्खियों में तब आये जब 1994 में आईएएस की परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया। इन्हें सबसे अधिक अंक लाने के लिये गोल्ड मैडल भी मिला। इसके बाद तो लगभग पूरा कैरियर हाइलाइटेड रहा है। इन्होनें बतौर कॉफी विकास बोर्ड के अध्यक्ष व सेक्रेटरी, एक ऐसा ऐप्प लांच किया जो कॉफी उत्पादक किसानों को अंतर्राष्ट्रीय मंच और नवीनतम कृषि तकनीक देगा।

प्रतिष्ठित जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय से अंतर्राष्ट्रीय संबंध में पीजी डिग्री रखने वाले श्रीवत्स के लिये आईएएस बनना अपने पिता के सपने को पूरा करने का एक मिशन था। इसलिये इन्होंने स्टैनफोर्ड और येल से मिल रही स्कॉलरशिप को छोड़ कर सिविल सेवा की तैयारी की। इन्होंने पिछले दस साल से टॉप की पोजीशन पर रहने वाले आईआईटी ग्रैजुएट्स का वर्चस्व तोड़ दिया। इन्होंने सेवा में आने के बाद हॉर्वर्ड बिजनेस स्कूल से एमबीए किया। ये देश के पहले और इकलौते आईएएस अधिकारी हैं जिन्होंने यह डिग्री हासिल की है।

इन्हें करीयर के शुरू में दिल्ली कैडर के लिए चुना गया। पहली पोस्टिंग में ही भूमाफियाओं से जोरदार झड़प हुई और इनका ट्रॉमा सेंटर में तबादला हो गया। वहां इन्होंने कैट्स ऐंबुलेंस की शुरुआत की जो आज भी हजारों दिल्लीवासियों की जान बचा रहा है। कुछ ही दिनों में इन्होंने आंध्र प्रदेश कैडर चुन लिया जहां तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इन्हें हैदराबाद को साइबर हब बनाने व सफलतापूर्वक चलाने के मिशन पर लगा दिया। ये श्रीवत्स की कोशिशों का ही नतीजा था कि हैदराबाद आज दुनिया के पंद्रह सबसे प्रमुख नगरों में शुमार है। इन्हें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का प्रतिष्ठित अवॉर्ड मिला। ये स्टडी लीव पर हॉर्वर्ड गये तो वर्ल्ड बैंक के साथ भी काम किया। वापस आकर इन्होंने पारिवारिक कारणों से कर्नाटक कैडर चुन लिया। कर्नाटक सरकार में सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी और विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शहरी विकास जैसे कई महत्त्वपूर्ण मत्रालयों का कार्यभार संभाला। अप्रैल 2017 से ये केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं जहां कॉमर्स मंत्रालय में कॉफी बोर्ड की जिम्मेदारी सौंपी गयी है।

गाने के शौकीन श्रीवत्स कृष्णा ने ऑस्कर विजेता म्युजिक डायरेक्टर एआर रहमान के निर्देशन में बॉलीवुड फिल्म शंघाई के लिये एक गीत भी गाया है।

अन्य प्रमुख नाम:

ऋचा शर्मा
राजेश अग्रवाल
संजय कुमार शुक्ला
डॉ महिंदर कौर द्विवेदी
डी थारा

(इस श्रेणी के सभी प्रमुख ब्यूरोक्रेटस की पूरी प्रोफाइल fameindia.co पर पब्लिश की जा रही है।)

फेम इंडिया मैगजीन- एशिया पोस्ट के प्रमुख मापदंड:

- दूरदर्शिता - ✓
- उत्कृष्ट सोच - ✓
- जवाबदेह - ✓
- गंभीरता - ✓
- शानदार गवर्नेंस - ✓
- व्यवहार कुशलता - ✓
- फैसला लेने की क्षमता - ✓

इन सात मुख्य बिंदुओं पर किये गये वार्षिक सर्वे 'असरदार ब्यूरोक्रेट्स -2019' में श्रीवत्स कृष्णा प्रमुख स्थान पर हैं।

सर्वे स्रोत :- विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की राय पर आधारित

सफलता की उड़ान भरने वाली अश्विनी भिड़े

उड़ान

नागपुर में स्वदेशी जल संरक्षण चैक डैम बनाने से लेकर मुंबई मेट्रो प्रोजेक्ट तक 1995 बैच की टापर महाराष्ट्र कैडर की आईएएस अधिकारी अश्विनी भिड़े ने कई महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एमएमआरसी की प्रबंध निदेशक अश्वनी सतीश भिड़े ऐसी पॉवरफुल महिला हैं जिन्होंने अपनी बुद्धि और आत्मविश्वास से कई मिसाल कायम की है।

प्रतिभाशाली अश्विनी सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और पढ़ाई के दौरान हमेशा बेहतर रही है। ये मराठी, अंग्रेजी के साथ हिंदी पर भी अच्छी पकड़ रखती है।

सिंहदुर्ग जिला परिषद की सीईओ,एडिशनल कलेक्टर कोल्हापुर से शुरू हुआ इनका प्रशासनिक सफर अश्विनी के असरदार ब्यूरोक्रट होने की कहानी बयां करता है। अपने शानदार ढाई दशक के कैरियर में भिड़े अब तक जिला परिषद के सीईओ, एडिशनल डिविजनल कमिश्नर , गवर्नर की ज्वाइंट सेक्रेटरी , एमएमआरडीए की एडिशनल मेट्रोपोलिटन कमिश्नर और राज्य की स्कूल एजुकेशन और स्पोर्टस की सेक्रेटरी भी रही है। एमएमआरडीए में इनकी प्रतिभा, कुशल नेतृत्व और शानदार गवर्नेंस के कारण ही मुम्बई की सबसे महत्वाकांक्षी और चुनौतीपूर्ण योजना के लिए राज्य सरकार ने 2015 में अश्विनी सतीश भिड़े को चुना। यह मेट्रो का प्रोजेक्ट 33.5 किलोमीटर लंबा है और 2021 में इसके शुरू होते ही मुम्बई में एक तरह की यात्रा क्रांति संभव है। यूं तो शुरुआत में प्रबंध निदेशक के तौर पर अश्विनी को ढेर सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, परन्तु जिस तरह इन्होंने जनता सहित सभी लोगों का विश्वास जीत कर इस प्रोजेक्ट को अब तक अमली जामा पहनाया है ये इनकी दूरदर्शिता और व्यवहार कुशलता से ही संभव हो पाया। अश्विनी भिड़े ने पूर्व में एमएमआरडी के अपने कार्यकाल के दौरान 5,000 से अधिक परिवारों के पुनर्वास प्रयासों के लिए भी इन्हें जाना जाता है, यह अपने आप में एक शोध का विषय है।

अश्विनी ने अपने पूर्व की अलग अलग नियुक्तियों के दौरान ग्रामीण भारत की विकास की परिकल्पना को भी एक नई गति दी।

अन्य प्रमुख नामः

लव अग्रवाल
अजिताभ शर्मा
ए कार्तिक
गायत्री ए राठौड़
महेंद्र प्रसाद अग्रवाल

(इस श्रेणी के सभी प्रमुख ब्यूरोक्रेटस की पूरी प्रोफाइल fameindia.co पर पब्लिश की जा रही है।)

फेम इंडिया मैगज़ीन- एशिया पोस्ट के प्रमुख मापदंडः

दूरदर्शिता - ✓
उत्कृष्ट सोच - ✓
जवाबदेह - ✓
गंभीरता - ✓
शानदार गवर्नेंस - ✓
व्यवहार कुशलता - ✓
फैसला लेने की क्षमता - ✓

इन सात मुख्य बिंदुओं पर किये गये वार्षिक सर्वे 'असरदार ब्यूरोक्रेट्स -2019' में अश्विनी भिड़े प्रमुख स्थान पर हैं।

सर्वे स्रोत :- विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की राय पर आधारित

कुशल प्रशासनिक क्षमता के धनी अधिकारी हैं गौरव द्विवेदी

कुशल प्रबंधक

छत्तीसगढ़ के सबसे प्रभावी अधिकारियों में गौरव द्विवेदी का नाम प्रमुख है। ये मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव हैं और छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा के भी मुखिया हैं। चाहे सरकारी खरीद को ई-गवर्नेंस के जरिये पारदर्शी बनाने की कवायद हो या फिर शिक्षा में सुधार के लिये शिक्षकों का ऐप्प और छात्रों का व्यापक अध्ययन, ये हर क्षेत्र में प्रदेश का गौरव बढ़ाने वाले अधिकारी साबित हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मूल निवासी गौरव द्विवेदी ने अपनी स्कूली पढ़ाई एपीजे स्कूल नोएडा से और आगे की पढ़ाई हिंदू कॉलेज, दिल्ली से की।

गौरव द्विवेदी दिल्ली विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में एमएससी हैं। ये 1995 बैच में केरल कैडर के अधिकारी बने और 1999 में मध्य प्रदेश कैडर में स्थानांतरित हो गये। इन्होंने ड्यूक सेंटर फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (डीसीआईडी), ड्यूक यूनिवर्सिटी, यूएसए से प्रोजेक्ट मूल्यांकन और रिस्क मैनेजमेंट पर एक कोर्स भी किया है। द्विवेदी ने छत्तीसगढ़ जाने से पहले केरल में सहायक कलेक्टर के रूप में आईएएस में अपना कैरियर शुरू किया। अन्य पोस्टिंग के बीच, इन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य विपणन मंडी बोर्ड के प्रबंध निदेशक और बाद में राज्य में संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में काम किया। ये महासमंद, कोरबा, बिलासपुर आदि जिलों के सफलतम जिलाधिकारियों में से गिने जाते हैं। 2009 और 2012 के बीच, द्विवेदी ने मसूरी में स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में उप निदेशक के रूप में काम किया। उसके बाद, वह नई दिल्ली चले गए और संचार मंत्रालय के तहत सूचना-प्रौद्योगिकी विभाग में उप निदेशक बने।

सितंबर 2014 में गौरव द्विवेदी को मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना "मायगाव" का सीईओ बनाया गया। कहते हैं अगस्त 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की तर्ज पर अपने पहले ऐतिहासिक टाउनहॉल संबोधन में देश भर के प्रबुद्ध वर्ग से पर्यटन, स्मार्ट सिटी, विदेश नीति से लेकर गौ संरक्षण तक के मुद्दों पर जिस प्रभावी ढंग से सवालों का जवाब दिया उसके पीछे इसी "मायगाव" का कमाल था। दिसंबर 2017 से ये वापस छत्तीसगढ़ कैडर की सेवा पर हैं।

गौरव द्विवेदी को प्रशासनिक कुशलता के लिये प्रधानमंत्री अवॉर्ड भी मिल चुका है। हाल ही में इन्होंने सातवें वेतन आयोग की घोषणा कर छत्तीसगढ़ के अधिकारियों का भी दिल जीत लिया है। हालांकि सरकारी खजाने पर ज्यादा बोझ डाले बिना इसे सफलता पूर्वक लागू करना इनके लिये भी एक चुनौती होगा।

अन्य प्रमुख नाम:

- वी शशांक शेखर
- नवीन मित्तल
- संजीव हंस
- डॉ एम गीता
- गुलशन बामरा

(इस श्रेणी के सभी प्रमुख ब्यूरोक्रेट्स की पूरी प्रोफाइल fameindia.co पर पब्लिश की जा रही है।)

फेम इंडिया मैगजीन- एशिया पोस्ट के प्रमुख मापदंड:

- दूरदर्शिता - ✓
- उत्कृष्ट सोच - ✓
- जवाबदेह - ✓
- गंभीरता - ✓
- शानदार गवर्नेंस - ✓
- व्यवहार कुशलता - ✓
- फैसला लेने की क्षमता - ✓

इन सात मुख्य बिंदुओं पर किये गये वार्षिक सर्वे 'असरदार ब्यूरोक्रेट्स -2019' में गौरव द्विवेदी प्रमुख स्थान पर हैं।

सर्वे स्रोत :- विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की राय पर आधारित

विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं प्रधानमंत्री के निजी सचिव राजीव टोपनो

विलक्षण
★★★★★

गुजरात कैडर के 1996 बैच के राजीव टोपनो की पहचान शानदार गवर्नेंस और जवाबदेह कार्यशैली के ब्यूरोक्रेट के तौर पर है। झारखंड से आने वाले राजीव टोपनो वर्त्तमान में देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निजी सचिव है। किसी भी आईएएस अधिकारी का प्रधानमंत्री के निजी सचिव के पद पर करीब पांच वर्षों से लगातार बने रहना इनकी असरदार होने की क्षमता का प्रत्यक्ष प्रमाण है।

राजीव की पहली पोस्टिंग भरूच में सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट के तौर पर हुई, वर्ष 2000 में इन्हें भुज का जिला विकास अधिकारी बनाया गया, वर्ष 2001 में गुजरात में आए भयानक भूकंप में सबसे ज्यादा तबाही इन्ही क्षेत्रों में आई थी। राहत और पुनर्वास के लिए इनके किए गए कार्य ने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदी को बेहद प्रभावित किया। यहां का कार्यकाल इनका तीन वर्षों का रहा।

कोलकाता के जाने माने सेंट जेवियर कॉलेज से ग्रेजुएट राजीव टोपनो वर्ष 2003 में भरूच के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनाए गए, वहां भी इन्होने अपने उत्कृष्ट कार्य से अच्छी छाप छोड़ी, वहां से उनका तबादला बड़ौदा के जिला अधिकारी के ही पद पर हुआ। इनके राहत, बचाव और पुनर्वास के कार्यों में अहम फैसले लेने की त्वरित क्षमता को देखते हुए वर्ष 2008 में गुजरात स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट आथरिटी में ज्वाइंट चीफ एक्जीक्यूटिव आफिसर के पद पर पोस्टिंग की गई।

2009 में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर प्रधानमंत्री कार्यालय आ गए, जहां 2010 में इन्हें प्रमोट कर डायरेक्टर बनाया गया।

वर्ष 2014 में जब केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तब इन्हें प्रधानमंत्री के सचिव के तौर पर नियुक्ति दी गई। इसी वर्ष अक्टूबर 2014 में इनका प्रमोशन डायरेक्टर से ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर हो गया। ये मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद लगातार उनके सचिव के पद पर हैं, और माना जाता है कि प्रधानमंत्री इनके कार्यक्षमता और जवाबदेह कार्यशैली के कारण राजीव टोपनो पर बेहद भरोसा भी करते हैं।

FAME INDIA

अन्य प्रमुख नाम:

राहुल सिंह
ममता वर्मा
श्यामल मिश्रा
संजीव जायसवाल
संतोष कुमार मल्ल

(इस श्रेणी के सभी प्रमुख ब्यूरोक्रेट्स की पूरी प्रोफाइल fameindia.co पर पब्लिश की जा रही है।)

फेम इंडिया मैगज़ीन- एशिया पोस्ट के प्रमुख मापदंड:

- दूरदर्शिता - ✓
- उत्कृष्ट सोच - ✓
- जवाबदेह - ✓
- गंभीरता - ✓
- शानदार गवर्नेंस - ✓
- व्यवहार कुशलता - ✓
- फैसला लेने की क्षमता - ✓

इन सात मुख्य बिंदुओं पर किये गये वार्षिक सर्वे 'असरदार ब्यूरोक्रेट्स -2019' में राजीव टोपनो प्रमुख स्थान पर हैं।

सर्वे स्रोत :- विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की राय पर आधारित

असंभव को भी संभव करने वाले हैं सुनील कुमार वर्णवाल

प्रशंसापत्र

झारखण्ड में शानदार ई गवर्नेंस का उदाहरण पेश करने वाले आईएएस ऑफिसर सुनील कुमार वर्णवाल 1997 बैच के टॉपर रहे हैं। फिलहाल ये झारखण्ड के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव हैं। इनकी गिनती सख्त,कर्मठ और अनुशासनप्रिय अधिकारियों में की जाती है। ये यह सुनिश्चित करते हैं कि सरकारी जनोपयोगी योजनाओं का लाभ समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे आदमी तक कैसे पहुंचे। बिहार के भागलपुर में पले-बढ़े सुनील कुमार वर्णवाल बचपन से ही काफी मेधावी रहे हैं।

इन्होंने पटना साइंस कॉलेज से इंटरमीडियेट की परीक्षा पास कर ली लेकिन उम्र कम होने के कारण आईआईटी एंट्रेंस नहीं दे पाये। प्रतिष्ठित आईएसएम धनबाद से तीन गोल्ड मेडल्स के साथ पेट्रोलियम इंजीनियरिंग करने के बाद इन्होंने गैस ऑथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में नौकरी ज्वाइन कर ली। इन्होंने मात्र 19 साल की उम्र में इंजीनियरिंग कर ली थी इसलिए दो साल तक आईएएस की परीक्षा में बैठ नहीं सके। नौकरी करते-करते इन्होंने आईएएस की परीक्षा दी और टॉपर बन कर अपना सपना पूरा किया। इन्होंने आईएसएम से ही पीएचडी की। वर्ष 2013 में इन्होंने रांची विश्वविद्यालय से एलएलबी किया और वर्ष 2014 में नेशनल युनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर व हॉर्वर्ड युनिवर्सिटी के संयुक्त कार्यक्रम में पब्लिक मैनेजमेंट में मास्टर्स डिग्री हासिल किया। इन्हें आईएसएम धनबाद ने विशिष्ट एलुमनस अवॉर्ड से भी सम्मानित किया है।

रांची के एसडीएम से लेकर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव तक का सफ़र सुनील कुमार वर्णवाल के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहा। इन्होंने झारखण्ड सरकार के विभिन्न कार्यक्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान दिया। इनकी योग्यता और क्षमता को ध्यान में रखते हुए इन्हें एक साथ चार विभागों का प्रमुख तक बनाया गया।

सुनील कुमार वर्णवाल ने झारखण्ड सरकार के उल्लेखनीय कार्यक्रम 'मोमेंटम झारखंड' और ऐसी परियोजनाओं में काम करके खासी प्रशंसा हासिल की। ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में इनके अभूतपूर्व योगदान के लिये इन्हें भारत सरकार से नेशनल ई-गवर्नेंस अवॉर्ड भी मिल चुका है। इसके अलावे इन्हें राष्ट्रपति के हाथों जनगणना का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। बतौर महानिदेशक इन्होंने राज्य की जेलों में अभूतपूर्व सुधार किये। राज्य में औद्योगिक सुधार और निवेश लाने के लिये इन्होंने लगभग हर क्षेत्र में झारखंड सरकार की स्पष्ट नीतियां बनवायीं। टेक्सटाइल नीति, आईटी नीति, ईडीएसएम नीति, बीपीओ नीति, स्टार्टअप नीति, बीपीओ नीति जैसी कई पॉलिसियों को इन्होंने खुद तैयार कर लागू करवाया।

अन्य प्रमुख नामः

शाश्वत मिश्रा
अश्विनी कुमार
संदीप कुमार
धनंजय द्विवेदी
देवेश कुमार

(इस श्रेणी के सभी प्रमुख ब्यूरोक्रेटस की पूरी प्रोफाइल fameindia.co पर पब्लिश की जा रही है।)

फेम इंडिया मैगजीन- एशिया पोस्ट के प्रमुख मापदंडः

- दूरदर्शिता - ✓
- उत्कृष्ट सोच - ✓
- जवाबदेह - ✓
- गंभीरता - ✓
- शानदार गवर्नेंस - ✓
- व्यवहार कुशलता - ✓
- फैसला लेने की क्षमता - ✓

इन सात मुख्य बिंदुओं पर किये गये वार्षिक सर्वे 'असरदार ब्यूरोक्रेट्स -2019' में सुनील कुमार वर्णवाल प्रमुख स्थान पर हैं।

सर्वे स्रोत :- विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की राय पर आधारित

हर पद पर उम्दा हैं राघवेंद्र कुमार सिंह

उम्दा
★★★★★

मध्य प्रदेश के तेजतर्रार ब्यूरोक्रेट राघवेंद्र कुमार सिंह को व्यवहार कुशल और जवाबदेह कार्यशैली का अधिकारी माना जाता है। ये देश के उन आईएएस आफिसर्स में शामिल है जो एक ही शहर के सब-डिविजनल आफिसर, सीईओ, कलेक्टर और कमिश्नर चारों ही पद पर बारी बारी रह चुके है। राघवेंद्र की पोस्टिंग वर्ष 2000 में इंदौर के एसडीओ, वर्ष 2010 में कलेक्टर और साल 2018 में डिविजनल कमिश्नर के पद पर हुई।

मध्य प्रदेश के मूल निवासी राघवेंद्र कुमार सिंह का चयन सिविल सर्विसेज के लिए मध्यप्रदेश कैडर के लिए ही हुआ। ये टाप रैंकिंग से सिविल इंजीनियरिंग में बी टेक और मैटेरियल मैनेजमेंट में एम टेक है। पढ़ाई में मेधावी और अपने सपनों को पंख देने के लिए राघवेंद्र ने प्रशासनिक सेवा की राह चुनी और 1997 में आईएएस के लिए चुने गए। राघवेंद्र ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर कभी नहीं रहे हैं। हिंदी और अंग्रेजी भाषा के बढ़िया जानकार राघवेंद्र वर्तमान में राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के आयुक्त है। इनके पास राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के परियोजना संचालक का अतिरिक्त प्रभार भी है। इस पद पर इनकी नियुक्ति इसी वर्ष जनवरी 2019 में राज्य में नई सरकार बनने के बाद ही हुई है। इससे पूर्व ये इंदौर के डिविजनल कमिश्नर और उससे पहले इंदौर में ही वाणिज्य कर आयुक्त के पद पर पदस्थापित थे।

राघवेंद्र राज्य के कई जिलों के जिलाधिकारी रहे हैं जिनमें शहडोल, दामोह, सेहोर और इंदौर जिले प्रमुख हैं। जनता से सरकार के संवाद की प्रक्रिया को सरल बनाने और विकास कार्यों के निपटारे में तेजी लाने में इन्होंने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई और बताया जाता है कि हर पोस्टिंग में इनकी छवि एक कुशल, शालीन और जनता से जुड़े प्रशासनिक अधिकारी की रही। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंदौर से लीडरशिप डैवलपमेंट प्रोग्राम और प्रोजेक्ट एप्राइजल एंड मैनेजमेंट की ट्रेनिंग ली है। राघवेंद्र कुमार सिंह राज्य में स्टेट इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन में मैनेजिंग डायरेक्टर और एमपी पश्चिम विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के सीएमडी रहे हैं।

राघवेंद्र को मप्र पर्यटन विकास निगम का प्रबंध निर्देशक की जिम्मेदारी दी गई जिसे इन्होंने बखूबी निभाया और मध्यप्रदेश पर्यटन को एक नई ऊंचाई प्रदान की। चाहे वो मध्यप्रदेश पर्यटन को लेकर जारी वीडियो हो या प्रचार लोगों को आकर्षित करने के लिए ये काफी प्रभावी रहे। इससे मध्यप्रदेश के खजाने में भी वृद्धि हुई। हर पद पर इन्होंने प्रशासनिक दक्षता का उम्दा प्रदर्शन किया।

अन्य प्रमुख नामः

सौरभ विजय
आकाश त्रिपाठी
विशाल गगन
विशाल चौहान
आनंदराव विष्णु पाटिल

(इस श्रेणी के सभी प्रमुख ब्यूरोक्रेटस की पूरी प्रोफाइल fameindia.co पर पब्लिश की जा रही है।)

फेम इंडिया मैगज़ीन-एशिया पोस्ट के प्रमुख मापदंडः

- दूरदर्शिता - ✓
- उत्कृष्ट सोच - ✓
- जवाबदेह - ✓
- गंभीरता - ✓
- शानदार गवर्नेंस - ✓
- व्यवहार कुशलता - ✓
- फैसला लेने की क्षमता - ✓

इन सात मुख्य बिंदुओं पर किये गये वार्षिक सर्वे 'असरदार ब्यूरोक्रेट्स -2019' में राघवेंद्र कुमार सिंह प्रमुख स्थान पर हैं।

सर्वे स्रोत :- विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की राय पर आधारित

बेहतर नीति निर्माता व सुलझे हुए ब्यूरोक्रेट हैं पंकज कुमार

शानदार

बिहार कैडर के 1997 बैच के आईएएस पंकज कुमार को एक सुलझा हुआ समझदार अधिकारी माना जाता है। ये तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त हैं और अपनी प्रशासनिक क्षमता के लिये पहचाने जाते हैं। बिहार के बांका में 1 जनवरी 1970 को एक साधारण मध्यमवर्गीय परिवार में जन्मे पंकज बचपन से ही मेधावी छात्र थे। इन्होंने बीआईटी सिंदरी से सिविल इंजीनियरिंग में बी-टेक प्रथम श्रेणी से करने के बाद आईआईटी दिल्ली से सॉइल इंजीनियरिंग में एमटेक भी किया।

सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय से जुड़े, फिर भारतीय इंजीनियरिंग सेवा में चयनित हुए और रेलवे से जुड़े। इन्होंने वर्ष 1997 में यूपीएससी की परीक्षा पास की।

पहली पोस्टिंग बतौर सिविल एसडीओ धनबाद हुई। कोल माफिया पर ऐसी लगाम लगायी कि दो महीने में ही पलामू तबादला हो गया। झारखंड बंटवारे के बाद ये बिहार कैडर में ही रहे और इन्हें गोपालगंज, सारण, पूर्णिया, मधुबनी, नवादा और समस्तीपुर जैसे जिलों की कमान सौंपी गयी। ये जहां रहे सरकार और जनता के हित में कार्य किया और भूमिहीनों के बीच जमीनों का आवंटन करवाया। इन्हें बिहार स्टेट क्रेडिट एंड इंवेस्टमेंट कॉरपोरेशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, को-आपरेटिव सोसायटी का रजिस्ट्रार, का पद भी सौंपा गया।

वर्ष 2012 में इनकी पोस्टिंग पूर्णिया के डिविजनल कमिश्नर के तौर पर हुई तो वहां भूमाफिया ने गरीबों की जमीनें हड़प रहे थे। इन्होंने एक अभियान चलाकर भूमाफियाओं को जेल भेज कर गरीबों को उनकी जमीनें 'दखल देहानी' के तहत वापस दिलवायीं। बाद में सरकार ने इसी तर्ज पर पूरे प्रदेश में ऑपरेशन दखल देहानी चलवाया। ये जब खाद्य एवम् उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव बने तो वहां राशन माफिया का राज था और निगम को करोड़ों का नुकसान हो रहा था। इन्होंने राशन वितरण व्यवस्था का कंप्युटरीकरण कर गाड़ियों में जीपीएस ट्रैकिंग लगवा दी तो सारी व्यवस्था सुधर गयी इन्होंने ई-चलान और डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करवा कर कालाबाजारियों का पूरी तरह सफाया कर दिया। ये पर्यटन विभाग के सचिव भी रहे।

पंकज कुमार ने प्रशासनिक दक्षता बनाए रखने के लिये समय-समय पर कई ट्रेनिंग और कोर्स किये हैं जिनमें टाटा मैनेजमेंट ट्रेनिंग सेंटर से डेवलपिंग लीडरशिप एक्सिलेंस प्रोग्राम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट से प्रोजेक्ट एंड रिस्क एनालिसिस, आईआईएम बैंगलोर से एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट आदि प्रमुख हैं। इन्हें जनता से जुड़े ब्यूरोक्रेट के तौर पर जाना जाता है।

अन्य प्रमुख नाम:

मनीष ठाकुर
अराधना पटनायक
मनीष मुदगल
ऋत्विक रंजन पांडेय
राजीव कुमार मित्तल

(इस श्रेणी के सभी प्रमुख ब्यूरोक्रेट्स की पूरी प्रोफाइल fameindia.co पर पब्लिश की जा रही है।)

फेम इंडिया मैगजीन- एशिया पोस्ट के प्रमुख मापदंड:

- दूरदर्शिता - ✓
- उत्कृष्ट सोच - ✓
- जवाबदेह - ✓
- गंभीरता - ✓
- शानदार गवर्नेंस - ✓
- व्यवहार कुशलता - ✓
- फैसला लेने की क्षमता - ✓

इन सात मुख्य बिंदुओं पर किये गये वार्षिक सर्वे 'असरदार ब्यूरोक्रेट्स -2019' में पंकज कुमार प्रमुख स्थान पर हैं।

सर्वे स्रोत :- विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की राय पर आधारित

FAME INDIA

ऊर्जावान और कार्यकुशल हैं संदीप कुमार सुल्तानिया

ऊर्जावान
★★★★★

तेलंगाना कैडर के आईएएस संदीप कुमार सुल्तानिया को तेज-तर्रार व ऊर्जावान अधिकारियों में से माना जाता है। ये राज्य के मुख्यमंत्री के सचिव हैं और कई विभागों में सेक्रेटरी भी। ये प्रदेश की प्रतिष्ठित पीवी नरसिंहाराव वेटनरी युनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी हैं। 20 नवंबर 1971 को बिहार में पैदा हुए संदीप कुमार सुलतानिया एक मेधावी छात्र रहे हैं और इन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अलावे कॉस्ट अकाउंटेंसी व कंपनी सेक्रेटरीशिप भी कर रखी है।

संदीप कुमार सुल्तानिया को 1998 बैच में आईएएस में चुने जाने के बाद इन्हें आंध्र प्रदेश कैडर मिला तो इन्होंने सबसे पहले तेलुगू सीखी। आज ये सलीकेदार तेलुगू बोलते हैं। इन्होंने आंध्र प्रदेश में चित्तूर के ऐडिशनल कलेक्टर के तौर पर प्रशासन की शुरुआत की। इसके बाद करीमनगर, निजामाबाद, विशाखापट्टनम आदि जिलों में प्रशासन से जुड़े रहने के बाद ये वर्ष 2007 में आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के एक्जीक्युटिव डायरेक्टर बनाये गये। इस दौरान इन्होंने प्रदेश में उद्योगों के विकास के लिये कई गंभीर प्रयास किये। वर्ष 2008 में करीमनगर के जिलाधिकारी बने और फिर वर्ष 2010 में प्रदेश पर्यटन विकास कॉरपोरेशन के उपाध्यक्ष व मैनेजिंग डायरेक्टर का पद मिला। इनके कार्यकाल में आंध्र-प्रदेश ने खुद को देश के टूरिज्म मैप पर 'गेटवे ऑफ साउथ' के तौर पर स्थापित किया।

प्रदेश विभाजन के बाद संदीप कुमार सुल्तानिया ने तेलंगाना कैडर चुना और करीब दो वर्षों तक तेलंगाना के ट्रांस्पोर्ट कमिश्नर रहे। इस दौरान ये अपने सुधारात्मक उपायों, खासकर एम वैलेट के कारण काफी चर्चित रहे। इस ऐप्प पर लांच होने के दिन ही करीब 70 हजार लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया और महीने भर में ये आंकड़ा 10 लाख पर था। नवंबर 2016 में ये वित्त सचिव बनाये गये।

मार्च 2018 में संदीप कुमार सुल्तानिया की क्षमताओं और दूरदर्शिता को देखते हुए मुख्यमंत्री के सचिव पद पर नियुक्त किया गया। ये सभी विभागों के समन्वयन और सुशासन के अनुभवी अधिकारी हैं। तेलंगाना के विकास के लिये केंद्र से सहयोग रखने और मुख्यमंत्री की गरिमा बनाये रखने की चुनौती है।

अन्य प्रमुख नाम:

वैभव गालरिया
संतोष डी विंध्य
एन गुलजार
नयन स्वरूप निगम
सुमेर सिंह गुर्जर

(इस श्रेणी के सभी प्रमुख ब्यूरोक्रेटस की पूरी प्रोफाइल fameindia.co पर पब्लिश की जा रही है।)

फेम इंडिया मैगज़ीन- एशिया पोस्ट के प्रमुख मापदंडः

दूरदर्शिता - ✓
उत्कृष्ट सोच - ✓
जवाबदेह - ✓
गंभीरता - ✓
शानदार गवर्नेंस - ✓
व्यवहार कुशलता - ✓
फैसला लेने की क्षमता - ✓

इन सात मुख्य बिंदुओं पर किये गये वार्षिक सर्वे 'असरदार ब्यूरोक्रेट्स -2019' में संदीप कुमार सुल्तानिया प्रमुख स्थान पर हैं।

सर्वे स्रोत :- विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की राय पर आधारित

होनहार ब्यूरोक्रेट की लिस्ट में शामिल हैं ऋचा बागला

काबिल

★★★★★

ऋचा बागला को ज्वाइंट सेक्रेट्री स्तर की सक्रिय व उपयोगी अधिकारियों में से माना जाता है। ये विकास संबंधी कई क्षेत्रों में कार्यरत रही हैं जिनमें सामाजिक व आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, विकास, सफल प्रशासन और मूल्यांकन की योजनाएं तैयार करना और इन्हें कार्यरूप देना आदि शामिल हैं। इन्हें मानव संसाधन प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, ग्रामीण व शहरी सुविधाओं के प्रबंधन का बेहतर अनुभव है। दिल्ली में पली-बढ़ी ऋचा बागला ने दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज से जूलॉजी में बीएससी और एमएससी की डिग्री हासिल की।

ऋचा बागला को 1999 बैच में आईएएस की परीक्षा पास करने के बाद महाराष्ट्र कैडर मिला। इन्होंने बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में पीएचडी की डिग्री हासिल की और भारतीय विदेश व्यापार संस्थान से विश्व व्यापार में सर्टिफिकेट अर्जित किया। ये आईआईएम बैंगलोर से पीपीपी व ड्यूक विश्वविद्यालय, कैरोलिना-अमेरिका से लोक नीति के सर्टिफिकेट भी हासिल कर चुकी हैं। ऋचा सुशिक्षित और सुप्रशिक्षित अधिकारी के तौर पर जानी जाती है।

महाराष्ट्र सरकार में इनकी पहचान एक कार्यकुशल और मिलनसार अधिकारी की रही है। शुरुआती दौर में प्रशिक्षण और प्रोबेशन के बाद इन्होंने प्रदेश के कई जिलों व सार्वजनिक प्रतिष्ठानों की कमान संभाली जिनमें वर्ष 2004 में जिला परिषद, सांगली की सीईओ एक महत्वपूर्ण मुकाम रहा। वहां इन्होंने शहरी व ग्रामीण इलाकों में शिक्षा, स्वच्छता, जल प्रबंधन, स्वास्थ्य, कृषि विकास आदि में अपने शानदार गवर्नेंस की छाप छोड़ी। वर्ष 2004 में ये औरंगाबाद डिवीजन सेल्स टैक्स की ज्वाइंट कमिश्नर बनीं। यहां इन्होंने आठ जिलों में लगभग एक लाख करदाताओं से पारदर्शी व सुविधाजनक तरीके से वैट वसूलने में सफलता हासिल की। वर्ष 2007 में ये औरंगाबाद की एडिश्नल कलेक्टर बनीं और वर्ष 2009 से 2011 तक अमरावती की जिलाधिकारी रहीं।

तकरीबन एक साल स्टडी लीव पर रहने के बाद सितंबर 2012 में ऋचा बागला एडिशनल कमिशनर और विदर्भ स्थायी विकास बोर्ड की मेंबर सेक्रेटरी बनायी गयीं। जून 2013 में इन्हें महाराष्ट्र का टेक्सटाइल निदेशक बनाया गया। ये इस पद पर मई 2016 तक रहीं और प्रदेश में हथकरघा, पॉवरलूम्स और वस्त्र उत्पादकों के कोऑपरेटिव को बढ़ावा दिया। इसके बाद इन्हें प्रदेश सरकार के खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड का सीईओ बनाया गया।

मार्च 2018 में ऋचा बागला को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भारत सरकार के एटॉमिक एनर्जी मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया गया। ये हेवी वॉटर बोर्ड और अन्य कई विभागों की देखरेख कर रहीं हैं। ऋचा बागला होनहार और काबिल आफिसर है।

अन्य प्रमुख नाम:

डॉ एम बीना
एम एस श्रीकर
शुभा शर्मा
भावना गर्ग
सैयद अली मुर्तजा रिज्वी

(इस श्रेणी के सभी प्रमुख ब्यूरोक्रेटस की पूरी प्रोफाइल fameindia.co पर पब्लिश की जा रही है।)

फेम इंडिया मैगजीन- एशिया पोस्ट के प्रमुख मापदंड:

- दूरदर्शिता - ✓
- उत्कृष्ट सोच - ✓
- जवाबदेह - ✓
- गंभीरता - ✓
- शानदार गवर्नेंस - ✓
- व्यवहार कुशलता - ✓
- फैसला लेने की क्षमता - ✓

इन सात मुख्य बिंदुओं पर किये गये वार्षिक सर्वे 'असरदार ब्यूरोक्रेट्स -2019' में ऋचा बागला प्रमुख स्थान पर हैं।

सर्वे स्रोत :- विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की राय पर आधारित

FAME INDIA

उड़ीसा के सबसे चर्चित और असरदार ब्यूरोक्रेट वी कार्तिकेयन पांडियान

चर्चित
★★★★★

उड़ीसा में सबसे शक्तिशाली युवा के तौर पर मशहूर वी कार्तिकेयन पांडियन एक बेहद समझदार, दूरदर्शी और मृदुभाषी अधिकारी हैं। खास बात यह है कि ये उड़ीसा के मूल निवासी न होते हुए भी एक अरसे से प्रदेश की सत्ता और सत्तारूढ़ पार्टी दोनों के सबसे महत्त्वपूर्ण शख्सियत बने हुए हैं। ये प्रदेश के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के निजी सचिव हैं और उनकी आंख व कान माने जाते हैं।

तमिलनाडु के एक साधारण परिवार में 29 मई 1974 में जन्मे वी कार्तिकेयन पांडियान ने वर्ष 2000 में आईएएस की परीक्षा उत्तीर्ण कर उड़ीसा कैडर में अपना कार्य शुरू किया। अपनी नौकरी के शुरुआती दिनों में ये रायगड़ा, कालाहांडी और धर्मापुरी के सब कलेक्टर रहे और सुंदरगढ़, मयुरभंज व गंजम जिले के जिलाधिकारी बने। इस बीच ये वर्ष 2004 में थोड़े समय के लिये मुख्य चुनाव अधिकारी भी बने और इसके बाद उद्योग विभाग के चीफ जेनरल मैनेजर का पदभार भी संभाला। वर्ष 2011 में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इन्हें अपना निजी सचिव नियुक्त किया और तब से अबतक ये सरकार के सबसे विश्वासपात्र व प्रमुख अधिकारी बने हुए हैं।

लोगों से कम बातचीत करने वाले इस अधिकारी ने हमेशा पब्लिसिटी से दूर रहकर अपने कार्य पर ध्यान दिया। इसके बावजूद इनकी चर्चा सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों ही हलकों में की जाती है। हालांकि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हमेशा से सत्ता चलाने के लिए मंत्रियों और विधायकों से ज्यादा नौकरशाहों पर भरोसा किया है, लेकिन कोई भी अधिकारी कभी भी इतनी चर्चा का विषय नहीं रहा है जितना पांडियन रहे हैं। चाहे पार्टी की बैठक हो या सरकार की, ये हर समय मुख्यमंत्री के ऐन पीछे बैठते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये आम तौर पर शांत रहने वाले मुख्यमंत्री से सबसे ज्यादा बातचीत करने वाले शख्स हैं। ये मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के लिये योजना बनाने और उनकी तैयारियों में डूब जाते हैं। दिन भर ये मुख्यमंत्री की दिनचर्या में शरीक रहते हैं और उनसे किसकी मुलाकात हो और किसकी नहीं, यह भी पांडियान ही तय करते हैं। कहते हैं, 2011 में मुख्यमंत्री पटनायक के निजी सचिव बनने के बाद से उनकी छाया से भी ज्यादा पक्के बन गये हैं। इस भरोसे के पीछे इनकी कर्मठता, ईमानदारी और दूरदर्शिता का सबसे बड़ा हाथ है, तभी ये सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री के सबसे अधिक दिनों तक जुड़े रहने वाले सहयोगी बन पाये हैं।

FAME INDIA

अन्य प्रमुख नाम:

डॉ आर विनोद कुमार
पी हेमलता
राहुल तिवारी
डी आनंदन
अनुराग यादव

(इस श्रेणी के सभी प्रमुख ब्यूरोक्रेटस की पूरी प्रोफाइल fameindia.co पर पब्लिश की जा रही है।)

फेम इंडिया मैगज़ीन- एशिया पोस्ट के प्रमुख मापदंडः

दूरदर्शिता - ✓
उत्कृष्ट सोच - ✓
जवाबदेह - ✓
गंभीरता - ✓
शानदार गवर्नेंस - ✓
व्यवहार कुशलता - ✓
फैसला लेने की क्षमता - ✓

इन सात मुख्य बिंदुओं पर किये गये वार्षिक सर्वे 'असरदार ब्यूरोक्रेट्स -2019' में वी कार्तिकेयन पांडियन प्रमुख स्थान पर हैं।

सर्वे स्रोत :- विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की राय पर आधारित

जवाबदेह कार्यशैली से जाने जाते हैं दीपक अग्रवाल

जवाबदेह

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के आयुक्त दीपक अग्रवाल को एक काबिल आईएएस अधिकारी माना जाता है , कंट्रोवर्सी से दूर सुलझी हुई कार्यशैली इनकी खासियत है । उत्तर प्रदेश कैडर के 2000 बैच के ब्यूरोक्रट दीपक अग्रवाल दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज से साइंस ग्रेजुएट हैं, इन्होंने अमेरिका के करनेगी मेलो यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन साइंस , पब्लिक पालिसी एंड मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट भी किया है ।

वर्तमान में वाराणसी के डिविजनल कमिश्नर बनने से पहले ये सहारनपुर के डिविजनल कमिश्नर थे। मूल रूप से धनबाद निवासी दीपक का जन्म 10 अक्टूबर 1974 को समृद्ध मारवाड़ी परिवार में हुआ, इन्होने शुरू से ही सिविल सर्विस में जाने का मन बना लिया था । हिंदी और अंग्रेजी भाषा की अच्छी समझ रखने वाले अग्रवाल ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, मेरठ के तौर पर हुई । वहां के इनके कार्यकाल को देखते हुए इन्हें चीफ डेवलपमेंट आफिसर के रूप में गाजियाबाद भेजा गया, जहां इन्होंने अच्छा कार्य किया। 2005 में इन्हें महाराजगंज का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाया गया, उसके बाद लगातार इन्हें राज्य के महत्त्वपूर्ण जिलों का जिलाधिकारी नियुक्त किया जाता रहा, जिसमें गाजियाबाद , सीतापुर, मुरादाबाद, फैजाबाद के साथ ही नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) का भी जिलाधिकारी बनाया गया। इन्होंने हर पद पर अपनी जिम्मेदारी बेहतर तरीके से निभाई, इस दौरान ये यमुना एक्सप्रेस-वे अथॉरिटी के चीफ एक्जीक्यूटिव आफिसर भी बनाए गए । इसी दौरान इन्हें करीब एक वर्ष के लिए केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर केंद्रिय राज्य मंत्री (मानव संसाधन विकास) का प्राइवेट सेक्रेटरी भी बनाया गया। वहां से लौटने के बाद इन्हें पुनः राज्य सरकार ने जिलों में महत्त्वपूर्ण कार्यभार सौंपा ।

वर्ष मार्च 2018 में इन्हें राज्य के सबसे महत्त्वपूर्ण डिविजनों में एक वाराणसी डिविजन का कमिश्नर बनाया गया । इनकी नियुक्ति के समय वहां कई चुनौतियां थीं, जिसमें केंद्र और राज्य की योजनाओं को तय समय में पूर्ण गुणवत्ता के साथ लागू करवाने से लेकर बनारस की ट्रेफिक की समस्या, वरूणा कारिडोर का मामला और सबसे प्रमुख समस्या काशी विश्वनाथ मंदिर के विस्तारीकरण की योजना को सुचारू बनाए रखना प्रमुख था । दीपक अग्रवाल ने अपने करीब डेढ़ साल के कार्यकाल में शानदार गवर्नेंस और बेहतर कार्यकुशलता का परिचय दिया है। देश के सबसे हाईप्रोफाइल संसदीय क्षेत्र में दीपक अपनी जवाबदेह कार्यशैली की छाप छोड़ चुके हैं।

अन्य प्रमुख नाम:

टी एन वेंकटेश
अभिनव चंद्रा
द्वारका नाथ मिश्रा
राजकुमार दिनेश सिंह
पीयूष सिंह

(इस श्रेणी के सभी प्रमुख ब्यूरोक्रेटस की पूरी प्रोफाइल fameindia.co पर पब्लिश की जा रही है।)

फेम इंडिया मैगजीन- एशिया पोस्ट के प्रमुख मापदंड:

- दूरदर्शिता - ✓
- उत्कृष्ट सोच - ✓
- जवाबदेह - ✓
- गंभीरता - ✓
- शानदार गवर्नेंस - ✓
- व्यवहार कुशलता - ✓
- फैसला लेने की क्षमता - ✓

इन सात मुख्य बिंदुओं पर किये गये वार्षिक सर्वे 'असरदार ब्यूरोक्रेट्स -2019' में दीपक अग्रवाल प्रमुख स्थान पर हैं।

सर्वे स्रोत :- विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की राय पर आधारित

FAME INDIA

युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत हैं स्मिता सबरवाल की कार्ययोजनाएं

युवा

23 वर्ष की आयु में आईएएस परीक्षा पास करने वाली स्मिता सबरवाल ने यूपीएससी के ऑल इंडिया रैंकिंग में चौथे स्थान पर थी। ये तेलंगाना कैडर की 2001 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। ये लोगो में "पीपल्स ऑफिसर" नाम से भी लोकप्रिय रही हैं। वर्त्तमान में स्मिता मुख्यमंत्री कार्यालय में सेक्रेटरी के पद पर हैं। 19 जून 1977 में दार्जिलिंग में जन्मी स्मिता सबरवाल हैदराबाद के सेंट फ्रांसिस डिग्री कॉलेज से कॉमर्स में ग्रेजुएट हैं।

स्मिता सबरवाल यूपीएससी की परीक्षा पास करने वाली सबसे कम उम्र के अधिकारियो में भी शामिल हैं।

इनकी पहली नियुक्ति चित्तूर जिले में बतौर सब-कलेक्टर हुई । जहां इन्हें भूमि अधिग्रहण प्रबंधन और प्रशासन में अच्छा कार्य किया। इसके बाद इन्होंने ग्रामीण विकास क्षेत्र में बतौर परियोजना निदेशक, डीआरडीऐ में कार्य किया। वारंगल में नगर निगम आयुक्त के रूप में इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान "फण्ड योर सिटी" नामक एक योजना शुरू की, जिसके अंतर्गत बड़ी संख्या में सार्वजानिक उपयोग के कार्य पीपीपी मोड में करवाया गया। इसके बाद इन्होंने वाणिज्य कर, विशाखापट्नम में बतौर उपयुक्त पद संभाला और कुरनूल व हैदराबाद के संयुक्त कलेक्टर के रूप में भी सेवा की। फिर इन्हें अप्रैल 2011 में करीमनगर जिले का डीएम बनाया गया। जहाँ इन्होंने स्वास्थ्य व शिक्षा के क्षेत्र बेहतरीन कार्य किया। यहां इन्होंने हेल्थ केयर सेक्टर में 'अम्माललाना' प्रोजेक्ट की शुरुआत की। इस प्रोजेक्ट की सफलता के चलते स्मिता को प्राइम मिनिस्टर एक्सीलेंस अवार्ड भी दिया गया। स्मिता के करीमनगर में बतौर डीएम तैनात रहने के दौरान ही करीमनगर को बेस्ट टाउन का भी अवॉर्ड भी मिला चुका है। ई गवर्नेंस के उपयोग में इनका कोई सानी नहीं रही है , स्काइप के जरिए इन्होंने सरकारी डॉक्टरों की निगरानी कर डिस्ट्रिक्ट में पब्लिक हेल्थ केयर को पूरी तरह बदल दिया। स्पेशल डिज़ाइन किए गए सॉफ्टवेयर के माध्यम से गवर्नमेंट स्कूलों के परफॉर्मेंस की सर्विलांस से इन्होंने जिलाधिकारी के तौर पर कार्य करते हुए करीमनगर और मेडक जिले की व्यवस्था को बदल दिया, इनके कार्यकाल के दौरान ये दोनों जिलों ने राज्य में शीर्ष स्थान बनाया। स्मिता सभरवाल 2013 में ई-भारत की ई-स्वस्थ्य श्रेणी में डिजिटल पहल के लिए 2013 में और सर्वश्रेष्ठ जिले के लिए मुख्यमंत्री से 21 पॉइंट फ्लैगशिप अवार्ड 2011-12 से भी सम्मानित की जा चुकी है।

अन्य प्रमुख नाम:

डी आनंदन
सुजाता आर कार्तिकेयन
पुजा सिंघल
बी चंद्रशेखर
नीतेश कुमार झा

(इस श्रेणी के सभी प्रमुख ब्यूरोक्रेटस की पूरी प्रोफाइल fameindia.co पर पब्लिश की जा रही है।)

फेम इंडिया मैगज़ीन- एशिया पोस्ट के प्रमुख मापदंड:

दूरदर्शिता - ✓
उत्कृष्ट सोच - ✓
जवाबदेह - ✓
गंभीरता - ✓
शानदार गवर्नेंस - ✓
व्यवहार कुशलता - ✓
फैसला लेने की क्षमता - ✓

इन सात मुख्य बिंदुओं पर किये गये वार्षिक सर्वे 'असरदार ब्यूरोक्रेट्स -2019' में स्मिता सबरवाल प्रमुख स्थान पर हैं।

सर्वे स्रोत :- विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की राय पर आधारित

FAME INDIA

नेक इरादे के साथ विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं नंदिता गुप्ता

इरादे

हिमाचल प्रदेश कैडर के 2001 बैच की आईएएस अधिकारी नंदिता गुप्ता समझदार और कुशल प्रशासक है। वर्त्तमान में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर नई दिल्ली में हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर पदस्थापित नंदिता गुप्ता सेंट स्टीफन कालेज ,दिल्ली यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएट हैं।

जे एनयू से इंग्लिश में पोस्ट ग्रेजुएट और वहीं से समाज शास्त्र में एम फिल नंदिता पढ़ाई में सदैव अव्वल रही है ।

ब्लाक डेवलपमेंट आफिसर, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट से लेकर ज्वाइंट सेक्रेटरी तक का उनका अब तक का सफर शानदार गवर्नेंस, जवाबदेह कार्यशैली और अहम मुद्दों पर त्वरित फैसला लेने की क्षमता को प्रदर्शित करता है । चाहे सोलन में एसडीएम, एडीसी कांगड़ा के तौर पर हो या फिर हमीरपुर और विलासपुर के जिलाधिकारी पद का कार्यकाल नंदिता ने सदैव एक बेहतर प्रशासक की भूमिका निभाई है । राज्य में हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, फाइनेंस, रेवेन्यू, होम, लेबर, इंडस्ट्रीज ये कई विभागों में पदस्थापित रही है, और जानकार बताते हैं हर जगह इनके कार्य को लोगों ने सराहा है । विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से जुड़ी 2007 में इंटरनेशनल लेवल की एक आर्टिकल लिखी - ए सेंश आफ द स्ट्रगल, जिसे स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क प्रेस ने पब्लिश किया ।

इन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर तरीके से जानने समझने के लिए यूएसए से ईएमपीए कोर्स किया है। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने से पहले ये धर्मशाला की डिविजनल कमिश्नर थी। उत्कृष्ट सोच की व्यवहार कुशल नंदिता गुप्ता को ईमानदार और लोकप्रिय ब्यूरोक्रेट माना जाता है। समाचार और मीडिया की चकाचौंध से दूर नंदिता मजबूत इरादों के साथ अपने कार्य में डूबी रहने वाली अधिकारी हैं । इन्हें अर्बन डेवलपमेंट और चाइल्ड एंड फैमिली वेलफेयर के विषय की उत्कृष्ट जानकार ब्यूरोक्रेट बताया जाता है ।

अन्य प्रमुख नामः

दर्पण जैन
डॉ एकरूप कौर
निपुण विनायक
डॉ निधि पांडेय
अमनीत पी कुमार

(इस श्रेणी के सभी प्रमुख ब्यूरोक्रेटस की पूरी प्रोफाइल fameindia.co पर पब्लिश की जा रही है।)

फेम इंडिया मैगजीन- एशिया पोस्ट के प्रमुख मापदंडः

- दूरदर्शिता - ✓
- उत्कृष्ट सोच - ✓
- जवाबदेह - ✓
- गंभीरता - ✓
- शानदार गवर्नेंस - ✓
- व्यवहार कुशलता - ✓
- फैसला लेने की क्षमता - ✓

इन सात मुख्य बिंदुओं पर किये गये वार्षिक सर्वे 'असरदार ब्यूरोक्रेट्स -2019' में नंदिता गुप्ता प्रमुख स्थान पर हैं।

सर्वे स्रोत :- विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की राय पर आधारित

त्वरित फैसला लेने वाले मयंक वरवडे

स्टार

★★★★★

बिहार कैडर के असरदार ब्यूरोक्रेट्स में एक प्रमुख नाम मयंक वरवडे का भी है, 2001 बैच के मयंक को शालीन और गंभीर ब्यूरोक्रेट माना जाता है। मध्य प्रदेश के मूल निवासी मयंक वरवडे ने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से बीटेक और मैनेजमेंट एंड सिस्टम से एम टेक की डिग्री में अव्वल रहने के बाद सिविल सर्विसेज में जाने का निर्णय लिया और 2001 में यूपीएससी के द्वारा आईएएस चुने गए।

बिहार कैडर मिला और पहली पोस्टिंग सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट के तौर पर मधुबनी सदर में हुआ। यह कार्यकाल दो वर्षों का रहा और बतौर एसडीओ इन्होंने यहां खास पहचान बनाई।2005 में इन्हें खगड़िया जिले का जिलाधिकारी बनाया गया, तीन साल के कार्यकाल में मयंक शानदार गवर्नेंस और कार्य कुशलता से आम जनता से जुड़े और विकास के कई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए। बाद में इन्हें भभुआ और जमुई जिले में भी जिलाधिकारी पद की जिम्मेदारी दी गई। ये बिहार में पंचायती राज में डायरेक्टर और लेबर कमिश्नर के पद पर भी रहे हैं। 2013 में ये इंटर स्टेट डेप्यूटेशन पर छत्तीसगढ़ गए, यहां इनका डेप्यूटेशन पांच वर्षों का था। इस दौरान वहां ये एमजीएनआरईजीएस में आयुक्त, नरेगा और पब्लिक इंट्रेक्सन में संचालक के पद पर रहे, इसके बाद स्कूल शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव और राज्य साक्षरता मिशन में डायरेक्टर बनाए गए। हर पद पर इन्होंने अपनी जवाबदेह कार्यशैली का सिक्का जमा दिया।

पांच वर्षों बाद कैडर में वापसी के साथ ही इन्हें भी 2018 में दरभंगा डिविजन का डिविजनल कमिश्नर बनाया गया।लोगों की राय मे विगत डेढ़ वर्षों का इनका यह कार्यकाल सराहनीय है , ये पूरी शालिनता और कर्मठता से अपनी सभी जिम्मेदारियों को निभाने वाले आईएएस अधिकारी के तौर पर जाने जाते हैं।

इनकी फाइनेंस की समझ भी अच्छी है, मयंक वरवडे ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कैपिटल मार्केट्स से फिनांसियल मार्केट रेगुलेशन की एक वर्ष की ट्रेनिंग भी ली है। सजग परन्तु सुलभ मयंक की सबसे बड़ी खासियत आम जनता को सहजता से उपलब्ध रहना है। इन्हें विकास और जनोपयोगी कार्यों के लिए त्वरित फैसला लेने वाला ब्यूरोक्रेट माना जाता है।

अन्य प्रमुख नाम:

सिद्धार्थ जैन
आरती कंवर
विजय नेहरा
जी प्रकाश
शांतनु बसु

(इस श्रेणी के सभी प्रमुख ब्यूरोक्रेटस की पूरी प्रोफाइल fameindia.co पर पब्लिश की जा रही है।)

फेम इंडिया मैगज़ीन- एशिया पोस्ट के प्रमुख मापदंड:

- दूरदर्शिता - ✓
- उत्कृष्ट सोच - ✓
- जवाबदेह - ✓
- गंभीरता - ✓
- शानदार गवर्नेंस - ✓
- व्यवहार कुशलता - ✓
- फैसला लेने की क्षमता - ✓

इन सात मुख्य बिंदुओं पर किये गये वार्षिक सर्वे 'असरदार ब्यूरोक्रेट्स -2019' में मयंक वरवडे प्रमुख स्थान पर हैं।

सर्वे स्रोत :- विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की राय पर आधारित

चुनौतीपूर्ण परिस्थिति को संभालने में माहिर हैं संजीव वर्मा

माहिर

जम्मू और कश्मीर कैडर से 2001 बैच के आईएएस अधिकारी संजीव वर्मा काफ़ी खुश मिजाज एवं अपने काम में सजग और सख्त माने जाते है। सोशल अवेयरनेस से जुड़े कार्यक्रमों में हमेशा सक्रिय योगदान देने वाले संजीव वर्मा ब्लड डोनेशन से लेकर अन्य सोशल वेलफेयर के लिए भी सदैव तत्पर रहते हैं। ये प्रशासनिक व्यस्तताओं के बावजूद सामाजिक जागृति और चेतना फैलाने के लिए समय निकालते हैं, जो एक ब्यूरोक्रेट को असरदार बनाता है।

सार्वजनिक मंचो पर जनसेवा की भावना के लिए लोगों को प्रेरित करने का इनका प्रयास इन्हें एक अलग छवि देता है। जम्मू-कश्मीर के मूल निवासी संजीव ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीई करने के बाद टाप रेंकिंग से मार्केटिंग में मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया। डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी भाषा के जानकार संजीव वर्मा ने 2001 में यूपीएससी की परीक्षा पास की और इन्हें उनका गृह कैडर ही मिला।

वर्तमान में जम्मू डिवीजन के कमिश्नर के तौर पर जुलाई 2018 में संजीव वर्मा की नियुक्ति हुई। ये बेहतर नेतृत्व और शानदार गवर्नेंस वाले आईएएस अधिकारी के तौर पर राज्य में जाने जाते हैं। इनकी पहली पोस्टिंग रियासी के सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट के तौर पर हुई थी, वहां ये दो वर्षों तक रहे। इस दौरान इन्होंने बेहतर कार्यशैली से प्रशासन पर लोगों का भरोसा जमाया।

2006 में इन्हें स्टेट रोड कारपोरेशन का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया। इसके बाद इनकी पोस्टिंग डिप्टी कमिश्नर के पद पर जम्मू-कश्मीर के विभिन्न जिलों रियासी, कठुआ, जम्मू आदि में हुई। लेह में डिप्टी कमिश्नर के तौर पर इनकी पोस्टिंग हिल काउंसिंल में चुनाव के वक्त और 2010 में बाढ़ के बाद पुनर्वास कार्यक्रम को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए हुई। इसके अलावा इन्होंने कमिश्नर और सेक्रेटरी के रूप में राज्य के कई विभागों में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है जिनमें पीडब्ल्यूडी, पीएचई, सोशल वेलफेयर और हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट प्रमुख है। हर पोस्टिंग के साथ इनकी गवर्नेंस, दूरदर्शिता और कार्य कुशलता में निखार आता चला गया। इन्हें राज्य के विभिन्न हिस्सों से जुड़ने समझने का मौका मिला, और उनसे आने वाले दिनों में और ज्यादा सफलता और शिखर पर जाने की अपेक्षा की जाती है।

अन्य प्रमुख नाम:

डॉ कृष्ण कांत पाठक
अर्पणा यू
अमित गुप्ता
रणवीर प्रसाद
मनीष चौहान

(इस श्रेणी के सभी प्रमुख ब्यूरोक्रेटस की पूरी प्रोफाइल fameindia.co पर पब्लिश की जा रही है।)

फेम इंडिया मैगजीन- एशिया पोस्ट के प्रमुख मापदंड:

दूरदर्शिता -	✓
उत्कृष्ट सोच -	✓
जवाबदेह -	✓
गंभीरता -	✓
शानदार गवर्नेंस -	✓
व्यवहार कुशलता -	✓
फैसला लेने की क्षमता -	✓

इन सात मुख्य बिंदुओं पर किये गये वार्षिक सर्वे 'असरदार ब्यूरोक्रेट्स -2019' में संजीव वर्मा प्रमुख स्थान पर हैं।

सर्वे स्रोत :- विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की राय पर आधारित

FAME INDIA

राज्य में प्रोग्रेसिव ब्यूरोक्रेसी की मिसाल हैं राधिका झा

प्रोग्रेसिव
★★★★★

राधिका झा को देश की उन गिने-चुने अधिकारियों में जाना जाता है जिन्होंने अपनी नौकरी को सत्ता की बजाय सेवा का जरिया माना। प्रदेश के विकास को समर्पित इस अधिकारी ने उत्तराखंड में कर्मठता की वो दास्तां लिखी है जो लंबे समय तक मिसाल बन कर रहेगी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जन्मी राधिका शुक्ला (झा) मेघावी छात्रा थीं और दिल्ली के प्रतिष्ठित लेडी श्रीराम कॉलेज से ग्रेजुएशन व इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में एमए किया।

आईएएस में चुने जाने के बाद 2002 बैच में सिक्किम कैडर की अधिकारी बनीं और उस पर्वतीय राज्य में सात वर्षों तक लगन-पूर्वक कार्य किया। इस दौरान ये पूर्वी सिक्किम, पश्चिमी सिक्किम, सिक्किम हाउस आदि में तैनात रहीं।

राधिका झा को वर्ष 2009 में उत्तराखंड कैडर मिला तो वहां शिक्षा विभाग से जुड़ीं। वर्ष 2010 में ये टिहरी जिले की जिलाधिकारी बनीं जहां हर गांव में ग्रामसभा का आयोजन कर ग्रामवासियों को एक नयी पहचान दी। वर्ष 2011 में शहरी विकास विभाग से जुड़ीं जहां इन्होंने स्वच्छ भारत अभियान से वर्षों पहले इधर-उधर कूड़ा फेंकने व थूकने के खिलाफ़ नियम बनाने का प्रस्ताव रखा था। वर्ष 2013 में इन्हें प्रदेश के सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान दोनों का प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया गया।इन्होंने इस अवसर पर एक महत्वाकांक्षी प्रोग्राम 'सपनों की उड़ान' लांच किया जिसकी चर्चा आज भी होती है। इसमें कॉरपोरेट घरानों की मदद से गांवों और झुग्गी-बस्तियों के बच्चों को मोबाइल विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा की मुख्य-धारा से जोड़ा गया। वर्ष 2014-15 में शहरी विकास और पर्यटन विभाग से जुड़ीं। वर्ष 2015 में ये भारत सरकार के इंटीग्रेटेड पॉवर डेवलपमेंट स्कीम की डायरेक्टर बनीं।

वर्ष 2017 में राधिका झा को उत्तराखंड वापस बुला कर मुख्यमंत्री का सचिव बनाया गया। प्रदेश सरकार के सभी कर्मियों में स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिये इन्होंने 'उत्कर्ष' नामक मॉनीटरिंग डैशबोर्ड तैयार किया और बढ़िया कार्य करने वाले विभागों के लिये सीएम अवॉर्ड भी शुरू करवाया। इन्हें प्रदेश के ऊर्जा विभाग की भी कमान सौंपी गयी। सौभाग्य, उजाला मित्र, पिरुल पॉवर प्लांट, सौर प्लांट जैसे कई प्रयासों से इन्होंने प्रदेश में बिजली की स्थिति में काफी सुधारा है। हाल ही में बिजली चोरी रोकने के लिये 'ऊर्जागिरी' अभियान चलाया है जो काफी लोकप्रिय हो रहा है। प्रदेश के विकास के लिये लागू कई प्रमुख योजनाओं और सरकार के लगभग सभी विभागों के सफल कार्यान्वयन के लिये इन्हें जिम्मेदार माना जाता है।

अन्य प्रमुख नाम:

सौरभ गौड़
संजय कुमार अग्रवाल
डॉ प्रतिभा एस कुमार
लोचन सेहरा
अर्चना पटनायक

(इस श्रेणी के सभी प्रमुख ब्यूरोक्रेट्स की पूरी प्रोफाइल fameindia.co पर पब्लिश की जा रही है।)

फेम इंडिया मैगज़ीन-एशिया पोस्ट के प्रमुख मापदंड:

- दूरदर्शिता - ✓
- उत्कृष्ट सोच - ✓
- जवाबदेह - ✓
- गंभीरता - ✓
- शानदार गवर्नेंस - ✓
- व्यवहार कुशलता - ✓
- फैसला लेने की क्षमता - ✓

इन सात मुख्य बिंदुओं पर किये गये वार्षिक सर्वे 'असरदार ब्यूरोक्रेट्स -2019' में राधिका झा प्रमुख स्थान पर हैं।

सर्वे स्रोत :- विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की राय पर आधारित

अनुशासन के बूते सफलता की ऊंचाइयों को छूती ऋतु सैन

आइकॉन

छत्तीसगढ़ के बस्तर और दंतेवाड़ा ज़िलों का नाम आते ही नक्सलियों का आतंक और उनके खूनी हमलों की तस्वीर सामने आती है। इसी इलाके में लोगों को जागरुक करने , महिलाओं को उनके पैरों पर खड़ा करने और स्वच्छता, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने की बेहतरीन मिसाल गढ़ी है ऋतु सैन ने। ऋतु सैन 2003 बैच की छत्तीसगढ़ कैडर की आईएएस हैं।

इन दिनों देश की राजधानी दिल्ली में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में बतौर डायरेक्टर काम रहीं हैं. इससे पहले ऋतु छत्तीसगढ़ भवन की एडिशनल रेजिडेंट कमिश्नर थीं। ये छत्तीसगढ़ के कोरिया और सरगुजा जैसे ज़िलों में कलेक्टर रह चुकी हैं।

राजस्थान की रहने वालीं ऋतु सैन ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से एम फिल किया है। ऋतु इरादों की पक्की और लगन की मज़बूत ऑफिसर मानी जातीं हैं। कहा ये जाता है कि जब ये सरगुजा की कलेक्टर बनीं तो शहर बदबूदार ढेर से पटा पड़ा था। इन्होंने उसे साफ करने का बीड़ा उठा लिया। नतीजा ये रहा कि 2018 में अम्बिकापुर देश के सबसे छोटे शहरों में सफाई के लिहाज से नंबर वन माना गया। बतौर आईएएस अधिकारी ऋतु सैन ने वो तमाम काम किये जिनके जरिये लोगों के बीच प्रशासन की साख और छवि निखरती है, मज़बूत होती है। ऋतु सैन का काम महिलाओं की स्थिति सुधारने को लेकर काफी सराहनीय माना जाता है। इन्हें रोज़गार देने और मुसीबत में पड़ी विधवाओं या उन जैसी महिलाओं को मुख्यधारा में लाने के लिए ऋतु ने दिन-रात एक कर दिया। ऋतु सैन छत्तीसगढ़ के एक बड़े दायरे में महिला कल्याण, उत्थान और विकास का पर्याय मानी जाती हैं।

ऋतु सैन जब छत्तीसगढ़ में राज्य आजीविका मिशन की निदेशक थीं तो उस समय बेहतरीन काम के लिए प्रदेश को नेशनल अवार्ड मिला था। 2014 में इन्हें बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस अवार्ड और 2011 में दृष्टिहीनों के लिए कोरिया ज़िला में काम करने की खातिर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए सम्मानित किया गया। 2009 में ऋतु सैन को प्राशसनिक काम के लिए प्रधानमंत्री लोक प्रशासन उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया । ये पुरस्कार 2007-08 के बीच इनके शानदार काम को देखते हुए दिया गया था। ऐसे और कई सम्मान हैं जो ऋतु सैन की प्रशासनिक दक्षता और लक्ष्य आधारित काम के सम्मान में दिए गए हैं।

अन्य प्रमुख नाम:

लोकेश कुमार सिंह
संध्या भुल्लर
प्रवीण भाई के सोलंकी
अजीत बाला जी जोशी
एम शंकरनारायणन

(इस श्रेणी के सभी प्रमुख ब्यूरोक्रेट्स की पूरी प्रोफाइल fameindia.co पर पब्लिश की जा रही है।)

फेम इंडिया मैगजीन- एशिया पोस्ट के प्रमुख मापदंड:

- दूरदर्शिता - ✓
- उत्कृष्ट सोच - ✓
- जवाबदेह - ✓
- गंभीरता - ✓
- शानदार गवर्नेंस - ✓
- व्यवहार कुशलता - ✓
- फैसला लेने की क्षमता - ✓

इन सात मुख्य बिंदुओं पर किये गये वार्षिक सर्वे 'असरदार ब्यूरोक्रेट्स -2019' में ऋतु सैन प्रमुख स्थान पर हैं।

सर्वे स्रोत :- विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की राय पर आधारित

FAME INDIA

सुधारवादी पर प्रशासनिक तौर पर सख्त हैं ऋतु महेश्वरी

सुधारवादी

सख्त तेवर, ईमानदारी और सबसे पहले ज़िम्मेदारी- इन तीन बातों से अपनी पहचान बनाने वाली आईएएस ऑफिसर ऋतु माहेश्वरी को प्रशासनिक हलकों में एक बेहद काबिल और कड़क अधिकारी माना जाता है। ऋतु माहेश्वरी को जो भी ज़िम्मेदारी मिलती है, पहले दिन से ही इनके प्रशासनिक क्षेत्र में आने वाले सारे विभाग नियम और कानून के ढांचे में काम करना शुरू कर देते हैं। कोताही, लापरवाही और हीलाहवाली को तनिक भी बर्दाश्त न करने वाली ऋतु माहेश्वरी काम के प्रति समर्पित और डेडलाइन के मुताबिक काम करने वाली ऑफिसर हैं।

उत्तर प्रदेश में नोएडा अथॉरिटी की सीईओ की ज़िम्मेदारी संभालते ही ऋतु माहेश्वरी ने सरकार से ठगी करने वाले और लोगों का पैसा लेकर भी इन्हें मकान न देने वाले बिल्डरों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। सूत्रों के मुताबिक इन्होंने ऐसे तमाम बिल्डरों की लिस्ट बना ली जिन पर ऑथोरिटी का भी भारी भरकम पैसा बाकी है।यह रकम लगभग 16 हज़ार 500 करोड़ बतायी जा रही है। इससे पहले ये मेरठ और हापुड़-पिलखुआ प्राधिकरण में उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं।

पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से ग्रैजुएट ऋतु माहेश्वरी का सरकारी पैसों की वसूली करवाने में शानदार ट्रैक रिकॉर्ड रहा है।जब ये उत्तर प्रदेश सरकार की कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी में काम कर रही थीं तब इन्होंने बिजली चोरी पर न सिर्फ लगाम कस दी थी बल्कि बिजली की चोरी रोकने के लिये बड़े पैमाने पर डिजिटल मीटर लगवा दिये। नतीजा ये हुआ कि कंपनी का नुकसान 30 प्रतिशत से घटकर 15 प्रतिशत पर आ गया।

मूल रूप से हरियाणा के पंचकुला की रहने वाली ऋतु माहेश्वरी 2003 बैच की उत्तर प्रदेश कैडर की आईएएस हैं। ये ग़ाज़ियाबाद, गाज़ीपुर, शाहजहांपुर, फिरोजाबाद और पीलीभीत में डीएम रह चुकी हैं। साथ ही इन्होंने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में भी प्रमुख कार्य किया है । खास बात यह है कि ये अपने सख्त स्वभाव और भ्रष्टाचारियों के आगे न झुकने वाली प्रवृत्ति को प्रकृति प्रदत गुण मानती है । लोगों का मानना है कि जन सेवा और राष्ट्र विकास ही इनकी प्राथमिकता है और ये इसके इसके लिए सदैव प्रयासरत रहती हैं । इन्हें सरकारी कामकाज को कंप्यूटराइज्ड करने के लिए ई गवर्नेंस में नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। यूएन हेडक्वार्टर , न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव द्वारा स्वास्थय के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने के लिए इन्हें “अवार्ड फार एक्सिलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन”से सम्मानित किया जा चुका है । यह इनके स्वास्थय के क्षेत्र में नए प्रयोग आरोग्यम के लिए मिला । आरोग्यम प्रोजेक्ट को अब इनके नाम से पेटेंट भी कर दिया गया है ।

अन्य प्रमुख नाम:

अविनाश चंपावत
परदेशी सिद्धार्थ कोमल
कांगला रीना बाबासाहेब
अवंतिका सिंह अलख
स्वरूप पी

(इस श्रेणी के सभी प्रमुख ब्यूरोक्रेटस की पूरी प्रोफाइल fameindia.co पर पब्लिश की जा रही है।)

फेम इंडिया मैगज़ीन- एशिया पोस्ट के प्रमुख मापदंड:

- दूरदर्शिता - ✓
- उत्कृष्ट सोच - ✓
- जवाबदेह - ✓
- गंभीरता - ✓
- शानदार गवर्नेंस - ✓
- व्यवहार कुशलता - ✓
- फैसला लेने की क्षमता - ✓

इन सात मुख्य बिंदुओं पर किये गये वार्षिक सर्वे ‘असरदार ब्यूरोक्रेट्स -2019’ में ऋतु माहेश्वरी प्रमुख स्थान पर हैं।

सर्वे स्रोत :- विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की राय पर आधारित

बेहतर संवाद क्षमता के धनी हैं अनुपम कुमार

संवाद क्षमता

★★★★★

असरदार ब्यूरोक्रेट्स में एक नाम अनुपम कुमार का है, बिहार के मुख्यमंत्री के सचिव 2003 बैच के अनुपम को सुलझा हुआ और कर्त्तव्यनिष्ठ ब्यूरोक्रेट माना जाता है। उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अनुपम कुमार ने लखनऊ विश्वविद्यालय से फिजिक्स में अव्वल दर्जे से एमएससी किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय में ही भैतिकी विभाग में अध्यापन का कार्य भी किया।

अनुपम कुमार सिविल सर्विसेज के लिए 2003 में चुने गए। बिहार कैडर मिला और पहली पोस्टिंग सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट के तौर पर वेस्ट चंपारण फिर हिलसा में हुई । कार्यकाल छोटा पर बेहद प्रभावशाली रहा । 2008 में नालंदा और फिर 2009 में रोहतास के जिलाधिकारी की जिम्मेदारी मिली। करीब साढ़े तीन वर्ष ये रोहतास के जिलाधिकारी रहे और इस दरम्यान अपनी कुशल नीतियों से रोहतास को बहुत हद तक नक्सल की समस्या से निजात दिलाने में सफल रहे हैं। जमीन के वितरण, विकास कार्यों तथा खेलकूद को बढ़ावा देना आदि के माध्यम से इन्होंने युवाओं का ध्यान संरचनात्मक कार्य में लगाया। इन्हें 2013 में मुजफ्फरपुर जिलाधिकारी बनाया गया, अनुपम ने शानदार गवर्नेंस और कार्य कुशलता से आम जनता से जुड़े और विकास के कई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए.मुजफ्फरपुर में इनके कार्यकाल के दौरान कांटी थर्मल पावर प्लांट हेतु अनेक बाधाओं को दूर किया तथा दो यूनिट्स को पुनः चालू कराने हेतु सभी आवश्यक सहयोग प्रदान किए गए।इनका यह कार्यकाल पांच सालों का रहा। मृदुभाषी एवं मिलनसार अनुपम कुमार की पोस्टिंग जहां भी रही है, वहां के जनमानस पर इन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ी है।

जिले में आमजनों से प्रतिदिन सुव्यवस्थित रुप से बड़ी सरलता से मिलते हैं।

ये बिहार में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक और ट्रांस्पोर्ट कमिश्नर के पद पर भी रहे हैं। परिवहन विभाग को इ-प्लेटफार्म पर लाने, प्रदूषण रहित इलेक्ट्रनिक वाहनों को बढ़ावा देने तथा पूर्ण पारदर्शी तरीके से परमिट देने हेतु इन्होंने काफी कार्य किया।

वर्त्तमान में अनुपम मुख्यमंत्री सचिवालय में सचिव के साथ ही राज्य के जनसंपर्क विभाग के सचिव भी है .इन्हें संवाद समिति के प्रबंध निदेशक के साथ ही नालंदा का प्रभारी सचिव भी बनाया गया है ।

हर पद पर अपनी जवाबदेह बेहद कुशलतापूर्वक और दूरदर्शिता के साथ निभा रहे अनुपम कुमार राज्य के मुख्यमंत्री के विश्वस्त ब्यूरोक्रेट में शामिल हैं।

अन्य प्रमुख नामः

रजत अग्रवाल
जयश्री एस भोज
अंकुर गर्ग
अमित सिंघल
डॉ पी सी जफर

(इस श्रेणी के सभी प्रमुख ब्यूरोक्रेट्स की पूरी प्रोफाइल fameindia.co पर पब्लिश की जा रही है।)

फेम इंडिया मैगजीन- एशिया पोस्ट के प्रमुख मापदंडः

- दूरदर्शिता - ✓
- उत्कृष्ट सोच - ✓
- जवाबदेह - ✓
- गंभीरता - ✓
- शानदार गवर्नेंस - ✓
- व्यवहार कुशलता - ✓
- फैसला लेने की क्षमता - ✓

इन सात मुख्य बिंदुओं पर किये गये वार्षिक सर्वे 'असरदार ब्यूरोक्रेट्स -2019' में अनुपम कुमार प्रमुख स्थान पर हैं।

सर्वे स्रोत :- विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की राय पर आधारित

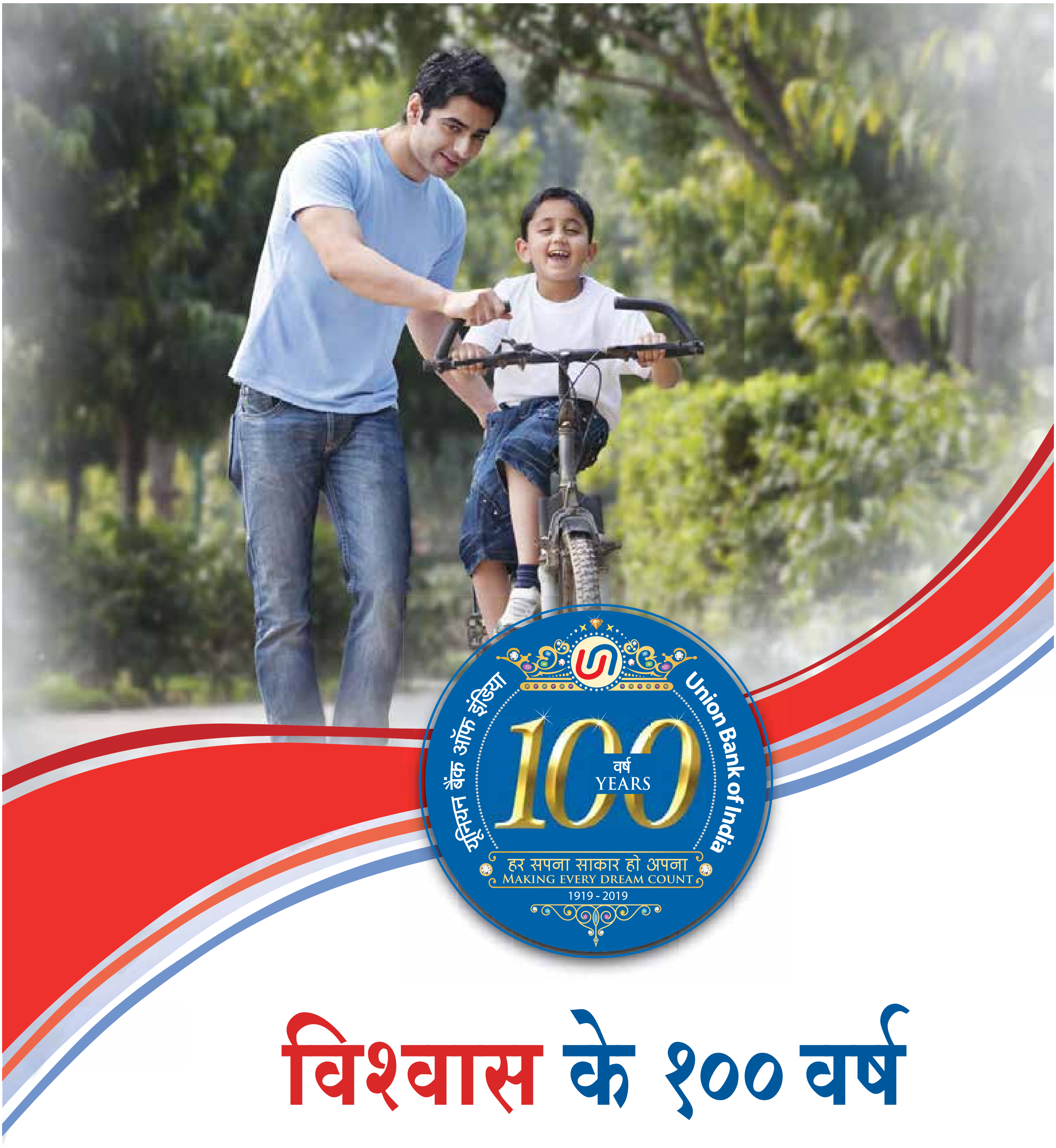

विश्वास के १०० वर्ष

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया **Union Bank of India**

अच्छे लोग, अच्छा बैंक — Good people to bank with

भारतीय बैंकिंग कोड एवं मानक बोर्ड के सदस्य — Member of Banking Codes & Standards Board of India

Proud to be associated with

Helpline Nos.: 1800 208 2244 / 1800 22 2244 (Toll free no.) **080 2530 0175** (Chargeable)
+91 80 2530 2510 (for NRIs) | **www.unionbankofindia.co.in**

Connect with us: **@unionbankofindia** **@UnionBankTweets**
@UnionBankInsta YouTube **UnionBankofIndiaUtube** **Unionbankofindia**

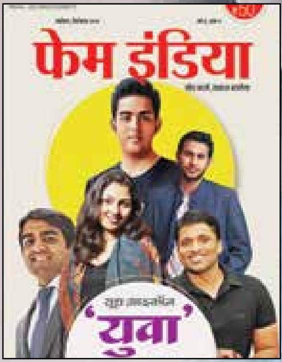

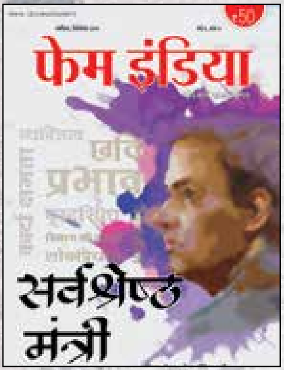

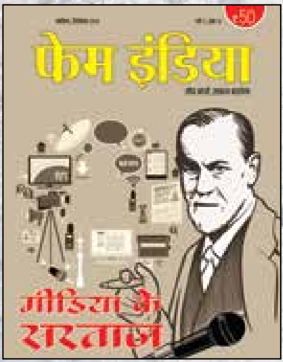

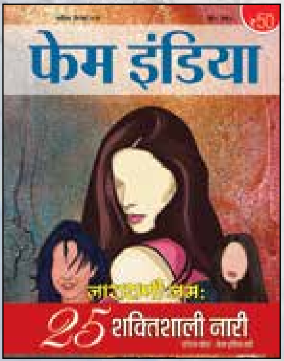

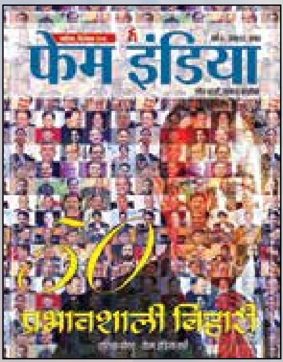

फेम इंडिया के बढ़ते कदम ...
सफलता के 8 वर्ष ....

सोच बदलें, समाज बदलेगा

सदस्यता फार्म

मैं फेम इंडिया की सदस्यता ले रहा / रही हूं

श्रीमती/ कुमारी/ श्री ....

पता: ....

.... राज्य ....

फोन (निवास) .... मोबाइल ....

ई-मेल ....

कृपया .... के नाम .... का डी डी

या चेक नं. ....

बैंक का नाम ....

चैक फेम इंडिया के नाम पर देय होगा

दिल्ली के बाहर से भेजे गए चेक में कृपया 30 रूपया अधिक भेजें

कृपया इस फार्म को भरकर डी डी या चेक के साथ हमें इस पते पर भेजें

फेम इंडिया

फेम इंडिया पब्लिकेशन प्रा.लि. 762, F-8, सेक्टर 50, नोएडा 201304 (उ.प्र.)

फोन नं. 09711535422

ई मेल-ई मेल- info.fameindia.co

अवधि	अंको की संख्या	कवर मूल्य	सब्सक्रिप्शन मूल्य	बचत
1 वर्ष	12	600	500	100
2 वर्ष	24	1200	1000	200
3 वर्ष	36	1800	1500	300

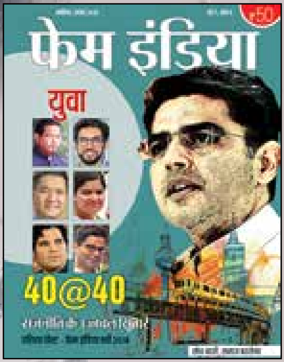

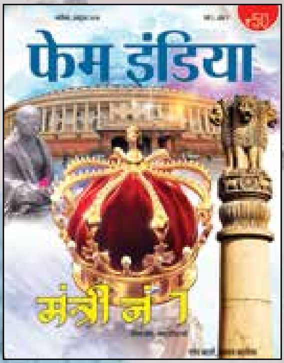

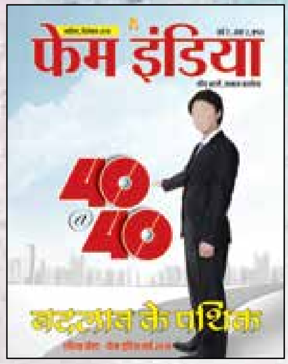

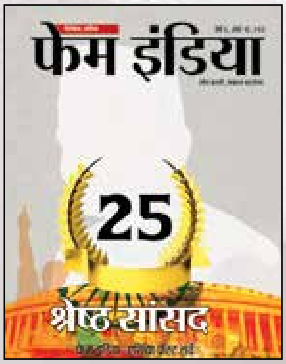

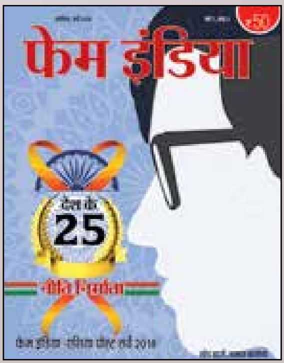

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
(मिनिरत्न श्रेणी–1 सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम)

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

अत्याधुनिक तकनीक एवं अंतरराष्ट्रीय मापदंड के साथ भा.वि.प्रा. का सुरक्षित हाथ

23	+	**10**	+	**80**	+	**23**	=	**136**
अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (3 सिविल एन्कलेव तथा 3 संयुक्त उद्यम हवाई अड्डे)		कस्टम हवाई अड्डे (4 सिविल एन्कलेव)		अन्तर्देशीय हवाई अड्डे		अन्य सिविल एन्कलेव		हवाई अड्डे

निगमित मुख्यालय : राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली–110 003
दूरभाष +91 11 24632950 फैक्स : +91 11 24632990
वेबसाइट : http://www.aai.aero & http://www.airportsindia.org.in @AAI_Official

THE FRONT
जो बोलेगा, वो बदलेगा
देश के बड़े पत्रकारों / विशेषज्ञों का मोर्चा
देश का प्रश्न
पक्षपात और विरोध से मुक्त, ख़बरों का बुलेटिन, सोमवार से शुक्रवार, रात 8 बजे
साधो जग बौराना
महत्वपूर्ण मुद्दों पर जाने माने पत्रकार एन के सिंह की बेबाक राय
राहुल की राय
प्रतिष्ठित पत्रकार राहुल देव की छोटी - छोटी बातों की बड़ी परख
बात बोलेगी
अरविंद मोहन
वरिष्ठ पत्रकार
देश के महत्वपूर्ण लोगों और घटनाओं की दिलचस्प क़िस्सागोई
@thefrontindia
@thefrontindia
@thefrontindia
@thefrontindia
info@thefront.in
www.thefront.in
हमें पसंद करें, Subscribe करें और सहयोग दें

क्या आप अपने बिज़नेस को ज़्यादा फ़ायदेमंद बनाना चाहते हैं?

अपनी फ़ैक्टरी में एनर्जी ऑडिट कराएं।

एनर्जी ऑडिट से सालाना ईंधन और एनर्जी के बिल में 20%* तक की बचत हो सकती है।

एनर्जी ऑडिट आपकी फ़ैक्टरी में एनर्जी पर चलनेवाले कई उपकरणों जैसे कि फ़र्नेसेस, बॉयलर्स, DG सेट्स, मोटर्स और डिस्ट्रिब्यूशन नेटवर्क, एयर कम्प्रेशर्स और रेफ़्रिजरेशन्स और इल्यूमिनेशन टावर्स से होनेवाली एनर्जी की फ़िज़ूलखर्ची को पहचानता है। इससे आपकी एनर्जी के बिल में 20%* तक की बचत हो सकती है।

एनर्जी बचाने के कुछ और आसान तरीके:

1. फ़िज़ूल जा रही ऊर्जा का बेहतर उपयोग करें।
2. DG सेट्स द्वारा ईंधन की ख़ास खपत को नियमितरूप से मापें।
3. पुराने और कम कार्यकुशल उपकरणों को नए ज़माने के उच्च कार्यकुशल उपकरणों से बदलें।

अधिक जानकारी के लिए विज़िट करें www.pcra.org या कॉल करें 011-26198809

बचाएं ईंधन
धन
पर्यावरण

*बचत सिर्फ़ सूचनात्मक है। वास्तविक बचत सुझावों के वास्तविक इस्तेमाल और अन्य मापदंडों पर निर्भर करेगी।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
भारत सरकार

पीसीआरए

पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ
संरक्षण भवन, 10, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066
फोन :+91-11-26198856 ई-मेल : pcra@pcra.org Website : www.pcra.org

1041.2013

आवश्यक है राष्ट्र-सेवकों का प्रोत्साहन

देश में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को प्रोत्साहित करने के लिए सिविल सर्विस डे मनाने का प्रचलन है । जब भी कोई भी अवसर आपके प्रोत्साहन का आता है वह प्रशंसा के साथ मूल्यांकन और आत्मनिरीक्षण के लिए प्रेरित भी करता है। यह एक कदम है जो आपकी सकारात्मक सोच को बढ़ाने के साथ आपकी राष्ट्र के प्रति निष्ठा और जिम्मेदारी का एहसास करवाता है । सरकार की प्राथमिकताओं में प्रधान मंत्री आवास बीमा योजना, दीनदयाल उपाध्याय कौशल्या योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और डिजिटल भुगतान जैसे प्राथमिकता कार्यक्रम बेहद महत्त्वपूर्ण है , तभी न्यू इंडिया बनेगा । एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में हर वर्ष चुने जाने वाले 115 जिले अपने पूरे राज्यों के लिए आदर्श के तौर पर विकास इंजन बन सकते हैं। विकास में जनभागीदारी, या जनभागीदारी के महत्व को भी समझने की जरूरत है । वर्ष 2022 आजादी की सत्तरवीं वर्षगांठ का वर्ष है और इसे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों के भारत को प्राप्त करने की दिशा में काम करने की प्रेरणा बनाया जाना चाहिए । शासन में सुधार के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी सहित सभी उपलब्ध प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए। ब्यूरोक्रेटस के लिए दुनिया भर में उभरती प्रौद्योगिकियों के साथ तालमेल रखना महत्त्वपूर्ण है। आईएएस अधिकारी महान क्षमता वाले लोग बनते हैं और ये क्षमताएं राष्ट्र के लाभ के लिए बड़े पैमाने पर योगदान कर सकती हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

IFFCO

पूर्णतः सहकारी स्वामित्व

Wholly owned by Cooperatives

पानी में घुलनशील व विशेष उर्वरक

उत्तम खाद, उचित दाम

Follow us :

IFFCO live

iffcolive.com

FORTUNE 500

Vietnam Airlines
LOTUSMILES
Telecomunication
Shopping - Beauty Care
Fly with Vietnam Airlines
and airline partners
Banking - Insurance
Travel - Leisure
It'S miles life
Enjoy your beautiful life with many opportunities via accumulating miles so as to upgrade your Lotusmiles membership tier and receive more exciting rewards
LOTUSMILES PLATINUM
• Fly with Vietnam Airlines and other airline partners;
• Use services from our banking partners and get benefit from their privileges;
• Use services by our telecom partners;
• Protect your life with our insurance partners;
• Enjoy your shopping, beauty care and travel from our high-ranking partners.
For more detail, please contact Vietnam Airlines booking office or visit www.vietnamairlines.com
4 STAR AIRLINE
SKYTRAX
1900 1800
vietnamairlines
www.vietnamairlines.com